www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 01 जुलाई-07 जुलाई 2013 | मूल्य 5 रुपये

एच सी गुप्ता ने इस्तीफ़ा दिया, प्रधानमंत्री कब देंगे?

पेज : 3

कठिन डगर पर नीतीश

पेज : 5

विरोधियों की साज़िश में घिरे राहुल

पेज : 7

साई की महिमा

पेज : 12

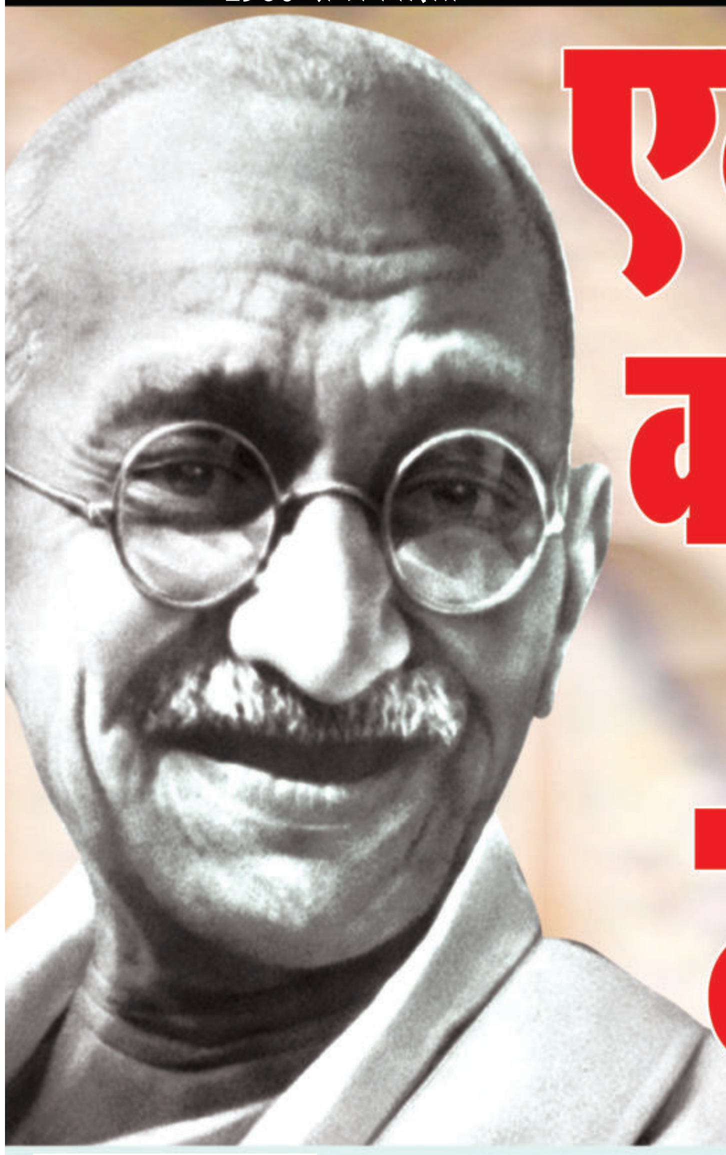

एक बार फिर कांग्रेस ने गांधी को मारा

फोटो-प्रभात पाण्डेय

बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो बदलते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो कभी सुधरते नहीं हैं. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादों से जुड़ी वस्तुओं की फिर से नीलामी हुई. फिर से भारत की ऐतिहासिक धरोहरों पर बोली लगी, लेकिन भारत की सरकार फिर से सोती रह गई. यह नहीं सुधरी. हालांकि फिर से एक भारतीय ने भारत की लाज बचाई. एक बार फिर उसी भारतीय ने महात्मा गांधी की यादों से जुड़ी वस्तुएं खरीदीं और पिछली बार की तरह इस बार भी अपना नाम मीडिया से छुपा लिया. अजीब इत्तेफाक है, सरकार सुधरती नहीं है और कमल मोरारका का अंदाज बदलता नहीं है.

मनीष कुमार

लंदन में एक बार फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादों की नीलामी हुई और देश का दुर्भाग्य देखिए, भारत सरकार सोती रह गई. एक बार फिर से उसी भारतीय ने देश की लाज बचाई, जिसने पिछली बार गांधी की यादों को विदेशी हाथों में जाने से रोका था और गांधी के खून से सनी मिट्टी भारत लेकर आया था. तारीफ इस बात की होनी चाहिए कि यह शख्स इसे कोई मीडिया में प्रचार का जरिया नहीं बनाता और अपना नाम गुप्त रखता है. वैसे, पहले भी कुछ भारतीयों ने ऐतिहासिक धरोहरें नीलामी में खरीदीं, लेकिन उन्होंने उनका इतना प्रचार किया कि ऐतिहासिक धरोहर को जैसे बेचने की वस्तु में तब्दील कर दिया हो.

सबसे पहले आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादों से जुड़ी नीलामी के बारे में बताते हैं. यह नीलामी ब्रिटेन के एक बड़े ऑक्शन हाउस मुलॉक्स ने 21 मई, 2013 को की. इसमें बापू की रामायण, चमड़े की चप्पल, लालटेन, माला, काठ की प्रतिमा, पेंटिंग, टोपी, तार, ऑडियो टेप आदि कई चीजों पर बोलियां लगाई गईं. इस नीलामी की जानकारी भारत सरकार को भी थी, लेकिन इस नीलामी में भारत सरकार की तरफ़ से न तो कोई बोली लगाने वाला था और न ही उसकी ओर से बापू से जुड़ी इन यादों को अपने देश में वापस लाने के लिए कोई कोशिश की गई. अफ़सोस इस बात का है कि गांधी की यादों की नीलामी का यह कोई पहला मौक़ा नहीं था, क्योंकि पहले भी सरकार की किरकिरी हो चुकी है. टीवी एवं अख़बारों के जरिए सरकार से गुजारिश की गई कि देश की प्रतिष्ठा को नीलाम होने से रोका जाए.

लेकिन कहते हैं कि सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जागते हुए को भला कौन जगा सकता है. मतलब यह कि कांग्रेस की सरकार ने अपनी करतूतों से साबित कर दिया है कि उसे न तो महात्मा गांधी की यादों से कोई लगाव है और न ही देश की प्रतिष्ठा

इस नीलामी के दौरान गांधी के खून का सैंपल भी नीलाम हो गया. बापू का यह ब्लड सैंपल 1924 का है. उस वक्त उनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था. ऑपरेशन के बाद वह मुंबई में रुककर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे. बताया जाता है कि उन्होंने यह ब्लड सैंपल उस परिवार को दिया था, जिसके घर में वह मुंबई में रुके थे. नीलामी करने वाली एजेंसी ने इसकी क़ीमत 10000 पाउंड रखी थी, लेकिन किसी ने इससे बढ़कर बोली नहीं लगाई.

की फिक्र है.

जब सरकार को देश की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रहता है, तो यह ज़िम्मेदारी देश के नागरिकों की हो जाती है. यही काम कमल मोरारका ने किया. जब यह ख़बर आई कि 21 मई, 2013 को बापू से जुड़ी क़रीब 16 वस्तुओं की नीलामी होने जा रही है, तो उन्होंने सरकार की प्रतिक्रिया का इंतज़ार किया. लेकिन जो गलती सरकार ने पिछली बार की थी, वही गलती उसने फिर से दोहरा दी. सरकार की ओर से कोई बयान तक नहीं आया. ऐसे में फिर से कमल मोरारका ने बापू की धरोहर देश में वापस लाने की ठानी और इन 16 वस्तुओं को नीलामी में खरीद लिया. कमल मोरारका की यह पहल पहली नहीं है.

पिछले साल भी कमल मोरारका बापू से जुड़ी यादों को देश में वापस ले आए थे. लंदन के विख्यात ऑक्शन हाउस मुलॉक्स (जो कि स्मृति चिन्हों की नीलामी के लिए मशहूर है) ने 17 अप्रैल, 2012 को महात्मा गांधी से जुड़ी 29 वस्तुओं की नीलामी की थी, जिनमें मुख्य रूप से गांधी जी के खून से सनी घास एवं मिट्टी, ब्रिटेन में वकालत की पढ़ाई करते समय इस्तेमाल किया जाने वाला चश्मा, उनका चरखा, उनके लिखे कुछ पत्र और उनसे जुड़ी ख़बरों के प्रकाशन वाले अख़बारों की वास्तविक प्रतियां शामिल थीं. इन सभी वस्तुओं को कमल मोरारका ने खरीद कर देश की धरोहर देश में लाने और गांधी की यादों को बचाने का काम किया. इसके बाद उन्होंने यह घोषणा की थी कि इन्हें

वह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए नहीं रखेंगे, बल्कि ये देश की धरोहर होंगी. पिछली बार जब बापू की निशानियों को भारत लाया गया, तो कमल मोरारका ने उन्हें अन्ना हज़ारे के सुपुर्द कर दिया. पटना में जब अन्ना हज़ारे ने जनतंत्र रैली की, तो उन्हें पहली बार लोगों के सामने रखा गया. गांधी देश की धरोहर हैं. उनके विचार बहुमूल्य हैं. गांधी के नाम से योजनाएं चला देने भर से राष्ट्रपिता के प्रति सरकार का दायित्व ख़त्म नहीं हो जाता है! असल में गांधी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाना सरकार का ही दायित्व है. सरकार को जो करना चाहिए, वह तो करती नहीं, लेकिन उसके अलावा, वह सारा काम करती है. जो काम सरकार को करना चाहिए, वह काम कमल मोरारका कर रहे हैं. इस बार फिर से उन्होंने बापू की धरोहर देश में लाकर यह साबित किया कि गांधी को भले ही इस देश के राजनीतिक दल भुला दें, लेकिन एक भारतीय के दिल में गांधी हमेशा से थे और आगे भी रहेंगे.

देश की जनता तो कमल मोरारका के जज्बे को सलाम करती है, लेकिन सरकार ने क्या किया? एक बार अगर नीलामी होती, तो यह कहा भी जा सकता था कि सरकार

(शेष पृष्ठ 2 पर)

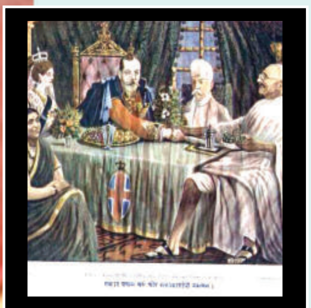
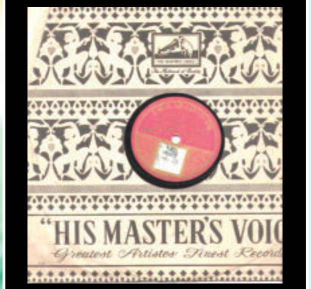

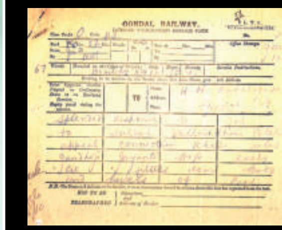

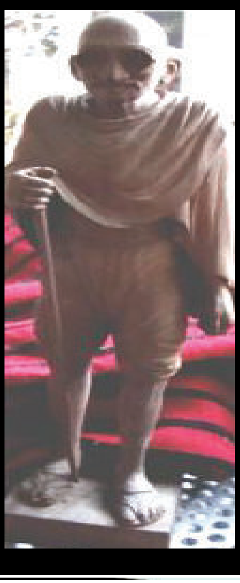

तबादलों को लेकर जब बात राज्यों की आती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में दो क़दम आगे निकल जाती है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

यह कैसी नीति?

पिछले साल हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका सुर्ख़ियों में थे. हरियाणा सरकार ने 20 वर्षों में अशोक खेमका का 42 बार तबादला किया. इसके बाद से नागरिक सेवाओं में जल्द होने वाले तबादलों को खेमका सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है. अशोक खेमका का तबादला बड़े एवं ताकतवर लोगों के विवादित भूमि सौदे को चुनौती देने की वजह से किया गया था. तबादलों को लेकर जब बात राज्यों की आती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में दो क़दम आगे निकल जाती है. पिछले साल समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के बाद अखिलेश सरकार ने एक साल के भीतर ही 2000 तबादले कर डाले. आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्होंने थोक के भाव किए गए इन तबादलों की खातिर 15 मई वाली तबादला नीति को भी नज़रअंदाज कर दिया. अखिलेश ने सारे नियम ताख पर रखकर एक साथ 16 बाबुओं का तबादला कर दिया. सूत्रों का कहना है कि उक्त तबादले उन 4 अधिकारियों को फिर से वापस लाने के लिए किए गए, जो मुख्यमंत्री के खास बताए जाते हैं. अखिलेश सरकार के इस निर्णय से पता चलता है कि राज्य में तबादलों से संबंधित नियम सिर्फ़ कागजों पर हैं, लागू करने के लिए बिल्कुल नहीं. ■

उड़ीसा के रसूखदार बाबू

उड़ीसा के मुख्य सचिव बी के पटनायक की सेवानिवृत्ति के बाद पांच वरिष्ठ नौकरशाहों के नाम इस पद के लिए चर्चा में हैं. हालांकि सूत्रों के अनुसार, जुगल किशोर मोहपात्र का नाम सबसे आगे है, जो वर्तमान में वित्त

एवं योजना विभाग में सचिव हैं. बताया जाता है कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की नज़र में मोहपात्र की छवि अन्य वरिष्ठों की तुलना में अच्छी है. मोहपात्र लंबे समय से पटनायक से संबद्ध रहे हैं. वह चार वर्षों तक पटनायक के प्रधान सचिव भी रहे हैं. दूसरी तरफ़ मोहपात्र से वरिष्ठ एवं योग्य अधिकारी जी सी पटी, नीलांजन सान्याल और हृषिकेश पंडा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनके गृहराज्य में लौटने के कोई संकेत भी नहीं हैं. वहीं अन्य दो बाबू जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इसलिए मोहपात्र का रास्ता पूरी तरह साफ़ हो गया है. ■

पारिकर की परेशानी

गोवा में इन दिनों स्थितियां काफी विपरीत हैं. मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर सरकार का राज्य के एक वरिष्ठ नौकरशाह से सार्वजनिक तौर पर मतभेद सामने आया है. लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने नंदन सिंह को दिल्ली में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में उपसचिव पद के लिए अनुशंसित किया था. अब उसी अधिकारी ने अन्य राज्यों की गाड़ियों को गोवा में नि:शुल्क प्रवेश देने का राज्य सरकार का फ़ैसला अवैध करार दिया है. उन्होंने कथित तौर पर राज्य सरकार से इस बात की मांग की है कि वह यह नियम हटाए. सूत्रों का कहना है कि गोवा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से उक्त अधिकारी की शिकायत करने का फ़ैसला किया है. हालांकि पारिकर सरकार को प्रधानमंत्री से जब भी जवाब मिले, लेकिन राज्यों के लिए यह अपनी तरह का पहला मामला नहीं है. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

प्रदीप ऊर्जा मंत्रालय जाएंगे

1987 बैच एवं केरल कैडर के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार को ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया जाएगा.

पंकज विदेश मंत्रालय गए

1999 बैच के आईटीएस अधिकारी पंकज गोयल को विदेश मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है. उन्होंने 1991 बैच के आईडीएएस अधिकारी देव कुमार का स्थान लिया.

संजय जेएस बनेंगे

1994 बैच एवं अंडमान कैडर के आईएएस अधिकारी संजय लोहिया को कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया जाएगा. वह 1985 बैच एवं हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संजीव गुप्ता का स्थान लेंगे, जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है.

संजीव रक्षा निदेशक बने

1989 बैच के आईओएफएस अधिकारी संजीव कुमार डोगरा को रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है. वह 1993 बैच की आईएफएस अधिकारी उमा नंदुरी का स्थान लेंगे, जिन्हें एनपीसीसी में सीवीओ बनाकर भेजा गया है.

रॉय होंगे एलआईसी चीफ

एस के रॉय का एलआईसी चीफ बनना अब लगभग तय माना जा रहा है. हालांकि पहले उनकी इस पद पर नियुक्ति को लेकर कुछ तकनीकी परेशानियां थीं, जिन्हें दूर कर लिया गया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

एक बार फिर कांग्रेस ने गांधी को मारा

बापू से जुड़ी 16 वस्तुएं, जो अब लंदन से भारत आएंगी

1. एक जोड़ी चमड़े की चप्पल.
2. गांधी जी की पूजा वाली माला.
3. लाइनेन की टोपी
4. 5 इंच का धातु का पानी पीने का ग्लास.
5. लालटेन.
6. थर्मस.
7. गांधी जी की रामायण.
8. पोस्टेज स्टांप.
9. गांधी जी की काठ की प्रतिमा.
10. तार.
11. कोलंबिया डिस्क, जिसमें गांधी जी का संदेश है.
12. एचएमवी डिस्क, जिसमें गांधी जी का संदेश है.
13. हिंदुस्तान रिकॉर्ड की डिस्क.
14. नेहरू जी की रिकॉर्डिंग वाली एचएमवी की डिस्क.
15. गांधी जी का पोस्टर.
16. श्याम सुंदर लाल द्वारा बनाया गया गांधी जी का इलस्ट्रेशन.

पृष्ठ एक का शेष

से गलती हो गई, लेकिन यहां तो हर साल नीलामी हो रही है और सरकार मूकदर्शक बनी बैठी है. क्या भारत सरकार इतनी असहाय एवं कमजोर है या फिर सरकार चलाने वाले लोगों ने गांधी को भुला देने की कसम खा ली है? सवाल तो यह भी उठता है कि क्या अमेरिका के किसी नेता की यादों की नीलामी हुई है या फिर ब्रिटेन की रानी या राजा की यादों पर बोली लगाई जा सकती है? नहीं, क्योंकि या तो नीलामी रोक दी जाती है या फिर वहां की सरकार सारी यादों को खरीद लेती है, लेकिन भारत सरकार अजीब है. कुछ-कुछ समय के अंतराल में यह ख़बर आ जाती है कि गांधी की यादों की नीलामी हो रही है. सरकार को लोगों की भावनाओं की भी कद्र नहीं रही. क्या उसे पता नहीं है कि महात्मा गांधी की यादों की नीलामी होते देखकर किसी भी हिंदुस्तानी का खून खौल उठता है? दरअसल, नीलामी कराने वाली कंपनियों ने गांधी की यादों को एक कमोडिटी बना दिया है. क्या भारत सरकार उन्हें रोकने में असमर्थ है या फिर उसे गांधी की फिक्र ही नहीं रही? वैसे, दोनों ही अवस्थाएं निंदनीय हैं. गांधी की यादें एक के बाद, एक करके नीलाम हो रही हैं, पर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं. सवाल यह है कि क्या गांधी की यादों की नीलामी रुक पाएगी? नहीं. ऐसा इसलिए, क्योंकि जिन लोगों ने पहले या हाल में गांधी की यादों को खरीदा है, वे उन सामानों को फिर से बेच देंगे और फिर से उन्हीं सामानों की नीलामी होगी, मुनाफा कमाया जाएगा. यह सिलसिला शायद कभी नहीं रुकने वाला है.

पिछली बार जब नीलामी हुई, तब अख़बारों में यह ख़बर छपी कि सोनिया गांधी मनमोहन सिंह से इस बात से बहुत नाराज़ हैं कि इन चीज़ों की नीलामी रोकने और अपने देश में वापस लाने के लिए उन्होंने कोई क़दम नहीं उठाया. लगता है कि कांग्रेस पार्टी की यह आदत हो गई है या फिर यह एक रणनीति है कि सरकार की हर गलती के बाद मीडिया के जरिए यह ख़बर फैला देना कि सोनिया जी नाराज हैं या राहुल जी दु:खी हैं. देश की जनता अब मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली ऐसी ख़बरों पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी को गांधी का जरा भी

ख्याल होता, तो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को निर्देश देतीं और इस तरह लगातार हो रही गांधी की यादों की नीलामी रोकी जा सकती थी. दुर्भाग्य तो यह है कि ऐसे मामलों में देश का विपक्ष भी खामोश रहता है. दरअसल, देश के राजनीतिक दलों ने सत्ता हासिल करने की दौड़ में फंसकर सारे वैचारिक एवं राजनीतिक मापदंडों को तिलांजलि दे दी है. उन्होंने न सिर्फ़ गांधी को भुला दिया, बल्कि उनके विचारों को भी ताख पर रख दिया है. यही वजह है, राजनीति में झूठ और हिंसा का बोलबाला है. ऐसे माहौल में बापू के बारे में सोचने का वक्त भी किसी के पास नहीं है और यही देश का दुर्भाग्य भी है. लेकिन जहां निराशा होती है, वहीं आशा के कमल भी खिलते हैं. कमल मोरारका जैसे व्यक्तित्व का देश में होना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है. पिछली बार जब उन्होंने बापू की यादों को खरीदा था, तो यह सुनकर कि उक्त सभी चीज़ें किसी भारतीय ने खरीदी हैं, हर किसी का सीना चौड़ा और सिर गर्व से ऊंचा हो गया था. कमल मोरारका देश के जाने-माने पूंजीपति हैं, लेकिन पूंजीपति से ज़्यादा वह एक देशभक्त और अच्छे इंसान हैं. देश के बड़े पैसे वालों को कमल मोरारका से यह सीखना चाहिए कि देश के प्रति पागलपन की हद तक लगाव कैसे रखा जाता है और देश की आन-बान-शान को कैसे जिया जाता है.

अफ़सोस इस बात का है कि इस नीलामी के दौरान गांधी के खून का सैंपल भी नीलाम हो गया. बापू का यह ब्लड सैंपल 1924 का है. उस वक्त उनके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था. ऑपरेशन के बाद वह मुंबई में रुककर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे. बताया जाता है कि उन्होंने यह ब्लड सैंपल उस परिवार को दिया था, जिसके घर में वह मुंबई में रुके थे. नीलामी करने वाली एजेंसी ने इसकी क़ीमत 10000 पाउंड रखी थी, लेकिन किसी ने इससे बढ़कर बोली नहीं लगाई, इसलिए यह ब्लड सैंपल 7000 पाउंड में नीलाम हुआ. इसे किसने लिया, यानी ब्लड सैंपल किसके पास है, यह सार्वजनिक नहीं किया गया है. अब सवाल है कि अगर यह ब्लड सैंपल किसी क्लोनिंग लेबोरेटरी के हाथ लग जाए और वह गांधी जी की क्लोनिंग शुरू कर दे, तो क्या होगा? अब यह तो कोई साइंटिस्ट ही बता सकता है कि इस ब्लड सैंपल से डीएनए निकाल कर क्या-क्या किया जा सकता है, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है. सरकार को तुरंत इस बात का पता लगाना चाहिए कि यह ब्लड सैंपल किसके पास है, क्योंकि इसके किसी भी गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की ज़रूरत है.

भारत सरकार अजीब है. यह योजनाएं तो गांधी के नाम पर बनाती है, लेकिन उनसे जुड़ी यादों को नीलाम होने देती है. संवेदनहीनता का आलम यह है कि हर नीलामी की जानकारी भी सरकार को होती है. हर बार मीडिया में हंगामा मचता है और गांधी के वंशज भी आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती. पिछली बार जब गांधी की वस्तुओं की नीलामी हुई थी, तब देश के गांधीवादी संगठन बिलबिला उठा थे और उन्होंने काफी विरोध किया था. प्रधानमंत्री कार्यालय से अपील की गई, अख़बारों में इस पर कई लेख प्रकाशित हुए और टीवी पर बहस भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. सरकार कुंभकर्ण की भांति सोती रही और नीलामी का इतना प्रचार हो गया कि गांधी की यादों की क़ीमतें और भी बढ़ गईं. अगर सरकार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति कोई श्रद्धा है, तो उसे कुछ कड़े क़दम उठाने पड़ेंगे. इन नीलामियों को रोकने का एक तरीका ढूंढना ही होगा. संसद में फौरन एक क़ानून पास करके यह घोषणा करनी चाहिए कि गांधी की यादों से जुड़ी सारी वस्तुएं राष्ट्रीय संपत्ति हैं. वैसे भी, भारत की ऐतिहासिक विरासत पर पहला हक भारतीयों का है, इसलिए उन्हें सरकार के पास होना ही चाहिए, देश के संग्रहालयों में भी होना चाहिए. उन्हें विदेशी एवं निजी हाथों में जाने से रोकने के उपाय सरकार को करने चाहिए, वरना हम पूरी दुनिया में हंसी के पात्र बन जाएंगे, क्योंकि हर खरीदार कमल मोरारका नहीं होता! ■

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 17
दिल्ली, 01 जुलाई–07 जुलाई 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय	0120–6451999
	6450888
	6452888
	011–23418962
विज्ञापन व प्रसार	+91–9266627379
फैक्स न.	0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि तेल की चोरी और कालाबाज़ारी की वजह से हर साल 70,000 करोड़ रुपये का नुक़सान होता है, उसे ख़त्म करने के लिए उसने क्या किया?

कोयला घोटाला

एच सी गुप्ता ने इस्तीफ़ा दिया प्रधानमंत्री कब देंगे?

चौथी दुनिया ने अपने पिछले अंक में बताया था कि किस तरह से यूपीए सरकार सीबीआई जांच प्रभावित करने का प्रयास कर रही है. पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बचाने की कोशिश की गई और अब पीएमओ के अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है. दूसरी ओर, पूर्व कोयला सचिव, जिन्होंने कोयला ब्लॉकों के अवैध आवंटन के विरुद्ध पीएमओ को पत्र लिखकर निरंतर अवगत कराया, अब उन्हीं के विरुद्ध आरोप तय करने की कोशिश की जा रही है.

डॉ. क़मर तबरेज़
feedback@chauthiduniya.com

वर्ष 2006 से 2009 के बीच कोयला सचिव रहे एच सी गुप्ता ने बीते 12 जून को अपने वर्तमान पद, यानी कंप्टीशन कमीशन ऑफ इंडिया की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया. दरअसल, सीबीआई ने यूपीए सरकार से कोयला घोटाले के बारे में एच सी गुप्ता से पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी. शुरू में तो सरकार ने अनुमति देने से इंकार कर दिया था, जिससे ऐसा लगा था कि शायद एच सी गुप्ता के पास ऐसा कोई न कोई राज़ ज़रूर है, जिससे अगर वह पर्दा उठा देंगे, तो मनमोहन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस समय कोयला घोटाला हुआ था, उस समय वह स्वयं कोयला मंत्रालय देख रहे थे, लेकिन अब, जबकि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, जिसके तहत कंप्टीशन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है, ने सीबीआई को एच सी गुप्ता से पूछताछ की अनुमति दे दी है, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. इसके बाद बीते 20 जून को वह सीबीआई के सामने हाजिर हुए. उन्होंने ऐसा इसलिए किया, ताकि सीबीआई की जांच में किसी प्रकार की रुकावट पैदा न हो. इससे उनकी ईमानदारी का पता चलता है. 20 जून को सीबीआई ने एचसी गुप्ता से गवाह के रूप में नहीं, बल्कि आरोपी के रूप अपने सामने हाजिर होने के लिए कहकर उनसे पांच घंटे तक पूछताछ की. हैरानी की बात तो यह है कि इतनी लंबी पूछताछ के दौरान सीबीआई ने एचसी गुप्ता से कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री के कार्यालय की भूमिका से संबंधित एक भी सवाल नहीं पूछा, बल्कि उनसे केवल अपनी ओर से दर्ज कराई गई पहली पांच एफआईआर से संबंधित सवाल ही पूछे. दरअसल, सीबीआई की प्रथम पांच एफआईआर उन पांच कंपनियों के विरुद्ध हैं, जिन्हें कोयला ब्लॉक नियमों का उल्लंघन करते हुए आवंटित किये गये. इन कंपनियों के नाम हैं, एएमआर आयरन एंड स्टील, जेएलडी येवतमाल एनर्जी लि., नवभारत पॉवर, विन्नी आयरन एंड स्टील और जेएएस इंफ्रास्ट्रक्चर.

दूसरी ओर मनमोहन सिंह हैं, जो अब भी अपने पद पर बने हुए हैं और कांग्रेस पार्टी बेशर्मी की तमाम सीमाओं को लांघने में लगी है. इस मामले की पारदर्शी एवं निष्पक्ष जांच के लिए यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफ़ा दें. हालांकि अब आगामी लोकसभा चुनाव को ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और इसीलिए ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी नवीन जिंदल समेत अपने मंत्रियों के नाम कोयला घोटाले में आने के बाद भी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं करेगी और चुनाव तक इस मामले को यूं ही टालती रहेगी. हैरानी की बात तो यह है कि सीबीआई ने पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायणराव के साथ एच सी गुप्ता पर भी आरोप लगाने की तैयारी शुरू कर दी है. हालांकि यह बात अब सबको मालूम है कि जिन दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से गठित स्क्रीनिंग कमेटी बिना किसी नीलामी के कोयला ब्लॉकों का आवंटन कर रही थी, उस समय कोयला सचिव एच सी गुप्ता ने ही पीएमओ को लिखे गए अपने कई पत्रों में यह बताया था कि सरकार की ओर से न केवल नियम-क़ानूनों का उल्लंघन, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नज़रअंदाज़ किया जा रहा है. उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार को एक-दो बार नहीं, बल्कि कई बार यह मशविरा दिया था कि कोयला ब्लॉकों का आवंटन नीलामी द्वारा किया जाना चाहिए, जैसा कि नियम है, लेकिन पीएमओ ने उनकी इस राय पर कोई ध्यान ही नहीं दिया.

सीबीआई ने अब तक की गई अपनी जांच में इस बात के संकेत दिए हैं कि पीएमओ के उस समय के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है, बल्कि सीबीआई 2006 से 2009 के बीच पीएमओ में कार्यरत किसी भी अधिकारी को तलब कर सकती है. ऐसा ही उसने आशीष गुप्ता एवं विन्नी महाजन के साथ किया और शायद टीकेए नायर के साथ भी सीबीआई का यही रवैया हो (यह स्टोरी लिखे जाने तक सीबीआई ने टीकेए नायर को नहीं बुलाया था, लेकिन उनसे पूछताछ करने की ख़बरें तेज़ी से आ रही थीं). इससे यह शक तो पैदा होता ही है कि सीबीआई कहीं न कहीं यूपीए सरकार के दबाव में काम कर रही है. हालांकि ऐसी भी ख़बरें हैं कि यूपीए-1 के दौरान पीएमओ में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत रह चुके जावेद उस्मानी एवं विन्नी महाजन से भी सीबीआई पूछताछ करने वाली है. उल्लेखनीय है कि 1978 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी जावेद उस्मानी इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं, जबकि 1987 बैच एवं पंजाब कैडर की आईएएस अधिकारी विन्नी महाजन भी अपने राज्य पंजाब में प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) के पद पर कार्यरत हैं. दूसरी ओर 1963 बैच एवं पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी टीकेए नायर, जो कोयला घोटाले के समय पीएमओ में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत थे, अब भी प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं.

यहां सवाल यह उठता है कि अगर पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता ने सीबीआई जांच की पारदर्शिता क़ायम रखने के लिए अपने वर्तमान पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो फिर मनमोहन सिंह के सलाहकार टीकेए नायर, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी, पंजाब की प्रधान सचिव विन्नी महाजन और 1989 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी आशीष गुप्ता, जो 2006 से 2009 के बीच पीएमओ में कार्यरत थे, को भी अपने-अपने सरकारी पदों से त्यागपत्र दे देना चाहिए. यही नहीं, इस समय पीएमओ के पूर्व प्रधान सचिव एवं प्रधानमंत्री के सलाहकार टीकेए नायर पर भी आरोप लगना चाहिए. इसके अलावा, कोयला घोटाले में कांग्रेस के जिन-जिन नेताओं पर उंगलियां उठ रही हैं, जिनमें फिलहाल नवीन जिंदल का नाम सबसे ऊपर है, उन्हें भी सीबीआई जांच को पारदर्शी बनाने के लिए तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए. चूंकि उन दिनों कोयला मंत्रालय स्वयं प्रधानमंत्री देख रहे थे, इसलिए उनका भी अपने पद से त्यागपत्र देना बहुत ज़रूरी है.

कौन हैं एच सी गुप्ता

1971 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी एच सी गुप्ता को 2 जनवरी, 2006 को पी सी पारिख के सेवानिवृत्त होने के बाद कोयला सचिव बनाया गया था. हम सब जानते हैं कि देश में 26 लाख करोड़ रुपये का कोयला घोटाला 2006 से 2009 के बीच हुआ था. तत्कालीन कोयला मंत्री शिबू सोरेन के जेल में होने के कारण इस मंत्रालय को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वयं संभाल रहे थे. उन दिनों कोयला ब्लॉकों का आवंटन पीएमओ की ओर से गठित एक स्क्रीनिंग कमेटी देख रही थी, जिसकी निगरानी तत्कालीन कोयला सचिव एच सी गुप्ता कर रहे थे. उक्त स्क्रीनिंग कमेटी नियम-क़ानूनों का उल्लंघन करते हुए कैसे कोयला ब्लॉकों की बंदरबांट कर रही थी, इसका अनुमान उस समय विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाली ख़बरों से लगाया जा सकता है. दूसरी ओर कोयला सचिव गुप्ता पीएमओ को बार-बार पत्र लिखकर आगाह कर रहे थे कि कोयला ब्लॉकों के आवंटन में नीलामी विधि अपनाई जानी चाहिए, जैसा कि क़ानून है, लेकिन पीएमओ ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनकी सलाहों को हर बार ठुकराता रहा. ■

बेबस सरकार, बेबस मंत्री

ज़्यादा ताकतवर है तेल लॉबी

क़रीब दो साल पहले चौथी दुनिया ने एक आमुख कथा प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे तेल लॉबी सरकार को अपने नियंत्रण में रखती है और कैसे यह पेट्रोलियम पदार्थों की क़ीमत अपनी सुविधा के मुताबिक बढ़वाती है? बहरहाल, तेल के काले खेल पर विपक्ष के आरोप या मीडिया की रिपोर्ट पर भरोसा न भी करें, तो अभी हाल में खुद पेट्रोलियम मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरप्पा मोइली ने जो बयान दिए हैं, उनसे यह साफ़ हो जाता है कि यह तेल लॉबी सचमुच कितनी ताकतवर है, जिसके आगे कैबिनेट मंत्री भी बेबस है.

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

वीरप्पा मोइली ने कहा है कि तेल आयात करने वाली लॉबी पेट्रोलियम मंत्रियों को धमकी देती है. उन्होंने पूरी ईमानदारी से यह स्वीकार करते हुए कहा है कि देश को तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने से रोकने में एक लॉबी काम कर रही है और मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यह लॉबी हर पेट्रोलियम मंत्री को धमकी देती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोइली को भी इस लॉबी से धमकी मिली है और क्या इसी के कहने पर पूर्व पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी को मंत्रालय से हटाया गया था? वैसे कांग्रेस इस सबसे इंकार कर रही है, लेकिन चूंकि मोइली एक ईमानदार छवि के नेता माने जाते हैं, इसलिए उनके बयान को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता है. हालांकि मोइली ने खुद को धमकी देने वाले लोगों या लॉबी का नाम नहीं बताया. शायद इतना बड़ा खुलासा करने की हिम्मत वह नहीं कर सकते.

बहरहाल, पेट्रोलियम मंत्री के इस बयान से कुछ संकेत तो मिलते ही हैं. मसलन, भारत जनसंख्या के हिसाब से एक विशाल देश है और यहां कच्चे तेल की बहुत ज़्यादा खपत है. खपत के मामले में यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है. जाहिर है, तेल उत्पादक देश, खासकर अमेरिका जैसे देश यह कभी नहीं चाहेंगे कि भारत तेल एवं गैस उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बने, जबकि भारत में खुद प्राकृतिक गैस का प्रचुर भंडार है, लेकिन उसका उचित इस्तेमाल अब तक नहीं हो सका है. अगर भारत खुद अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने लगे, तो इसका सीधा नुक़सान उन देशों को होगा, जो भारत को अब तक तेल बेचते आ रहे हैं. जाहिर है, इतना बड़ा बाज़ार खोने का जोखिम उक्त तेल उत्पादक देश नहीं लेना चाहते. यह बात सर्वविदित है कि तेल के लिए अमेरिका जैसे देश ने इराक और कुवैत जैसे देशों में क्या-क्या काम नहीं किए. इराक युद्ध के बारे में एक तथ्य यह भी है कि सारा खेल सामरिक क्षेत्र के साथ-साथ तेल पर कब्जा करने के लिए खेला गया था. जाहिर है, उसमें पश्चिम की तेल लॉबी का भी बड़ा हाथ था. ऐसे में भारत जैसे विशाल बाज़ार पर कब्जा बनाए रखने के लिए तेल लॉबी एक मंत्री को आसानी से हटवा सकती है या उस पर दबाव भी डाल सकती है.

कैसे तेल लॉबी पेट्रोलियम पदार्थों की क़ीमत के मामले में सरकार पर दबाव डालती है, इसका एक उदाहरण देखिए. आज अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की जो क़ीमत है, उसके मुताबिक़, पेट्रोल का दाम 35 रुपये प्रति लीटर से एक भी पैसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत मई 2011 में 112 डॉलर प्रति गैलन थी, जो अब घट गई है. फिर भी देश में पेट्रोल की क़ीमत गिरने वाली नहीं है. पेट्रोल की क़ीमत में गिरावट तो दूर, तेल कंपनियों के दबाव में सरकार डीजल, केरोसिन एवं रसोई गैस की क़ीमत भी बढ़ाने को मजबूर है. इसके बाद अगर कोई यह आरोप लगाए कि भारत की सरकार तेल कंपनियों के हाथों की कठपुतली बन गई है, तो क्या गलत होगा?

सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि तेल की चोरी और कालाबाज़ारी की वजह से हर साल 70,000 करोड़ रुपये का नुक़सान होता है, उसे ख़त्म करने के लिए उसने क्या किया? जाहिर है, तेल लॉबी और तेल माफिया इसलिए बेलगाम हैं, क्योंकि उन्हें नेताओं का संरक्षण हासिल है, या फिर यूं कहें कि सरकार इसलिए खामोश है, क्योंकि तेल के कारोबार पर उनका नियंत्रण है. सरकार पर तेल कंपनियों, खासकर निजी कंपनियों के दबाव का एक और उदाहरण हमारे सामने है. सरकार ने रंगराजन कमेटी बनाई थी. इस कमेटी से सरकार को उम्मीद थी कि यह पेट्रोलियम पदार्थों की क़ीमतें घटाने और करों के उदारीकरण का सुझाव देगी, लेकिन रंगराजन कमेटी ने उदारीकरण की सलाह नहीं दी. सरकार ने दूसरी कमेटी बना दी. इस बार योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट पारिख को एक्सपर्ट ग्रुप का प्रमुख बनाया गया और उदारीकरण का सुझाव भी दिया गया. सरकार ने तुरंत उस सुझाव को मान लिया. सरकार की तरफ़ से दलील दी गई कि तेल कंपनियों को नुक़सान हो रहा है, इसलिए पेट्रोल के दाम को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से जोड़ना ज़रूरी हो गया है. अब सवाल है कि यह सरकार जनता की है या तेल कंपनियों की? इसका जवाब भले ही सरकार न दे, लेकिन कम से कम खुद उसके पेट्रोलियम मंत्री के हालिया बयान से सब कुछ साफ़ हो जाता है कि कैसे यह सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय तेल लॉबी के इशारे पर काम करने को मजबूर हैं. ■

एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि केंद्र सरकार ने बचाव एवं राहत कार्यों और मुआवजे के लिए जो धनराशि आज दी है.

पृथक तेलंगाना
सरकारों ने जनता को सिर्फ़ छला

अलग तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर जनता को कभी भाजपा, तो कभी कांग्रेस ने छला. न जाने कितने लोगों की जानें चली गईं, लेकिन सरकारों का रवैया शुरू से ही ढुलमुल और निराशाजनक रहा. एक बार फिर तेलंगाना राज्य की मांग जोरों पर है, लेकिन इस बार भी सरकार चुप है. दरअसल, राजनीतिक दल इस समस्या का हल निकालना ही नहीं चाहते!

राजीव रंजन
feedback@chauthiduniya.com

यूं तो किसी भी आंदोलन का शुरू होना और उसकी सफलता बेहद मुश्किल काम है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल काम है सरकार की उन राजनीतिक चालों से सावधान रहना, जो आंदोलन को भटकाने के लिए चली जाती हैं. आंध्र प्रदेश में पृथक तेलंगाना की मांग का हाल भी धीरे–धीरे कुछ ऐसा ही होता जा रहा है. सरकार है कि राजनीति करने से बाज नहीं आती और जनता के पास उस पर विश्वास करने के अलावा, और कोई चारा नहीं है. परिणामस्वरूप यह आंदोलन भी सरकारों के राजनीतिक पाटों के बीच पिसती जा रही है. पृथक तेलंगाना राज्य की मांग कर रही तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) और उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह ने पिछले दिनों तेलंगाना बंद का आह्वान किया. इस बंद का आह्वान चलो असेंबली रैली के दौरान तेलंगाना समर्थक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया. इससे पहले भी पुलिस ने तेलंगाना समर्थक पार्टियों द्वारा आंध्र प्रदेश विधानसभा तक मार्च निकालने का प्रयास विफल कर दिया था. भाजपा के वरिष्ठ नेताओं सहित अलग राज्य के गठन की मांग के समर्थन में सड़क पर उतरे क़रीब 1400 लोगों को हिरासत में ले लिया गया था. तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश सरकार पर तेलंगाना आंदोलन को कुचल देने का आरोप लगाते हुए तेलंगाना क्षेत्र में बंद का आह्वान किया था. दरअसल, भाजपा हो या कांग्रेस, समय–समय पर दोनों ही पार्टियां मुस्लिम हितैषी होने का दंभ भरती रही हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के एक बड़ी संख्या में होने के बावजूद किसी भी पार्टी ने इस ओर आज तक ध्यान नहीं दिया. राज्य में चल रहे मौजूदा घटनाक्रम ने 1969 के आंदोलन की याद दिला दी है, जब जय तेलंगाना आंदोलन के नाम से अलग राज्य की मांग की गई थी और लगभग 360 छात्रों की जान आंदोलन के दौरान चली गई थी.

1953 में जवाहर लाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के लिए एक समिति बनाई थी. जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता वाली इस समिति ने अध्ययन के बाद यह कहा था कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग होना चाहिए या नहीं और अलग होने के बाद उसका भविष्य कैसा होना चाहिए, यह निर्णय तेलंगाना के लोगों को ही लेना है. यह क्षेत्र आर्थिक रूप से आंध्र प्रदेश से पिछड़ा हुआ है, लेकिन राजस्व यहां से ज़्यादा मिलता है. दूसरी बात, कृष्णा एवं गोदावरी पर बने बांधों का लाभ आंध्र के लोगों को ज़्यादा मिलेगा, यह डर भी तेलंगाना के लोगों को है. तीसरी बात, शिक्षा एवं रोजगार में आंध्र के लोगों को वरीयता दी जाएगी, यह संशय भी यहां के लोगों को है. इन तमाम तथ्यों को देखते हुए समिति ने सिफारिश की थी कि तेलंगाना पृथक राज्य बनना चाहिए, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस वादे के साथ कि वह तेलंगाना के लोगों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देगी, उसे आंध्र प्रदेश से अलग नहीं होने दिया. आश्चर्य की बात तो यह है कि इस वादे पर अधिक दिनों तक वह कायम नहीं रही और आज भी तेलंगाना की जनता को यह एहसास बार–बार होता है कि राजनीतिक दल उससे छल रहे हैं.

कुछ रोचक तथ्य

- तेलंगाना पहले हैदराबाद रियासत का हिस्सा था, जिसका मतलब है तेलुगु की धरती.
- 1948 में हैदराबाद रियासत के विलय के बाद 1956 तक तेलंगाना अलग राज्य रहा.
- 1956 में आंध्र में तेलंगाना का विलय हुआ, जिससे आंध्र प्रदेश बना.
- आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य.
- कुल जिले : 10 (ग्रेटर हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेंडक, नालगोंडा, महबूबनगर, वारंगल, करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद और खम्मम)
- क्षेत्रफल: 1 लाख 14 हज़ार 800 वर्ग किलोमीटर.
- आबादी: 3.5 करोड़.
- प्रस्तावित राजधानी: हैदराबाद.
- भाषा: तेलुगु, उर्दू.
- प्रमुख नदियां: कृष्णा, गोदावरी.
- 294 सदस्यीय आंध्र प्रदेश विधानसभा में तेलंगाना क्षेत्र से 119 विधायक पहुंचते हैं.
- आंध्र प्रदेश के 42 सांसदों में से 17 तेलंगाना क्षेत्र के हैं.

राजनीतिक दलों के चोंचले

पृथक तेलंगाना की मांग आंध्र प्रदेश की राजनीति का प्रमुख बिंदु रही है. राज्य अलग बने न बने, लोगों की भावनाओं का सम्मान हो न हो, किंतु इसका भरपूर राजनीतिक लाभ लेने में दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी. जब केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उसने वादा किया कि वह अलग तेलंगाना राज्य ज़रूर बनाएगी. उसके शासनकाल में झारखंड, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ तो बन गए, लेकिन तेलंगाना का गठन अंततः नहीं हो पाया. भाजपा की सहयोगी पार्टी तेलुगुदेशम ने इसका विरोध किया. वर्ष 2000 के बाद तेलंगाना के कांग्रेसी विधायकों ने तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेटिव फोरम का गठन किया. बाद में तेलंगाना राष्ट्र समिति के गठन से इस आंदोलन में और गति आई, लेकिन यह भी राजनीतिक मोह से परे नहीं रह सकी. टीआरएस जब यूपीए सरकार में साथ में थी, तो उसने कई बार सरकार पर तेलंगाना को अलग करने का दबाव बनाया. 2006 में बाकायदा समय सीमा भी दे दी गई, लेकिन फिर भी यह संभव नहीं हो सका. वैसे परिस्थितियां कांग्रेस के लिए भी चुनौतीपूर्ण हैं. जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ की बजाय समस्या का तर्कसंगत समाधान हो, ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए.

श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट

तेलंगाना मुद्दे पर गठित श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट में इस मसले को सुलझाने के लिए छह विकल्पों पर चर्चा की गई है.

- पहला विकल्प : मौज़ूदा स्थिति को बरकरार रखना.
- दूसरा विकल्प : आंध्र प्रदेश को सीमांध्रा और तेलंगाना में विभाजित किया जाए और हैदराबाद को केंद्र शासित बनाया जाए.
- तीसरा विकल्प : आंध्र प्रदेश का रायल, तेलंगाना और तटीय आंध्र क्षेत्र में विभाजन किया जाए, जिनमें हैदराबाद, रायल तेलंगाना का हिस्सा हो.
- चौथा विकल्प : आंध्र प्रदेश को सीमांध्रा और तेलंगाना में विभाजित किया जाए, जिनमें हैदराबाद महानगर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए. इस केंद्र शासित प्रदेश में तीन ज़िलों, रंगारेड्डी, महबूबनगर एवं नलगोंडा को शामिल किया जाए.
- पांचवां विकल्प : आंध्र प्रदेश की सीमांध्रा और तेलंगाना की मौजूदा सीमाओं को बरकरार रखते हुए विभाजित किया जाए, जिनमें हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हो और सीमांध्रा को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाया जाए.
- छठा विकल्प : राज्य को एक रखा जाए, साथ ही तेलंगाना क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कुछ संवैधानिक एवं वैधानिक क़दम उठाए जाएं तथा तेलंगाना क्षेत्रीय काउंसिल का गठन किया जाए. ■

उत्तराखंड
तबाही के लिए सरकार हैं ज़िम्मेदार

सरकार ने अगर पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए समय रहते एहतियात के तौर पर आवश्यक क़दम उठाए होते, तो लोगों की जानें बच सकती थीं, लेकिन उसे तो भ्रष्टाचार और लूट–खसोट से फुर्सत नहीं है. नेताओं को भाषणबाजी से फुर्सत नहीं है. हकीकत तो यह है कि राज्य में आधारभूत सुविधाएं ही नहीं हैं और जो थोड़ी–बहुत है, वह भी बदतर हालत में है.

उत्तराखंड में आई भारी बारिश के बाद बाढ़ की विनाशलीला में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और हज़ारों लोग लापता हैं. क़रीब 12 हज़ार फुट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास सब कुछ बह गया है. केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास मलबे का अंबार लग गया है. राज्य के पिथौरागढ़ की धारचुला तहसील में भी हालात बदतर दिखे. नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाया और गांव के गांव उनकी तेज धारा में बह गए. कुदरत के इस कहर के कारण चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई. जहां–तहां फंसे लोगों को 5000 से ज़्यादा सेना के जवानों और हेलिकॉप्टरों की मदद से सुरक्षित निकाला गया.

राज्य में भारी बारिश से तबाही का जो मंजर देखने को मिला, उसके पीछे सरकार का उदासीन रवैया ही ज़िम्मेदार है. उक्त धार्मिक यात्राएं पहले से ही तय होती हैं. सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति में सरकार समय से पहले कुछ क्यों नहीं करती? सवाल यह भी उठता है कि सरकार तीर्थयात्रियों से मिलने वाले राजस्व का क्या करती है? कहीं यह राजस्व भी सरकार की लूट की भेंट तो नहीं चढ़ जाता? उत्तराखंड में न तो सड़कों की स्थिति सही है और न बिजली–पानी की मुकम्मल व्यवस्था है. अगर सरकार समय रहते इन आधारभूत चीजों को लेकर सजग रहती, तो तबाही के कारण हुआ यह नुक़सान कम हो सकता था. सैकड़ों लोगों की मौत, हज़ारों लोगों के लापता होने और गांव के गांव बह जाने के बावजूद सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है. आश्चर्य की बात तो यह है कि राहत और बचाव कार्य भी पर्याप्त नहीं हैं. हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और 1000 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की, जिसमें से 145 करोड़ रुपये तुरंत देने का वादा भी किया गया. एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि केंद्र सरकार ने बचाव एवं राहत कार्यों और मुआवजे के लिए जो धनराशि आज दी है, उसे अगर पहले, यानी समय रहते राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर खर्च कर दिया गया होता, तो शायद आज यह भयावह स्थिति न आई होती! ■

> राज्य में भारी बारिश से तबाही का जो मंजर देखने को मिला, उसके पीछे सरकार का उदासीन रवैया ही ज़िम्मेदार है. उक्त धार्मिक यात्राएं पहले से ही तय होती हैं. सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति में सरकार समय से पहले कुछ क्यों नहीं करती? सवाल यह भी उठता है कि सरकार तीर्थयात्रियों से मिलने वाले राजस्व का क्या करती है? कहीं यह राजस्व भी सरकार की लूट की भेंट तो नहीं चढ़ जाता?

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

एक और सरबजीत पाकिस्तानी जेल में
हम हो सकते हैं फिर शर्मसार

30 मई को सजा काट चुका भारतीय नागरिक यशपाल आज भी पाकिस्तानी जेल में बंद है. भारत सरकार के ढुलमुल रवैए के कारण अब डर इस बात का है कि कहीं यशपाल भी सरबजीत की तरह सरकार की ओछी राजनीति का शिकार न हो जाए?

यशपाल पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में बंद है. वह अपनी सजा 30 मई को ही पूरी कर चुका है, बावजूद इसके, सरकार उसे छुड़ाने के लिए कोई ठोस क़दम नहीं उठा रही है. यहां यह बताना ज़रूरी है कि यशपाल की तरह ही भारत सरकार सरबजीत की रिहाई को लेकर भी उन दिनों ढुलमुल रवैया अपना रही थी. आख़िरकार सरबजीत ने पाकिस्तानी धरती पर दम तोड़ दिया. भारत सरकार ने सरबजीत की रिहाई को लेकर वर्षों तक राजनीति करने की कोशिश की. आज वही राजनीति यशपाल को लेकर हो रही है. सरबजीत पर सरकार की राजनीति तब तक बंद नहीं हुई, जब तक वह पंचतत्व में विलीन नहीं हो गया. यह हम सभी जानते हैं कि सरबजीत के जीते जी सरकार ने उसकी रिहाई के लिए कोई ठोस क़दम ही नहीं उठाया, लेकिन उसकी मौत के बाद तथाकथित कद्दावर शख़्सियतों ने उसके शव के इर्द–गिर्द जमावड़ा ज़रूर लगाया. सरकार की इस अवसरवादी और घटिया राजनीति को देखकर हर भारतीय का सिर शर्म से झुक गया. भारत सरकार ने जिस तरह से उस समय माहौल बनाया था, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सरबजीत वाली गलती फिर से न दोहराई जाए! हैरानी की बात तो यह है कि 30 मई तक पूरी सजा काट चुके यशपाल की रिहाई को लेकर पाकिस्तान ने भी बिल्कुल चुप्पी साध ली है. पाकिस्तान के इस दुस्साहस के पीछे फिर पूरी तरह से भारत सरकार का ढुलमुल रवैया ही ज़िम्मेदार माना जा रहा है. लाहौर स्थित कोट लखपत जेल में कैद यशपाल फरीदपुर के पढेरा गांव का रहने वाला है. यशपाल 30 मई, 2010 को पाकिस्तानी सीमा में पकड़ लिया गया था. कई दिनों तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां जासूस होने के शक में उससे पूछताछ करती रहीं, लेकिन जब वे यशपाल से कुछ नहीं उगलवा पाईं, तो उसे सीमा उल्लंघन के आरोप में पंजाब की साहीवाल अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुना दी. शुरू में उसे साहीवाल जेल में ही रखा गया, बाद में अन्य भारतीय कैदियों के साथ लाहौर की कुख्यात कोट लखपत जेल में पहुंचा दिया गया. अफसोस! यशपाल की सजा 30 मई को पूरी हो चुकी है, बावजूद इसके पाकिस्तान सरकार ने उसे रिहा नहीं किया. सामाजिक संस्था जागर की कोशिशों से भारतीय उच्चायोग सक्रिय ज़रूर हुआ, लेकिन पाकिस्तानी अफसरों ने यशपाल की पहचान का पेंच फंसा दिया. पिछले दिनों उसकी राष्ट्रीयता से जुड़े सभी दस्तावेज भी पाकिस्तान सरकार को सौंप दिए गए, लेकिन सारे कागजात लेने के बावजूद पाकिस्तानी अफसर लगातार टालमटोल कर रहे हैं. इस मामले में उच्चायोग के काउंसलर एक्विनो विमल ने ई–मेल से बताया कि वह लगातार संपर्क में हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी अफसरों की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है और इसीलिए आज भी यशपाल वहीं कैद है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कांग्रेस से जदयू की हुई नई दोस्ती पर सुशील मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के साथ जाने वालों का गर्त में जाना तय है. देश भर में लोगों के अंदर कांग्रेस के प्रति गुस्सा है

रिश्ते की डोर, यानी गठबंधन टूटते ही नीतीश चुनौतियों से घिर गए हैं. ऐसे में, अब उन्हें न केवल पार्टी के अंदर का असंतोष शांत करना है, बल्कि उन्हें हमलावर विपक्ष से भी चतुराई से निपटना होगा. वहीं दूसरी ओर, भाजपा में यह तय हो गया है कि राज्य के सभी बड़े नेता लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे. दरअसल, सामाजिक समीकरणों में फिट बैठने वाले सभी मजबूत उम्मीदवारों को मोदी मैजिक के कमाल से दिल्ली भेजने की बिसात किस तरह से बिछाई जा रही है, इन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं सरोज सिंह.

कठिन डगर पर नीतीश

लंबी जद्दोजहद, खींचातानी और तीखी बयानबाजी के बीच नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन इस बड़े राजनीतिक फ़ैसले से उन्होंने अपने सामने चुनौतियों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर लिया, जिससे आगे अगर वह नहीं निकल पाए, तो उनके लिए यह क़दम आत्मघाती भी साबित हो सकता है. नीतीश के पुराने मित्र एवं अब नेता विपक्ष नंदकिशोर यादव ने विधानसभा में विश्वास मत के दौरान अपने जानदार भाषण में एक तरह से दोस्ती का फर्ज अदा करते हुए उनके सामने आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा कर दिया. उन्होंने कहा, नीतीश जी, आप बड़ा ख्वाब देख रहे हैं और ऐसे ख्वाब तभी पूरे होते हैं, जब कोई इंसान बड़ी लाइन खींचता है, न कि छोटी लाइन मिटाता है. इसलिए बड़ी लाइन खींचने की कोशिश कीजिए. नंदकिशोर यादव पूरे मूड में थे. वह बोले कि किस–किस को लालबत्ती दीजिएगा नीतीश जी? दर्जनों लोगों को आश्वासन दिया जा चुका है, किसे खुश कीजिएगा और किसे नाराज़? जनादेश तो एनडीए को मिला था. अब आप गठबंधन तोड़ सरकार चला रहे हैं, जनता को क्या जवाब दीजिएगा? उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा समाज से एक चाय बेचने वाले का बेटा देश की कमान संभालने की तैयारी कर रहा है, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? आप नहीं चाहते कि अति पिछड़ा समाज का कोई आदमी देश के सर्वोच्च पद पर जाए. मतलब यह है कि नीतीश कुमार के लिए राज्यपाल कोटे की 12 सीटों का मनोनयन और मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है. मंत्रिमंडल विस्तार को वह ज़्यादा दिनों तक टाल नहीं सकते, क्योंकि निर्दलीय विधायकों का उन पर भारी दबाव है.

इसके अलावा, भाजपा कोटे से खाली विभागों को अगर जल्दी नहीं भरा गया, तो उससे सरकार का कामकाज पूरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि प्रभार देकर काम चलने वाला नहीं है. मंत्रिमंडल विस्तार साल भर से टल रहा है. इस कारण जदयू के बहुत सारे नेता भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव बना रहे हैं कि अब यह राजनीतिक कसरत कर ही दी जाए, लेकिन दावेदारों की फौज नीतीश को परेशान कर रही है. विश्वासमत से पहले ही जदयू के कुछ गुटों ने अलग–अलग बैठक करके अपना एजेंडा तय कर लिया था. जदयू विधायक नीरज कुमार बब्लू एवं जयकुमार सिंह ने तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग तक कर डाली. बाद में नरेंद्र सिंह ने खुद इन ख़बरों का खंडन कर लीपापोती का प्रयास किया. पार्टी के अंदर मांग किसी मुस्लिम नेता को उप मुख्यमंत्री बनाने की भी उठ रही है. तर्क यह दिया जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भाजपा छोड़ने का फ़ैसला हुआ, तो अब किसी मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री बनाकर यह संदेश दिया जाए कि नीतीश सरकार सही मायनों में अल्पसंख्यकों की चिंता करती है. राजद एवं लोजपा तो केवल मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन जदयू की सरकार ने उसे पूरा करने का काम किया है. सूत्रों पर भरोसा करें, तो सांसद ललन सिंह कई बार टेलीफोन से अब्दुल बारी सिद्दीकी का मन टटोल चुके हैं. एक बार तो उन्होंने सिद्दीकी से कहा कि आपके यहां खाने पर आ रहे हैं, लेकिन सिद्दीकी ने ललन सिंह का प्रस्ताव ठुकरा दिया. समस्या यहीं ख़त्म नहीं हो रही है.

नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल विस्तार और मनोनयन कोटे को भरने में सोशल इंजीनियरिंग का विशेष ख्याल रखना होगा. गठबंधन टूटने के बाद अब तक चली आ रही सोशल इंजीनियरिंग की कमर टूट गई है. अब तक होता यह आया था कि अगड़ी जातियों के कोटे को ज़्यादातर भाजपा भर रही थी और उसके बाद का गणित जदयू पूरा कर रहा था. इस तरह सोशल इंजीनियरिंग का सर्किट पूरा किया जा रहा था, लेकिन अब तो यह सर्किट ही टूट गया है, इसलिए पूरा नेटवर्क जदयू को ही पूरा करना है. नीतीश को अगड़ी जातियों को भी मनाना है और दूसरी तरफ़ अपनी पार्टी के आधार वोट को भी बनाए रखना है. इन दोनों में संतुलन बनाए रखना एक बड़ी बाजीगरी है. देखना यह होगा कि नीतीश यह बाजीगरी कर पाते हैं या नहीं. नीतीश के सामने एक परेशानी कांग्रेस को लेकर भी आ रही है. कांग्रेस के चार विधायकों ने विश्वासमत के समर्थन में वोट देकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है. जानकार बताते हैं कि शरद यादव इस घटनाक्रम से बहुत खुश नहीं हैं. कुछ सांसदों ने भी इस क़दम का कड़ा विरोध किया है. दरअसल, कांग्रेस को लेकर देश भर में जो माहौल है, उसमें सांसदों को लगता है कि इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में हो सकता है. नाराज़ सांसदों का कहना है कि जब बहुमत का जुगाड़ हो गया था, तो फिर कांग्रेस के समर्थन की क्या ज़रूरत थी?

जानकार बताते हैं कि इसके पीछे नीतीश कुमार की सोच यह है कि अगर दिल्ली में लोकसभा चुनाव के बाद कोई विशेष परिस्थिति बनी, तो फिर कांग्रेस उन्हें भी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आगे कर सकती है. कांग्रेस को लगता है कि जो दल उसके साथ सीधे नहीं आना चाहते हैं, वे नीतीश को समर्थन दे सकते हैं. इनमें बीजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस एवं वामदल शामिल हैं. अगर त्रिशंकु जैसे हालात बने, जिसकी पूरी आशंका है, तो कांग्रेस बाहर से भी इस तरह के किसी मोर्चे को समर्थन दे सकती है. कांग्रेस पहले भी यह काम करती रही है. जानकार बताते हैं कि नीतीश के मन में भी इसी तरह का गणित है, इसलिए ज़रूरत न होने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस का साथ लिया. दूसरी तरफ़ कांग्रेस को भी इससे 18 सांसदों का एक रिजर्व स्टॉक मिल गया और चुनाव बाद राजनीति का विकल्प भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कांग्रेस के साथ दिखकर लोकसभा की कितनी सीटें बिहार में जीत पाएंगे? अगर सीटें कम रहीं, तो फिर सारा गणित उल्टा हो जाएगा. नीतीश के सामने एक और चुनौती कमजोर संगठन की है, क्योंकि कमजोर संगठन ने ही महाराजगंज में पार्टी की नैया डुबो दी. लगभग तीन सौ बूथों पर पार्टी का पोलिंग एजेंट ही नहीं था. नीतीश को भी इस कमी का एहसास हुआ है और वह जल्द ही राजनीतिक यात्रा पर निकलने वाले हैं. यह यात्रा पूरी तरह पार्टी बैनर पर होगी और इस दौरान कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा. देखा जाए, तो अभी नीतीश को बहुत काम करना है. यह उनके लिए परीक्षा की घड़ी है. इसमें पास होने का मतलब है दिल्ली की दावेदारी और फेल होने का मतलब है, सब कुछ ख़त्म. ■

नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल विस्तार और मनोनयन कोटे को भरने में सोशल इंजीनियरिंग का विशेष ख्याल रखना होगा. गठबंधन टूटने के बाद अब तक चली आ रही सोशल इंजीनियरिंग की कमर टूट गई है. अब तक होता यह आया था कि अगड़ी जातियों के कोटे को ज़्यादातर भाजपा भर रही थी और उसके बाद का गणित जदयू पूरा कर रहा था.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

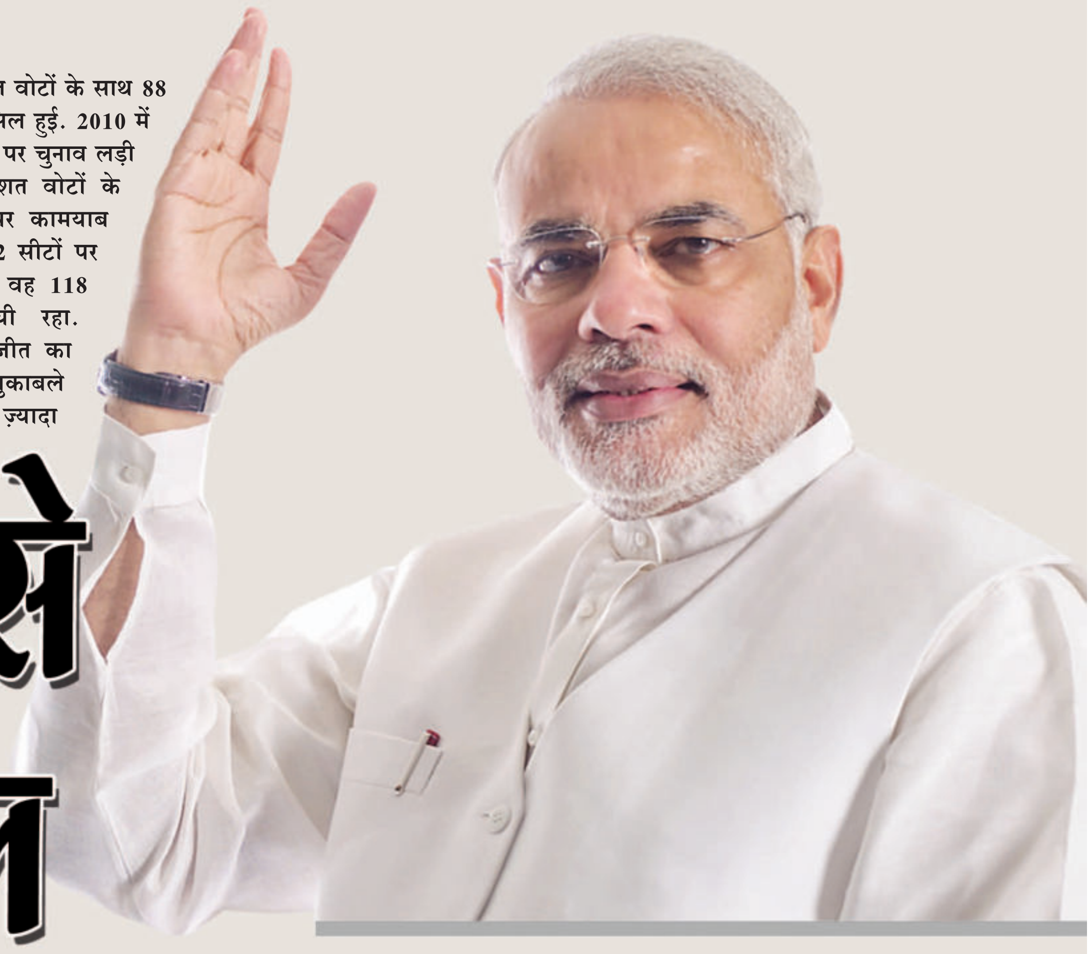

मोदी मैजिक से मिलेगी मंजिल

नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया तो था अपना बहुमत साबित करने के लिए, मगर जब सदन नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा, तो लगा कि यह कुछ और नहीं है, बस मोदी मैजिक है. नीतीश सरकार के सामने 91 विधायकों वाला मुख्य विपक्ष इसी इरादे से आया था कि बहुमत तो सरकार के पास है ही, इसलिए सदन के माध्यम से केवल इतना संदेश दे दिया जाए कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही भाजपा बिहार में जदयू से बड़ी लाइन खींचने जा रही है. यह एक ऐसी लाइन होगी, जिसे पार करना जदयू के लिए असंभव हो जाएगा. हाल यह है कि 17 साल पुरानी दोस्ती टूटने के बाद भाजपा पूरी तरह हमलावर विपक्ष के तेवर में आ गई है. प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय कहते हैं कि हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे. बिहार की जनता और जनादेश के साथ नीतीश कुमार ने जो धोखा किया है, उसका बदला जनता लोकसभा चुनाव में लेगी. इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए सुशील मोदी कहते हैं कि दोस्ती तोड़ने का भी एक तरीका होता है. इतनी पुरानी दोस्ती थी और इसका इतना दु:खद अंत होगा, यह हमारी कल्पना से परे है! नीतीश कुमार अगर एक बार हमारा इस्तीफ़ा मांग लेते, तो घंटे भर में उन्हें सभी भाजपाई मंत्रियों का इस्तीफ़ा मिल जाता, पर उन्होंने मंत्रियों को बर्ख़ास्त करने की सिफारिश कर सामान्य शिष्टाचार का भी परिचय नहीं दिया. खैर, जनता सब देख रही है और आगामी चुनाव में वह धोखा देने वालों को मजा ज़रूर चखाएगी.

कांग्रेस से जदयू की हुई नई दोस्ती पर सुशील मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के साथ जाने वालों का गर्त में जाना तय है. देश भर में लोगों के अंदर कांग्रेस के प्रति गुस्सा है और तय मानिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगियों का सफाया हो जाएगा. दरअसल, सुशील मोदी जो दावा कर रहे हैं, उसके पीछे भाजपा द्वारा इस काम के लिए किया जा रहा होमवर्क है. पार्टी ने लोकसभा की सभी चालीस सीटों के लिए गहन सर्वे का काम शुरू कर दिया है. एक बूथ–दस यूथ की थ्योरी को अमलीजामा पहनाया जा रहा है. काम केवल कागजी न हो, इसलिए बूथों पर तैनात होने वालों के नाम एवं मोबाइल नंबर भी दर्ज हो रहे हैं. गठबंधन धर्म के तहत अगर लोकसभा चुनाव पर नज़र डालें, तो 1996 में भाजपा 32 और समता पार्टी 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी. वर्ष 1999 में भाजपा ने 22 और जदयू एवं समता ने मिलकर 32 सीटों पर चुनाव लड़ा. वर्ष 2004 में यह संख्या और भी घट गई. भाजपा ने 16 और जदयू ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा, वहीं वर्ष 2009 में भाजपा ने 15 और जदयू ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा. निरंतर घटती संख्या को लेकर भाजपा में हर बार सवाल उठते रहे, लेकिन वे सवाल महज सवाल ही रहे.

वहीं विधानसभा की स्थिति देखें, तो वर्ष 1995 में भाजपा के 41 विधायक थे और समता पार्टी के मात्र सात. भाजपा को 12.96 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि समता पार्टी को 7.06 प्रतिशत. इसी चुनाव से नीतीश ने समता पार्टी के नाम से एक अलग पार्टी बनाकर राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी. फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा 103 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिनमें 37 पर उसे विजय हासिल हुई और 10.97 प्रतिशत वोट मिले. जदयू एवं समता पार्टी ने 215 सीटों पर चुनाव लड़ा, उन्हें 75 सीटों पर जीत हासिल हुई और उनका वोट प्रतिशत 25.07 रहा. अक्टूबर 2005 में भाजपा ने 102 सीटों पर चुनाव लड़कर 55 सीटों पर जीत हासिल की और उसका वोट प्रतिशत 15.65 रहा. जदयू ने 139 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उसे 20.46 प्रतिशत वोटों के साथ 88 सीटों पर जीत हासिल हुई. 2010 में भाजपा 102 सीटों पर चुनाव लड़ी और 16.49 प्रतिशत वोटों के साथ 91 सीटों पर कामयाब रही. जदयू ने 142 सीटों पर चुनाव लड़ा और वह 118 सीटों पर विजयी रहा. मतलब यह कि जीत का औसत जदयू के मुकाबले भाजपा का कहीं ज़्यादा बेहतर रहा. भाजपा के रणनीतिकार अब यह मानकर चल रहे हैं कि बिहार की जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें बेहतर सोशल इंजीनियरिंग, मजबूत प्रत्याशी और ऊपर से मोदी मैजिक का तड़का पार्टी को काफी बेहतर परिणाम दिलवा सकता है. इसी मंत्र का जाप कर भाजपा लोकसभा चुनाव में बहुत आगे निकल जाने की व्यूह रचना कर रही है.

नीतीश कुमार एवं लालू प्रसाद से नाराज़ अगड़ी जातियों को गोलबंद करने का अभियान शुरू हो गया है. जदयू में नाराज़ सवर्ण नेताओं को सॉफ्ट टार्गेट बनाया गया है. आरंभिक दौर की बातचीत के बाद फिलहाल उन्हें शांत रहने के लिए कहा गया है. दरअसल, भाजपा चाहती है कि नीतीश सरकार जनता के सामने और भी बेनकाब हों. सदन से लेकर सड़क तक, भाजपा ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि जनता के बीच यह संदेश जाए कि जब तक भाजपा सरकार में थी, तब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन भाजपा के अलग होते ही नीतीश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है. भाजपा को मंत्रिमंडल विस्तार का भी इंतज़ार है. पार्टी के रणनीतिकार यह मानकर चल रहे हैं कि राज्यपाल कोटे की 12 सीटों के मनोनयन और 17 नए मंत्रियों को शामिल करने की कवायद में नीतीश कुमार के पसीने छूट जाएंगे. ऐसी सोच इसलिए भी है, क्योंकि इन पदों के दावेदारों की संख्या सैकड़ों में है और ऐसे में सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार किसे खुश करेंगे और किसे नाराज़. भाजपा इस उम्मीद के साथ इंतज़ार कर रही है कि चापलूसों से घिरे नीतीश इन राजनीतिक नियुक्तियों में बहुत सारे सही दावेदारों को नाराज़ कर देंगे और ऐसी स्थिति उसके लिए बहुत अनुकूल साबित होगी और उसी समय वह सवर्ण गोलबंदी का अपना अभियान तेज कर देगी.

इसके अलावा, भाजपा उपेंद्र कुशवाहा के भी संपर्क में है. उनके माध्यम से जदयू से नाराज़ सांसदों एवं मंत्रियों पर नज़र रखी जा रही है. पार्टी ने मोटे तौर पर फ़ैसला किया है कि उसके प्रदेश के सभी बड़े नेता लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिनमें सुशील कुमार मोदी, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, राधामोहन सिंह एवं संजय पासवान प्रमुख हैं. इसके अलावा, वह अपने–अपने क्षेत्रों में मजबूत नेताओं, जैसे लवली आनंद, छेदी पासवान, ओमप्रकाश यादव, उपेंद्र कुशवाहा, अरुण कुमार, ब्रह्मानंद मंडल, मंगनी लाल मंडल, अन्नू शुक्ला एवं ब्रह्मेश्वर मुखिया के पुत्र इंदुभूषण का मन भी टटोल रही है. मतलब साफ़ है कि सामाजिक समीकरणों में फिट बैठने वाले मजबूत उम्मीदवारों को मोदी मैजिक के कमाल से दिल्ली भेजने की बिसात बिछाई जा रही है. बिसात ऐसी कि कहीं से भी चूक की गुंजाइश न रहे और बाजी हर हाल में भाजपा के हाथ में ही रहे. ■

नीतीश कुमार एवं लालू प्रसाद से नाराज़ अगड़ी जातियों को गोलबंद करने का अभियान शुरू हो गया है. जदयू में नाराज़ सवर्ण नेताओं को सॉफ्ट टार्गेट बनाया गया है. आरंभिक दौर की बातचीत के बाद फिलहाल उन्हें शांत रहने के लिए कहा गया है. दरअसल, भाजपा चाहती है कि नीतीश सरकार जनता के सामने और भी बेनकाब हों. सदन से लेकर सड़क तक, भाजपा ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि जनता के बीच यह संदेश जाए कि जब तक भाजपा सरकार में थी, तब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन भाजपा के अलग होते ही नीतीश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है.

अपने इस दावे के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार ने अख़बारों एवं अन्य संचार माध्यमों के जरिए विज्ञापनों पर लाखों रुपये खर्च कर दिए हैं और अभी भी यह सिलसिला जारी है.

मणिपुर

सरकारी कर्मचारी करते हैं ड्रग्स का काला कारोबार

एस. बिजेन सिंह sbijensngh@gmail.com

भारत-म्यांमार सीमा पर ड्रग्स लेकर जाते लोगों के पकड़े जाने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है. ड्रग्स का यह काला और जानलेवा कारोबार धीरे-धीरे अब पूरे पूर्वोत्तर तक पहुंच चुका है. सबसे दु:खद और आश्चर्यजनक बात तो यह कि इस कारोबार में सरकारी तंत्र भी लिप्त है और उसके सबूत भी मिल रहे हैं. भारतीय सेना एवं मणिपुर पुलिस के जवान और मंत्रियों-राजनेताओं के बेटे आदि सभी इस कारोबार में बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी कर रहे हैं. जब सेना के लोग इस काले कारोबार में लिप्त पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में पूर्वोत्तर में लागू आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पर भी सवाल खड़े होते हैं. कहीं सेना के लोग इस एक्ट की आड़ में तो यह सब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह एक्ट उन्हें काफी अधिकार देता है?

बीते 26 मई को थौबाल ज़िले में पुलिस ने दो लोगों को बड़ी मात्रा में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी क़ीमत अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में 2.50 करोड़ रुपये आंकी गई. ड्रग्स की इस खेप के साथ पकड़े गए वांजिंग निवासी टी बोकुल और थौबाल निवासी एम डी ताजुद्दीन शाह पुलिस अधिकारी हैं. उक्त दोनों पुलिस अधिकारी एक सरकारी जिप्सी पर ड्रग्स की यह खेप लेकर नगालैंड से मणिपुर की तरफ़ आ रहे थे और वह भी बाकायदा यूनिफॉर्म में! जिप्सी में इफिड्रिन बाइउसेट नामक टैबलेट से भरे तीन बॉक्स लदे थे, बाद में टैबलेटों की कुल संख्या 3,19,200 पाई गई. पूछताछ में पता चला कि ड्रग्स की यह खेप सीमावर्ती शहर मोरे (मणिपुर) होते हुए म्यांमार (बर्मा) जानी थी.

हैरान करने वाली घटना तो यह है कि मणिपुर के पलेल नामक जगह से बीते 24 फरवरी को इंफाल में तैनात कर्नल रैंक के डिफेंस पीआरओ अजय चौधरी का 25 करोड़ रुपये के ड्रग्स के साथ पकड़ा जाना. अजय चौधरी के साथ छह अन्य लोग भी थे, जिनमें उसका असिस्टेंट आर के बब्लू, असिस्टेंट मैनेजर इंडिगो- ब्रोजेंद्रो, हाउपू हाउकिप, मिनथं डोंगेल, मिलान हाउकिप एवं साइखोलेन हाउकिप शामिल थे. साइखोलेन हाउकिप वर्तमान कांग्रेसी विधायक टी एन हाउकिप का बेटा है. अजय चौधरी भी ड्रग्स लेकर मोरे जा रहा था.

यह इस काले कारोबार से जुड़ी एक छोटी-सी घटना है. इससे बड़ी और हैरान करने वाली घटना तो यह है कि मणिपुर के पलेल नामक जगह से बीते 24 फरवरी को इंफाल में तैनात कर्नल रैंक के डिफेंस पीआरओ अजय चौधरी का 25 करोड़ रुपये के ड्रग्स के साथ पकड़ा जाना. अजय चौधरी के साथ छह अन्य लोग भी थे, जिनमें उसका असिस्टेंट आर के बब्लू, असिस्टेंट मैनेजर इंडिगो- ब्रोजेंद्रो, हाउपू हाउकिप, मिनथं डोंगेल, मिलान हाउकिप एवं साइखोलेन हाउकिप शामिल थे. साइखोलेन हाउकिप वर्तमान कांग्रेसी विधायक टी एन हाउकिप का बेटा है. अजय चौधरी भी ड्रग्स लेकर मोरे जा रहा था. ग़ौरतलब है कि भारत-म्यांमार मार्ग पर केवल 77 दिनों के अंदर 19 ड्रग्स कारोबारी गिरफ्तार किए गए, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं. जानकार बताते हैं कि क़रीब 90 प्रतिशत ड्रग्स म्यांमार से भारत में आता है. म्यांमार से भारत में ड्रग्स लाने के लिए चार रूट इस्तेमाल किए जाते हैं, तामु (म्यांमार)-मोरे-इंफाल-कोहिमा-डिमापुर, न्यू सोमताल (एक गांव, भारत-म्यांमार सीमा)-सुगनु-चुराचांदपुर-इंफाल-कोहिमा-डिमापुर, खैमान (म्यांमार)-बेहियांग-चुराचांदपुर-इंफाल-कोहिमा-डिमापुर और सोमराह (म्यांमार)-तुइसांग (उख्रूल ज़िला मणिपुर)-खारासोम-जेसामी-कोहिमा (नगालैंड)-डिमापुर. इन चारों रूटों में सबसे ज़्यादा ड्रग्स मणिपुर-नगालैंड होते हुए भारत लाया जाता है.

इस सिलसिले में हाल के दिनों की सबसे बड़ी घटना है, मोरे कमांडो के पूर्व ऑफिसर-इन-चार्ज एवं सब-इंस्पेक्टर आर के बीनोदजीत की गिरफ्तारी, जिसके पास से बरामद ड्रग्स की क़ीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3.64 करोड़ रुपये आंकी गई. बीनोदजीत को बीते 8 मई को गिरफ्तार किया. उसने 11 पुलिसकर्मियों को यह ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करने का ऑर्डर दिया था, जो इसे बर्मा की ओर ले जा रहे थे. फिलहाल बीनोदजीत एवं उसके 11 मणिपुर पुलिस कमांडो साथी जेल में हैं. इस ड्रग्स की डिलीवरी मोरे में होनी थी. मोरे मणिपुर-म्यांमार की सीमा पर बसा एक छोटा-सा बाज़ार है और यह भारत का एक व्यापारिक केंद्र भी है. जबसे इंडो-म्यांमार ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ, तबसे यहां व्यापार के क्षेत्र में काफी तेजी आ गई. रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली कई वस्तुएं म्यांमार से भारत लाकर बेची जाती हैं. इसके बाद उन्हें पूर्वोत्तर और अन्य भारतीय बाज़ारों में बेचा जाता है. ऐसे में सवाल यह है कि ऐसी जगह पर तैनात पुलिसकर्मियों का ड्रग्स के साथ पकड़ा जाना आख़िर क्या साबित करता है?

इसी तरह बीते 29 मई को नार्कोटिक अफेयर्स बॉर्डर पुलिस (एनएबीपी) ने लंफेल के सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इरोइसेम्ब गेट से लगभग 50 लाख रुपये क़ीमत की 25 किलो इफिड्रिन टैबलेट्स के साथ तीन लोगों को धर दबोचा. इससे पहले एक जनवरी को 1.5 करोड़ रुपये का ड्रग्स इंफाल एयरपोर्ट से पकड़ा गया था, लेकिन उसे कौन ले जा रहा था, इसका पता ही नहीं चल सका. कई सामाजिक संगठनों ने इस मामले में किसी सरकारी आदमी की संलिप्तता का शक जताया था. ड्रग्स के इस काले कारोबार का पूर्वोत्तर पर विपरीत असर पड़ रहा है. इस मामले में पूरे पूर्वोत्तर में नगालैंड का दिमापुर सबसे आगे है, जबकि दूसरे नंबर पर मणिपुर का चुराचांदपुर ज़िला है. इन दोनों स्थानों पर आप खुलेआम ड्रग्स की खरीद-फरोख्त और उसका सेवन होते देख सकते हैं. यहां एचआईवी पॉजिटिव कई नवयुवक मिलेंगे, जो बहुत खराब हालत में हैं. सुबह से लेकर शाम तक, पूरे दिन टैबलेट्स खाना और सीरिंज के जरिए ड्रग्स लेना उनका एकमात्र काम है. वे जो सीरिंज अपने दोस्तों को लगाते हैं, उसे दोबारा किसी को भी लगा देते हैं, इससे एचआईवी पॉजिटिव होने की आशंका ज़्यादा रहती है. जाहिर है, उत्तर-पूर्व में चल रहे ड्रग्स के इस काले कारोबार को अगर समय रहते नहीं रोका गया, तो यह उग्रवाद से भी ज़्यादा बड़ी समस्या बन जाएगा. ■

मध्य प्रदेश

...हकीकत झुठलाने की कोशिश

चुनावी वर्ष है, इसलिए राज्य की भाजपा सरकार प्रचार का कोई मौक़ा छोड़ना ही नहीं चाहती, भले ही इसके लिए उसे आंकड़ों की बाजीगरी क्यों न करनी पड़े. अब मामला चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की कामयाबी का हो, या फिर पूंजी निवेश और औद्योगिक विकास का, हर तरफ़ उसका झूठ सहज ही पकड़ा जा रहा है. इसमें कोई दो राय नहीं कि यहां झूठ की बुनियाद पर प्रचार हो रहा है...

संध्या पांडे feedback@chauthiduniya.com

मध्य प्रदेश सरकार मौजूदा चुनावी वर्ष में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी एवं उसके नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि सुधारने के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि विज्ञापनों और प्रचार-प्रसार के अन्य संसाधनों पर खर्च कर रही है. यह देखकर आश्चर्य होता है कि सरकारी अधिकारी हकीकत को झुठला कर केवल प्रचार सुख के लिए सरकारी धन की बर्बादी कर रहे हैं. हाल में वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए, लेकिन राज्य सरकार ने उन आंकड़ों का अपने तरीके से विश्लेषण करते हुए मीडिया के जरिए आम जनता के बीच यह प्रचार करना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली लक्ष्मी योजना की सफलता के कारण राज्य में जनसंख्या का लिंगानुपात संतुलन सुधर रहा है. नतीजतन, लोगों में बालिकाओं के प्रति रुझान धीरे-धीरे बढ़ रहा है. अपने इस दावे के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार ने अख़बारों एवं अन्य संचार माध्यमों के जरिए विज्ञापनों पर लाखों रुपये खर्च कर दिए हैं और अभी भी यह सिलसिला जारी है. विज्ञापनों में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे बुलेटिन 2011-12 के नतीजों का सहारा लेकर बताया गया है कि 2010-11 में प्रति 1000 बालक, बालिकाओं की संख्या 911 थी, जो 2011-12 में बढ़कर 915 हो गई है. इस प्रकार लाडली लक्ष्मी योजना के कारण जनता में बालिकाओं के प्रति रुझान बढ़ रहा है.

राज्य सरकार का यह प्रचार सिर्फ़ आंकड़ों की बाजीगरी का कमाल है, जबकि सच्चाई यह है कि जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शुमार किया जाता है, जहां लिंगानुपात न केवल काफी असंतुलित है, बल्कि बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या काफी कम है. वर्ष 2011 में लिंगानुपात प्रति हज़ार 919 रहा, जो कि वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़े 931 से 12 अंक गिरा है. जनगणना के इन नतीजों से साफ़ है कि 2001-2011 के दशक में मध्य प्रदेश में लिंगानुपात में कोई सुधार नहीं हुआ है, बल्कि चिंताजनक रूप से गिरावट ही आई है, जबकि इस अवधि में दिसंबर 2003 के बाद से अब तक भारतीय जनता पार्टी ही राज्य की सत्ता पर काबिज है. जनगणना के विश्वसनीय एवं निर्विवाद आंकड़ों को झुठलाने के लिए राज्य सरकार ने यह प्रचार शुरू कर दिया है कि लिंगानुपात में सुधार आया है और 4 वर्ष की आयु तक के बच्चों का लिंगानुपात 2010-11 के प्रति हज़ार 911 से बढ़कर 2011-12 में 915 हो गया है.

राज्य सरकार का यह प्रचार सिर्फ़ आंकड़ों की बाजीगरी का कमाल है, जबकि सच्चाई यह है कि जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शुमार किया जाता है, जहां लिंगानुपात न केवल काफी असंतुलित है, बल्कि बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या काफी कम है. वर्ष 2011 में लिंगानुपात प्रति हज़ार 919 रहा, जो कि वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़े 931 से 12 अंक गिरा है.

ग़ौरतलब है कि जनगणना के आंकड़े काफी गहन सर्वे और जांच-पड़ताल के बाद तैयार किए जाते हैं. जनगणना के लिए देश भर में लाखों सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर एक-एक व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाते हैं और जन्म-मृत्यु के ताजा आंकड़ों का भी संकलन करते हैं, जबकि वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण बुलेटिन वास्तव में एक सतही और स्थूल अध्ययन के लिए जारी किया जाता है, जिसमें नमूने के तौर पर राज्य में जन्म-मृत्यु के कुछ हज़ार मामले ही शामिल किए जाते हैं, हालांकि राज्य सरकार अपने फ़ायदे की खातिर इस अप्रिय सत्य को दबाने के लिए झूठ का सहारा लेने में जरा भी शर्म महसूस नहीं कर रही है. ■

झूठ की बुनियाद पर प्रचार

स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य में विकास का अनुकूल माहौल होने एवं सरकार की विकास अभिमुख नीति का जमकर प्रचार करके देश और विदेशों से पूंजीपतियों को पूंजी निवेश के लिए आकर्षित करने में सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन अब सच्चाई किसी के छिपाए नहीं छिप रही है. शायद इसीलिए पूंजी निवेश का वादा करने वाले कई पूंजीपति अब राज्य में पूंजी निवेश करने से कतरा रहे हैं और सरकार के साथ अपने करार रद्द कर रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, 2010 तक पूंजी निवेश के 111 करार रद्द हो चुके हैं और अब एक सौ नए करार भी रद्द किए जा रहे हैं. बताते हैं कि इस बारे में सरकार के साथ समझौते- करार करने वाले पूंजीपतियों को बाकायदा नोटिस भी जारी किए गए हैं. राज्य सरकार ने देशी-विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए हर साल कई इन्वेस्टर्स मीट आयोजित किए, जिन पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाए गए. ग़ौरतलब है कि इंदौर में 2007 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हुआ था और उसमें अरबों रुपये के पूंजी निवेश के करार किए गए थे, लेकिन करार करने वाले पूंजी निवेशकों को जब राज्य की हकीकत का पता चला, तो वे घबरा गए और ऐसे में उन्होंने पूंजी निवेश से हाथ खींच लिए. वर्तमान में लगभग पचास पूंजी निवेशक ऐसे हैं, जो अपने करार रद्द करने के लिए समय का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. इससे लगता है कि सरकार की पूंजी निवेश और औद्योगिकीकरण नीति में कहीं न कहीं खामियां हैं. जानकारों का मानना है कि सबसे बड़ी दिक्कत शासन-प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार है. शीर्ष से लेकर नीचे तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को खुश करने के लिए उद्योगपतियों को रिश्वत देनी पड़ती है. इसके अलावा, विद्युत एवं जल आपूर्ति की समस्याएं भी हैं. उद्योगों के लिए ज़मीन हासिल करना सबसे मुश्किल काम है, इसीलिए राज्य में सीमेंट, स्टील एवं विद्युत उत्पादन संबंधी कई पूंजी निवेश सफल नहीं हो पाए. ग्लोबल मीट के समय मुख्यमंत्री और आला अफसरों ने पूंजी निवेशकों को भरोसा दिलाया था कि उन्हें उद्योग की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन कई उद्योगों को भूमि का आवंटन नहीं हो पाया और जिन्हें भूमि आवंटन के प्रस्ताव मिले, वे आवंटित की जाने वाली भूमि से संतुष्ट नहीं हुए. कई औद्योगिक प्रस्ताव 3 से 5 साल की अवधि से केवल इसलिए लंबित हैं, क्योंकि उन्हें ज़रूरत के अनुसार, भूमि उपलब्ध नहीं हुई. ग्लोबल मीट में पूंजी निवेश के कई बोगस और अगंभीर करार हुए, जिनका जमकर प्रचार भी हुआ. ऐसे मामलों में सरकार द्वारा करार करने वालों से पत्र व्यवहार करने पर कोई जवाब ही नहीं मिलता. इस सबसे स्पष्ट है कि राज्य में भारी-भरकम पूंजी निवेश और विकास का सुनहरा सपना दिखाने का प्रचार केवल झूठ की बुनियाद पर किया जा रहा है. ■

रामपुर का एक समृद्ध इतिहास रहा है. इसे 1774 में नवाब फ़ैजुल्लाह ख़ां ने बसाया था. इससे पूर्व इसे रम्पुरा के नाम से जाना जाता था और यहां राजा राम सिंह का शासन था.

उत्तर प्रदेश

विरोधियों की साज़िश में घिरे राहुल

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी राजनीति के रंग में रंगते जा रहे हैं. उनकी बातों में अब ईमानदारी की महक नहीं है, बोलचाल का लहजा बदल गया है, विश्वास में कमी आई है और कामयाबी के लिए अपनी पीठ थपथपाना और नाकामी का ठीकरा विरोधियों के सिर फोड़ने में उन्हें महारथ हासिल है. लेकिन क्या है जमीनी हकीकत?

अजय कुमार

राहुल गांधी ने पिछले दिनों अमेठी का विकास न हो पाने के लिए राज्य की सपा सरकार को घेर लिया. एक तरफ़ उन्होंने सपा सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई, वहीं दूसरी तरफ़ भावनाओं के सहारे क्षेत्रीय जनता को अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश की. वह जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं-नेताओं से संपर्क कर रहे थे. जनता उन्हें समस्याएं बता रही थी और पार्टी नेता-कार्यकर्ता उन्हें नफा-नुकसान की गणित समझा रहे थे. जनता का कहना था कि कहीं सड़क खराब है, तो कहीं बिजली-पानी की समस्या है और अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है. जनता की नाराज़गी अपने सांसद से थी, लेकिन वह उसकी भावनाओं को समझने के बजाय हवा का रुख सपा सरकार की तरफ़ घुमाने में लगे थे. वह जनता को समझा रहे थे कि अमेठी के विकास में प्रदेश सरकार बाधक बनी हुई है. अगर यहां उनकी सरकार होती, तो नजारा कुछ और होता. एक तरफ़ वह अखिलेश सरकार को नाकारा साबित करने में लगे थे, तो दूसरी तरफ़ जनता को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार वादे कर रहे थे. राहुल बता रहे थे कि आधार कार्ड के माध्यम से लोगों को कैश सब्सिडी का लाभ अतिशीघ्र मिलेगा, लेकिन शायद उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि प्रदेश में आधार कार्ड बनाने का काम कछुआ गति से चल रहा है. अगर आधार कार्ड को आधार बनाकर सब्सिडी दी गई, तो चार-पांच प्रतिशत लोगों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. वह जनता को बता रहे थे कि किसानों, मज़दूरों एवं निर्बल आय वर्ग के लोगों के विकास के लिए आने वाले दिनों में कई योजनाएं आएंगी, लेकिन इसका जवाब उनके पास नहीं था कि उक्त योजनाएं चार वर्षों तक क्यों नहीं बनीं.

जनता को वादों के जाल में फंसाने को आतुर राहुल शायद हकीकत देखने-समझने के लिए तैयार नहीं थे. सच तो यह है कि अमेठी में नए राशनकार्डों के सत्यापन में बीपीएल एवं अंत्योदय योजना के पात्र लाभार्थियों के साथ खुलेआम धोखाधड़ी हो रही है. यहां पांच हज़ार रुपये में बीपीएल और दस हज़ार रुपये में अंत्योदय राशन योजना का कार्ड मिल रहा है. साजिशन और राजनीतिक हित साधने के लिए बांग्लादेशियों को भी ग़ैर-क़ानूनी तरीके से भारतीय नागरिकता दिलाई जा रही है. इस खेल में ग्राम विकास अधिकारी से लेकर ग्राम सेवक तक शामिल हैं. जिलाधिकारी कहते हैं कि अगर उनके पास कोई शिकायत आएगी, तो सत्यापन टीम के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और दोषियों को जेल भेजा जाएगा. हालात इतने खराब हैं कि अमेठी के जामो इलाके में राशनकार्डों के सत्यापन के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए और अंधाधुंध फायरिंग भी हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई. जिले में सत्यापन को लेकर रोज लाठियां चलती हैं. बीपीएल और अंत्योदय योजना के कार्ड सरकारी कर्मचारियों, ज़मीदारों और डॉक्टरों को भी दे दिए गए हैं. बीपीएल कार्ड सूची में हेराफेरी का मामला लोकसभा में भी उठ चुका है, इसके बावजूद चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कोई ठोस क़दम नहीं उठाया जा रहा है. ज़रूरतमंद लोग पैसा न दे पाने के कारण इसका फ़ायदा उठाने से वंचित हैं. राशनकार्ड धारकों की पात्रता जांचने के लिए गठित टीम ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया. उसने घर-घर जाकर राशनकार्ड धारकों का ज़मीनी सत्यापन करने के बजाय ग्राम प्रधानों के दरवाजे पर बैठकर वह पुरानी बीपीएल सूची बहाल कर दी, जो 2002 में बनी थी और जिसमें अपात्रों को शामिल करने के आरोप पहले ही लग चुके हैं.

एक ओर राहुल विकास न होने का प्रलाप कर रहे हैं, तो वहीं राज्य के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि सपा सरकार प्रदेश का विकास अपने प्रयासों से करा रही है. केंद्र से उसे आर्थिक मदद की दरकार है, लेकिन केंद्र सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते कोई फ़ैसला नहीं ले रही है. दरअसल, राहुल गांधी को लगता है कि जनता का दिल बातों का मरहम लगाकर जीता जा सकता है, लेकिन इसके लिए मजबूत इरादे के साथ-साथ शक्तिशाली संगठन एवं कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है. शायद इसीलिए वह अमेठी की कांग्रेस इकाई की ओवरहालिंग करने का मूड बना चुके हैं. स्थानीय संगठन में व्यापक फेरबदल किए जाने की बात कहकर राहुल ने जता दिया कि उनकी नज़र लोकसभा चुनाव पर है. दूसरी ओर, सपा सरकार को राहुल की यह तेजी रास नहीं आ रही है. जैसे ही राहुल ने सपा सरकार पर हमला बोला, समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने पलटवार करते हुए उन्हें निशाने पर ले लिया. उन्होंने कहा कि ऐसी बातें तो कोई नादान शख्स ही कर सकता है. केंद्र में कांग्रेस का राज है और प्रदेश में पिछले पांच सालों तक बसपा राज कांग्रेस के भरोसे ही चलता रहा. अमेठी-रायबरेली में एकाध अंतराल को छोड़कर उनके परिवार का ही वर्चस्व रहा. ऐसे में प्रदेश और क्षेत्र का विकास न होने की बात असंगत है. बसपा राज में प्रदेश में विकास अवरुद्ध रहा. सरकारी खजाना पत्थरों, पार्कों, स्मारकों एवं प्रतिमाओं पर लुटाया जाता रहा. केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार चुपचाप प्रदेश का विनाश देखती रही. समाजवादी पार्टी समाजवाद, लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता को मजबूती देने और प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है. जो लोग प्रदेश का सद्भाव बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं, उन्हें करारा जवाब देने के लिए जनता तैयार खड़ी है. ■

सभी ड्रीम प्रोजेक्ट मरणासन्न की स्थिति में...

संजय सक्सेना
feedback@chauthiduniya.com

विकास न होने का ठीकरा सपा सरकार पर फोड़ने वाले राहुल गांधी अपनी सांसद निधि भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं. पिछले दो वर्षों के चार करोड़ रुपये के बारे में उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा. 2004 में उन्होंने ग्रामीण महिलाओं का सेल्फ हेल्थ ग्रुप बनाया एवं उन्हें बैंक से कर्ज दिलाया और दूसरा यह कि दिल्ली की मदर डेरी की तर्ज पर यहां काम शुरू कराया, लेकिन ये दोनों ड्रीम प्रोजेक्ट मरणासन्न हो गए हैं. स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोज़गार से जुड़ी कई योजनाएं नाकाम हो जाने से जनता की नाराज़गी लगातार बढ़ती ही जा रही है. पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1982 में मुंशीगंज में राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज की नींव इसलिए रखी थी, ताकि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें. यहां से पढ़-लिखकर चिकित्सक बाहर निकलें, लेकिन यह योजना भी वर्षों तक खटाई में पड़ी रही. 2003 में तत्कालीन सांसद सोनिया गांधी ने प्रदेश सरकार से मेडिकल कॉलेज के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगा और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने स्थलीय निरीक्षण भी किया, लेकिन राहुल गांधी द्वारा रुचि न लेने से यह योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई. मुंशीगंज स्थित संजय गांधी चैरिटेबल हॉस्पिटल को भी राहुल की मेहरबानी से एक प्राइवेट ग्रुप को सौंप दिया गया. नतीजतन ग़रीबों के लिए इस अस्पताल के दरवाजे स्वत: बंद हो गए.

राहुल ने अरविंदो आई हॉस्पिटल मदुरई से अनुबंध कर मुंशीगंज में इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय खुलवाया, लेकिन मात्र तीन वर्षों के भीतर अनुबंध टूट गया. राजीव गांधी सचल स्वास्थ्य सेवा का हाल बहुत खराब है. राजीव गांधी ग्रामीण साक्षरता कार्यक्रम बंद पड़ा है. गैस आधारित फैक्ट्री भेल को अमेठी के नवयुवकों को अपने यहां रोजगार देना था, लेकिन उसने हरिद्वार-भोपाल से स्टाफ पूरा कर लिया. यही रवैया कोरवा स्थित एचएएल और फुरसतगंज स्थित एफडीडीआई पेट्रोलियम फैक्ट्री ने अपनाया. स्थानीय युवाओं को रोज़गार के लिए आंदोलन करना पड़ा. जिन किसानों की ज़मीनें उक्त योजनाओं के लिए ली गई थीं, उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं. ■

शाहिद नईम
feedback@chauthiduniya.com

आज़म ख़ां की नई राजनीतिक चाल

झूठे नवाबों, रामपुर छोड़ो!

रामपुर को नवाबों ने बसाया था, इसीलिए लोग इस शहर को आज भी नवाबों के रामपुर के नाम से जानते हैं, लेकिन अब इस ऐतिहासिक शहर की पहचान मिटाने के लिए राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि जिन्होंने इस शहर की बुनियाद रखी थी, अब उन्हें ही यहां से निकालने का षड्यंत्र रचा जा रहा है.

लगभग 40 साल से रामपुर की राजनीति में आज़म ख़ां का दबदबा है, लेकिन सच तो यह है कि उनकी सियासत केवल नवाबों के विरोध और दुश्मनी के बल पर ही क़ायम है. आज़म ख़ां सपा सरकार में इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में नगर विकास मंत्री हैं, लेकिन रामपुर की जनता को उन्होंने बिजली के अलावा, आज तक कुछ भी नहीं दिया. लोग बीड़ी बनाकर, कारचोब, ज़रदोज़ी एवं पतंगसाज़ी का काम करके और रिक्शा चलाकर अपना पेट पाल रहे हैं. आरा मशीनें भी बंद कर दी गई हैं. जौहर यूनिवर्सिटी के रास्ते में जो दुकानें और मकान आ रहे हैं, उन्हें भी तोड़ा जा रहा है, ताकि सड़कों को साफ़-सुथरा बनाया जा सके. ग़ौरतलब है कि सपा की पिछली सरकार में शहर के एकमात्र सरकारी मांटेसरी स्कूल की इमारत और उसके परिसर में स्थित जौहर मेमोरियल को मर्जर एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए ख़त्म कर दिया गया था. नवाबों द्वारा इस शहर में बनवाए गए बुलंद दरवाज़े या तो तोड़ दिए गए हैं या फिर उनके नाम बदले जा रहे हैं. जैसे कि राहे रज़ा का नाम जौहर रोड और राहे मुर्तुज़ा का नाम शौकत अली रोड कर दिया गया है. रोहिल्ला इतिहास की पहचान नवाब गेट को आज़मुद्दीन गेट, शाहबाद गेट को ईदगाह गेट और दिल्ली गेट को बाबे इल्म का नाम दे दिया गया है. हद तो यह है कि नवाबी दौर की सभी स्मृतियां मिटाई जा रही हैं और नवाबों को शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिसके लिए बाक़ायदा एक मुहिम शुरू कर दी गई है.

जौहर विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक भूमिका मिलने पर आज़म ख़ां ने अपने संबोधन में कहा कि नवाबों के अत्याचार सब जानते हैं, उनके दौर में किसी को सड़क पर चलने की इजाज़त नहीं थी. कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था, उन्हें लोगों को गुलाम बनाना पसंद था और उनसे यहां की जनता नफ़रत करती है, इसलिए उन्हें रामपुर छोड़ना होगा. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बीते 30 मई को सपा के कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में एकत्र हुए, जहां नूरमहल के ख़िलाफ़ ख़ूब आग उगली गई. बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य नसीर ख़ां के नेतृत्व में शहर में एक जुलूस भी निकाला. उनके हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था, शिक्षा के दुश्मन, झूठे नवाबों, रामपुर छोड़ो, रामपुर छोड़ो. इस पर नवाब काजिम़ अली ख़ां की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया मिली. उन्होंने कहा कि आज़म के पुरखे नेहटोर (बिजनौर) से आकर रामपुर में बसे थे, उन्हें वहां जाकर रहना चाहिए और हमारे पुरखों ने तो इस शहर को आबाद किया था, तो फिर हम क्यों रामपुर छोड़ें? नवेद मियां ने इसका विरोध किया और कहा कि आज़म ख़ां रामपुरी नहीं हैं, इसीलिए वह रामपुर को बर्बाद करने पर आमादा हैं. उन्होंने रामपुर के लोगों से रोज़गार छीनकर उन्हें 25 साल पीछे कर दिया है. दरअसल, आज़म ख़ां जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बेहद गंभीर हैं और उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार हैं. लेकिन आज़म ख़ां को यह सोचना चाहिए कि संस्कृति किसी भी राष्ट्र के लिए ऐतिहासिक धरोहर होती है, इसलिए उसकी सुरक्षा हर हाल में होनी चाहिए. विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों, भवनों, सड़कों एवं दरवाज़ों के नाम बदलने और नवाबों से रामपुर छोड़कर चले जाने के लिए कहने से सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता, बल्कि यह इतिहास के साथ खिलवाड़ करना होगा.

रामपुर का एक समृद्ध इतिहास रहा है. इसे 1774 में नवाब फ़ैजुल्लाह ख़ां ने बसाया था. इससे पूर्व इसे रम्पुरा के नाम से जाना जाता था और यहां राजा राम सिंह का शासन था. रोहिल्ला सरदारों एवं नवाबों ने सत्ता हासिल करने के बाद न तो इस शहर का नाम बदलने की कोशिश की और न ही यहां मौजूद हिंदुओं के पवित्र स्थलों एवं मोहल्लों को कोई क्षति पहुंचाई. सरकारी दस्तावेज़ों में दर्ज नाम मुस्तुफ़ाबाद प्रस्तावित है, लेकिन इस नाम को लोकप्रियता न मिलने के कारण रम्पुरा से यह शहर रामपुर के नाम से मशहूर हो गया. रामपुर के प्रथम नवाब फ़ैजुल्लाह ख़ां बहुत ही मिलनसार एवं धार्मिक व्यक्ति थे. उनकी धार्मिक सहिष्णुता का ही उदाहरण है कि कोसी स्थित प्राचीन मंदिर और श्मशान घाट सदियां गुज़र जाने के बाद आज भी यथास्थिति में है. यही नहीं, शहर के प्रतिष्ठित लोगों के नाम पर आबाद मोहल्ले मसलन, कूचा भागमल, कूचा देवीदास, कूचा परमेश्वरी दास, चाह केसर सिंह, बाग़ीचा ज़ोक़ी राम एवं गणेश घाट आदि आज भी सुरक्षित हैं. नवाब फ़ैजुल्लाह ख़ां के बाद मोहम्मद अली ख़ां, गुलाम मोहम्मद ख़ां, मोहम्मद सईद ख़ां और फिर यूसुफ़ अली ख़ां ने रियासत की सत्ता संभाली. इन नवाबों ने अपने शासनकाल में रामपुर की हिंदू-मुस्लिम जनता के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए अथक प्रयास किए.

शैक्षणिक, औद्योगिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं आधुनिक विकास के नज़रिए से नवाब रज़ा अली ख़ां के शासनकाल को सुनहरा युग कहा जा सकता है. वह कला, संस्कृति एवं व्यापार के विकास के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे. रज़ा अली ख़ां ने रामपुर में गांधी समाधि बनवाई, जिसे देश में दिल्ली के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है. इसके अलावा, अपने शासनकाल में उन्होंने बिजली आपूर्ति शुरू कराई और रेडियो स्टेशन स्थापित कराया. जनता को शिक्षित बनाने के लिए नवाब रज़ा अली ख़ां ने कई क्रांतिकारी क़दम उठाए. उन्होंने रामपुर के युवाओं के लिए रज़ा डिग्री कॉलेज, रज़ा इंटर कॉलेज, हामिद इंटर कॉलेज (पूर्व में स्टेट हाईस्कूल), जुल्फ़िक़ार स्कूल, बाक़र स्कूल, मॉडल मॉन्टेसरी स्कूल और लड़कियों के लिए ख़ुर्शीद गर्ल्स इंटर कॉलेज एवं क़मर लक़ा स्कूल की स्थापना कराई. साथ ही कई प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल भी स्थापित कराए गए. ग़ौरतलब है कि उक्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए नवाब रज़ा अली ख़ां ने या तो नए भवनों का निर्माण कराया या फिर अपने परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण भवन उसके लिए दान कर दिया. रज़ा अली ख़ां को खेलों से काफी लगाव था, इसीलिए उन्होंने फिजिक़ल कॉलेज और स्टेडियम बनवाए, जिनमें स्वीमिंग पूल, जिम्नेजिय़म हॉल और स्केटिंग बॉल आदि भी शामिल हैं.

नवाब रज़ा अली ख़ां के दौर में रामपुर ने औद्योगिक रूप से इतना विकास किया कि कानपुर के बाद अगर उत्तर प्रदेश में कहीं सबसे ज़्यादा कारख़ाने थे, तो वह रामपुर में ही थे. रज़ा अली ख़ां की प्रेरणा से ही रामपुर में टेक्सटाइल मिल, रज़ा शुगर फैक्ट्री, ज्वाला फैब्रिक्स, डॉन मैच फैक्ट्री, हंसा साइकिल्स, बून फैक्ट्री, बून फर्टिलाइजर्स, मेस फैक्ट्री, किट प्लाइवुड फैक्ट्री, टेंट फैक्ट्री, ऑयल मिल्स, रामपुर पाटरेज़, गन फैक्ट्री, स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री के अलावा, कई फ्लोर मिलों एवं फैक्ट्रियों की स्थापना हुई, जो सालों-साल तक चलती रहीं. लेकिन बाद के राजनीतिक पचड़ों ने इन सब फैक्ट्रियों-कारखानों का अस्तित्व ही ख़तरे में डाल दिया और एक दिन ऐसा भी आया, जबकि यहां केवल एक फैक्ट्री शेष रही. 70 के दशक तक रामपुर में औद्योगिक गतिविधियां समाप्त हो चुकी थीं. शैक्षणिक रूप से भी यह उसी स्थिति में था, जहां इसे नवाबों ने छोड़ा था. रामपुर रियासत का इतिहास पढ़ने के बाद भी अगर कोई शख्स यह कहता है कि नवाबों ने रामपुर की जनता पर अत्याचार किए, उन्हें शिक्षा से दूर रखा और उन्हें अच्छी सड़कों एवं रोज़गार से वंचित रखा, तो यही कहा जाएगा कि वह शख्स या तो नवाबी दौर से अच्छी तरह परिचित नहीं है या जानबूझ कर नवाबों की छवि ख़राब कर रहा है या फिर उसे नवाबों से व्यक्तिगत घृणा है. ■

उत्तर प्रदेश

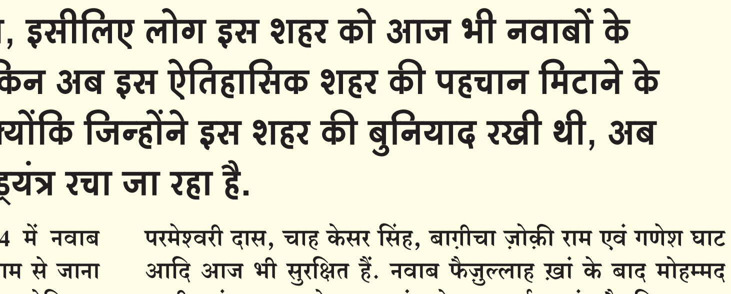

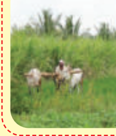

राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव घोषणा-पत्रों में किसानों की सुविधाओं का तो जिक्र किया है, लेकिन किसानों को वाजिब दाम मिले, इसका उनमें उल्लेख नहीं रहता है.

जेफरसन ने अमेरिकी संविधान के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने संविधान बनाने वालों के लिए बहुत ही उम्दा विचार रखे हैं, जिन्हें खारिज करना आसान नहीं है.

www.kamalmorarka.com

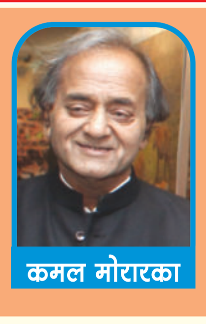

कमल मोरारका

हमें सबक सीखना चाहिए

पिछले दिनों दो घटनाएं हमारे सामने आईं. पहली घटना प्राकृतिक आपदा से संबंधित थी और दूसरी राजनीतिक परिवर्तन की. प्रस्तुत टिप्पणी यह बताती है कि घटना कोई भी हो, वह हमेशा एक संदेश अपने पीछे छोड़ जाती है, जिस पर हमें मनन ज़रूर करना चाहिए.

पिछले दिनों भारत को एक भारी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा. हिमालय की गोद में आई यह आपदा काफी वक्त तक लोगों के जेहन में रहेगी. पूरे के पूरे शहर और छोटे कस्बे इस आपदा के शिकार बन गए. सवाल यह उठता है कि इस सबकी वजह क्या रही? मेरे हिसाब से पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है, जो सरकार और शासन की प्राथमिकता में सबसे नीचे है. यह आपदा एक पर्यावरणीय मुद्दा भी है. सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं देती कि कैसे हमारे पर्यावरण को ख़तरा पहुंच रहा है, इससे क्या नुक़सान हो सकते हैं और इससे बचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? दूसरी तरफ़, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो पैसों के लालच में पर्यावरण को नुक़सान पहुंचा कर अनाप-शनाप निर्माण करते रहते हैं और इस सबका भुगतान करता है बेचारा आम आदमी. इस आपदा में जितने भी लोग मारे गए हैं, उस घटना को बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन हां, इसके बाद हिमालय क्षेत्र में नदी तट पर किए गए निर्माण पर ध्यान ज़रूर दे सकते हैं. इस सबसे कितना ख़तरा है, इसका तत्काल आकलन करने की ज़रूरत है. हालांकि प्रधानमंत्री ने राहत कार्यों के लिए एक हज़ार करोड़ रुपये दिए हैं, लेकिन यह एक अलग मुद्दा है. असल मुद्दा तो यह है कि स्थानीय लोगों का पुनर्वास कैसे हो और कैसे इन पैसों का सही इस्तेमाल हो, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. अवैध निर्माण की समस्या का समाधान निकाल कर अगले दो से तीन सालों में हिमालय को ठीक करने की ज़रूरत है.

इस बीच एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना घटी. बिहार में राजग टूट गया और नीतीश कुमार की सरकार अल्पमत में आ गई. उन्होंने एक सच्चे लोकतंत्रवादी के रूप में राज्यपाल से बहुमत साबित करने की अनुमति मांगी. भाजपा स्वाभाविक रूप से इस मामले में एक लूज़र रही. उसके मंत्रियों को अपने पद से हाथ धोना पड़ा. हालांकि, भाजपा अब भी नहीं समझ रही है. उसने नीतीश कुमार को अवसरवादी कहा है और उसके नेता नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार भाजपा के बंधुआ मज़दूर थे? जबकि सच तो यह है कि वह इस गठबंधन में एक कनिष्ठ साथी थे. भाजपा कह रही है कि उन्होंने विश्वासघात किया है. दरअसल, भाजपा की यही गलत मानसिकता उसकी हालत के लिए ज़िम्मेदार है. मोदी को आगे बढ़ाने के बाद उसके प्रवक्ता द्वारा जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह हिटलर और गोएबल्स की याद दिलाता है. भाजपा हमेशा फासीवादी प्रवृत्ति के तहत काम करती रही है. आडवाणी जी और मोदी के मामले में जो कुछ भी हुआ, उसे पूरे देश ने देखा और समझा. क्या मोदी को आगे बढ़ाने के लिए कोई आम सहमति बनाई

गई? बल्कि उल्टे, एक फासीवादी तरीका अपनाया गया. और अब भाजपा नीतीश कुमार को अवसरवादी बता रही है! यदि भाजपा में थोड़ी-सी भी क्षमता बची है, जिससे कि वह केंद्र में सरकार बना सके, तो उसे राजनीतिक रूप से सही होने की ज़रूरत है. इसके लिए उसे पढ़ना और सीखना चाहिए. इस बात की भी ज़रूरत है कि वह संविधान पढ़े. माना कि आपके पास आरएसएस की तरह एक कैडर है, लेकिन आप यह मत समझिए कि आपका काम इतने से ही निकल जाएगा. देश की जनता सब कुछ देखती है और समझती भी है. इसी जनता ने इंदिरा गांधी के आपातकाल को बर्दाश्त नहीं किया था और उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था. जितनी जल्दी भाजपा इस पाठ को सीख लेती है, उतना ही उसके लिए अच्छा होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

उत्तराखंड की मदद हर भारतीय का कर्तव्य है

उत्तराखंड की आपदा क्या दैवीय आपदा है? क्या यह भगवान की नाराज़गी का परिणाम है, या यह गंगा मां के गुस्से का परिणाम है? हम हिंदुस्तान के लोग नुक़सान उठाने के बाद अपनी संतुष्टि के लिए भगवान पर ज़िम्मेदारी डाल देते हैं और यह आदत उन्हें बचा ले जाती है, जो आपदा के लिए ज़िम्मेदार होते हैं. इस बार भी यही हो रहा है.

अन्ना हज़ारे की यात्रा उत्तराखंड में 13 मई से 24 मई तक चली. एक पत्रकार के नाते मैं भी इस यात्रा में शामिल हुआ. इस यात्रा में मैं हर उस स्थान पर गया, जहां आज अख़बारों में विनाशलीला के समाचार छप रहे हैं. श्रीनगर हो या चमोली, रुद्रप्रयाग एवं बागेश्वर, हर जगह तबाही का मंजर है. कुला मिलाकर गढ़वाल वाला हिस्सा इतिहास की सबसे बड़ी विनाशलीला का गवाह बन गया है. इस यात्रा में जाते हुए हमने देखा कि जिले स्तर के हेडक्वार्टर पर चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं. हमने देखा कि उत्तराखंड में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की देखरेख का कोई प्रबंध ही नहीं है. हमने यह भी देखा कि वहां मेंटिनेंस की इकाइयां नहीं हैं और हमने यह भी देखा कि उत्तराखंड में किसी को इसकी चिंता भी नहीं है.

मैं उदाहरण के रूप में उत्तरकाशी का नाम लेता हूं. जब हम उत्तरकाशी गए, तो हमें उत्तरकाशी के पत्रकार साथियों एवं नागरिकों ने बताया कि अभी साल भर पहले उत्तरकाशी में बाढ़ की वजह से विनाशलीला हुई थी और आसपास के ज़्यादातर घर टूटकर नदी में गिर गए थे. उसकी सफाई और नदी के उथलेपन को दूर करने के लिए पैसों का इंतज़ाम भी हुआ था, लेकिन जानबूझ कर कोई भी काम बारिश से पहले शुरू नहीं कराया गया. उत्तरकाशी के लोगों ने हमें साफ़ कहा कि इस बार उत्तरकाशी तबाह हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से नदियों में मिट्टी भर गई है, सफाई नहीं हुई है, किनारे टूट रहे हैं और इस बार की बारिश तबाही लाएगी. इस बात का जिक्र अन्ना हज़ारे की आम सभा में भी हुआ, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया. उत्तराखंड की सरकार ने, जिसमें मंत्री, विपक्ष और ब्यूरोक्रेसी आती है, उसने जानबूझ कर उत्तरकाशी को तबाह किया. यही हाल श्रीनगर, टिहरी, गोपेश्वर, बागेश्वर, चमोली, यानी हर जगह का है. ऐसा नहीं था कि लोगों को नहीं मालूम था कि बारिश होगी, क्योंकि हर साल बारिश होती है. उन्हें यह भी पता था कि बाढ़ आएगी. यह कैसी सरकार है, जो यह अंदाज नहीं लगा पाई कि इस सीमा तक यदि पानी आता है, या कौन सी वह सीमा है, जिसे पार करने के बाद तबाही मच सकती है, इसकी तैयारी करनी चाहिए थी. यह कैसी सरकार है और कैसा इसका आपदा प्रबंधन है? और आपदा प्रबंधन केवल उत्तराखंड का नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन पूरे देश का.

शायद हमारे यहां बाढ़, सूखा और भूकंप लोगों के खाने- कमाने के नए रास्ते हैं. उत्तराखंड के लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं कि इस 1000 करोड़ रुपये में से कम से कम 400 करोड़ रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगे. इसका मतलब यह हुआ कि इस बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वह और भी ख़तरनाक होगा और एक भी बाढ़ या हल्के से पानी को झेल नहीं पाएगा. वहां के लोग राहत कार्यों की निगरानी और नए निर्माण की ज़िम्मेदारी सेना के हाथों सौंपना चाहते हैं. उन्हें लगता है कि अगर सेना इसे बनाएगी, तो शायद ज़्यादा सही बनाएगी, बनिस्बत कि सिविलियन कंस्ट्रक्शन कंपनीज अगर इसमें शामिल होती हैं, तो भ्रष्टाचार का ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाता है. लोगों के मन की यह आस्था ईश्वर करे, बनी रहे. कम से कम सेना पर तो लोगों का विश्वास अभी है. हालांकि सेना से भी अब बड़े भ्रष्टाचार की ख़बरें चारों तरफ़ निकलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहां सबसे ज़्यादा देश को ध्यान में रखकर सोचने वाली अगर कोई एक इकाई है, तो वह भारत की सेना ही है.

पर्यावरणविद् जो भी कहते रहे हों, उन बातों पर हम अमल नहीं करते, क्योंकि उनकी चेतावनियों को तो हमने न सुनने का फ़ैसला कर लिया है. दरअसल, पर्यावरण हमारे यहां प्राथमिकता पर कभी रहा ही नहीं. पर्यावरण को लेकर लोगों में कभी आस्था जगी ही नहीं. गंगा या अलकनंदा भागीरथी जैसी नदियों को हमने निजी कंपनियों को सौंप दिया है. उन कंपनियों की गंदगी इन नदियों में मिलती है. वे कंपनियां छोटे-बड़े बांध का निर्माण या अवैध कंस्ट्रक्शन करती हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण को घनघोर नुक़सान होता है. लेकिन जो भी पर्यावरण के नाम पर आवाज़ उठाता है, या तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, या फिर मार दिया जाता है. शायद उत्तराखंड की सरकार यह चाहती है कि वहां के लोग अपने हाथ में क़ानून ले लें और अफवाह के आधार पर हिंसा करें.

टेलीविजन पर दिखने वाली ख़बरें बताती हैं या चित्र बताते हैं कि उत्तराखंड के अधिकारियों के चेहरों पर कहीं से भी दर्द और तकलीफ नज़र नहीं आती. वे लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी आपदा के दौरान सिर्फ़ रिपोर्ट भेजते देखा गया. सेना ने आगे बढ़कर काम किया और इसीलिए सेना के जवानों की जानें भी गईं. उत्तराखंड की सरकार को और प्रकारांतर से कहें कि देश की सरकारों को क्या अब भी यह समझ में आएगा कि लोगों की ज़िंदगी से खेलने का शौक कितना ख़तरनाक है! हज़ारों लोगों की मौत, करोड़ों-अरबों का नुक़सान और वह भी सिर्फ़ इसलिए, क्योंकि सरकारें या सरकार में शामिल अधिकारी और कहीं कहीं पर मंत्री, आपदा के बाद की सहायता राशि में कितना घपला करना है, यह पहले से ही तय कर चुके होते हैं. अफसर जो भ्रष्टाचार करते हैं, उनमें सरकारी अधिकारियों के नाम भी आते हैं, एनजीओ के नाम भी आते हैं, कुछ अख़बारों के नाम भी आते हैं, जो आपदा राहत के नाम पर सहायता मांगकर एक तरफ़ अपनी पीठ थपथपाते हैं और दूसरी तरफ़ इनकम टैक्स में भारी छूट तो ले लेते हैं, लेकिन कहां खर्च करते हैं, पता ही नहीं चलता.

उत्तराखंड की आपदा को प्रधानमंत्री ने इन पंक्तियों के लिखे जाने तक राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया. लोग अपनी तरफ़ से मदद लेकर उत्तराखंड जा रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी मदद, मंत्रियों या मुख्यमंत्रियों को छोड़कर, सरकारी आपदा कोष, मुख्यमंत्री कोष या प्रधानमंत्री आपदा कोष में नहीं दे रहा. पहले किसी भी राष्ट्रीय आपदा के समय लोग आगे बढ़-चढ़कर इन कोषों में अपना योगदान करते थे. सरकारों की ख़त्म होती साख का यह ज्वलंत उदाहरण है. इस आपदा के समय आम लोग नहीं खड़े हो रहे हैं. शायद जनता खुद को असहाय मान रही है और यह मान रही है कि यह सरकार का काम है.

वास्तविकता यह है कि उत्तराखंड के लोग हमारे अपने लोग हैं, ग़रीब लोग हैं. वे पहाड़ से उतर कर मैदान में जीविका के लिए आते हैं. गांव में उनकी पत्नी, छोटे बच्चे, बूढ़े मां-बाप रह जाते हैं और इन्हीं सारे लोगों ने इस ख़तरे को झेला है और अपनी जानें दी हैं. इन लोगों के लिए क्या देश के लोग नहीं खड़े होंगे? केंद्र सरकार या राज्य सरकारें न खड़ी हों, पर लोगों को तो इसके लिए खड़ा होना चाहिए. ये आरोप लगेंगे कि सहायता में कुछ लोगों ने कहीं भ्रष्टाचार कर लिया. कुछ लोगों के पास कहीं से पैसा आया, उन्होंने उसमें से थोड़ा-सा खा लिया, लेकिन जब लोग खड़े होंगे, तो ज़्यादातर लोगों की सहायता उत्तराखंड पहुंचेगी. उत्तराखंड में सहायता जानी ही चाहिए, छोटी हो या बड़ी, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की सहायता जानी चाहिए. और मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तान के लोग इस विपत्ति में उत्तराखंड के भाइयों एवं बहनों के साथ खड़े होंगे और कम से कम उन लोगों को यह एहसास कराएंगे कि वे भी इस देश के सम्मानित नागरिक हैं. और ऐसे में, हमें यह साबित करने का मौक़ा मिलेगा कि देश में कहीं भी प्राकृतिक विपदा आए, हम एक भारतीय के नाते हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति की तकलीफ में उसके साथ हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

वाजिब दाम-नीति का सवाल

ठाकुरदास बंग feedback@chauthiduniya.com

सरकार कृषि के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार करती है. सरकार आज नगरों में नए उद्योगों को बिजली रियायती दर पर देती है. औद्योगीकरण जारी रहे, इसलिए सरकार कुछ पुराने उद्योगों के लिए भी यह सुविधा प्रदान करती है, जैसे हिंडालको कंपनी रेणुकूट को कई वर्षों तक 2 पैसे प्रति यूनिट के भाव से बिजली दी जाती रही, जिसे कुछ दिनों पहले 10 पैसे किया गया, जबकि सामान्य उपभोक्ता के लिए बिजली की दर 35 से 40 पैसे प्रति यूनिट है. बिड़ला पेपर मिल को लगने वाला बांस दो पैसे में एक दिया जाता है, जबकि उसी बांस की क़ीमत बाज़ार में 2 रुपये है. बिजली मिले या न मिले, किसानों को 20 रुपये प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से मासिक खर्च मोटर पर उत्तर प्रदेश में देना पड़ता है. ऐसा अंधेर चलता रहता है और किसान उसे सहन करते रहते हैं. नगरों में बने माल के निर्यात को सरकार प्रोत्साहन देती है, जबकि कृषि के माल के निर्यात पर पाबंदी लगाई जाती है. लगातार चलने वाले इस शोषण के विरुद्ध समय-समय पर देश के कई प्रदेशों में 19वीं सदी में बलवे भी हुए, जो दमनपूर्वक दबा दिए गए. देश में किसान सभाएं बनीं, उन्होंने छोटी-छोटी मांगों को लेकर आंदोलन किए और सरकार से छोटी-मोटी सहूलियतें भी मांगीं.

राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव घोषणा-पत्रों में किसानों की सुविधाओं का तो जिक्र किया है, लेकिन किसानों को वाजिब दाम मिले, इसका उनमें उल्लेख नहीं रहता है. स्वराज के बाद सभी दलों की सरकारें पिछले 35 वर्षों में बनी हैं, लेकिन किसी दल की सरकार ने किसानों की वाजिब मांगें पूरी करने के बारे में नहीं सोचा. कांग्रेस अधिक समय तक केंद्र और राज्यों में शासन करती रही. हमने देखा कि उसने यह नीति अपनाई कि देश के

औद्योगीकरण के लिए कच्चा माल और अनाज सस्ता मिले. जनता पार्टी दो-ढाई साल शासन करती रही, लेकिन उसने भी वाजिब दाम-नीति के संबंध में कोई ठोस क़दम नहीं उठाए. देश के एक भाग में चरण सिंह किसानों के नेता माने जाते हैं और वह अपने दल, यानी लोकदल के अध्यक्ष भी हैं. वह जब प्रधानमंत्री थे, तब, यानी वर्ष 1979 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना मिट्टी के भाव बिका. गन्ना तोड़ने और उसे फैक्ट्री तक पहुंचाने का खर्च भी नहीं निकल सके, इतना उसका दाम हो गया. गन्ने का भाव इतना गिर गया कि उसकी खोई का मूल्य एक बार बाज़ार में उससे ज़्यादा था, यानी सरकार किसी भी दल की रहे, इस बारे में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है.

अत: किसानों एवं मज़दूरों को एकत्र होकर इस मांग के लिए आंदोलन करना पड़ेगा. केवल ज्ञापन देने या सभा करके प्रस्ताव पास करने से यह काम होने वाला नहीं है. ऐसा नहीं है कि सरकार अज्ञान के कारण किसानों, यानी ग्रामीण समाज के साथ इस मामले में अन्याय कर रही है. सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो समझ-बूझकर ग्रामीणों के शोषण की नीति तथाकथित देशहित में अपनाए हुए हैं, उन्हें जगाने और न्याय करने को विवश करने के लिए जनमत का दबाव पैदा होना चाहिए. अत: भारत को इकट्ठा और संगठित होकर इंडिया के विरुद्ध न्याय मिलने तक शांतिपूर्ण संघर्ष करना होगा. इंडिया, यानी जिस व्यवस्था या जिन लोगों ने अंग्रेजों का आर्थिक (यानी शोषण का) एवं सांस्कृतिक उत्तराधिकार पाया है, उन्हें श्री शरद जोशी इंडिया कहते हैं, बाकी सब भारतीय हैं. अत: भारत, यानी गांव के किसान, मज़दूर, कारीगर, सिपाही एवं ग्राहकों का बड़ा हिस्सा.

जन-आंदोलन के अलावा दूसरा कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है. अगर भारत की ग़रीबी मिटानी है, तो ग्रामीणों की ग़रीबी मिटनी चाहिए और उत्पादन बढ़ाने की तमन्ना देश भर में पैदा होनी चाहिए. वाजिब दाम-नीति के बिना किसानों-मज़दूरों में उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा कैसे पैदा होगी? कौन घाटे में लगातार अपना धंधा करता रहेगा? अत: राष्ट्र की ग़रीबी हटाने के लिए वाजिब दाम-नीति पहला अनिवार्य क़दम है. वास्तव में, इसके लिए सरकार को कुछ भी खास करने की ज़रूरत नहीं है. वाजिब दाम न मिले, इसलिए सरकार ने जो पाबंदियां लगाई या नीतियां गढ़ी हैं, उन्हें वह बंद कर दे. केवल इतना ही काम उसे करना है. किसान अपनी अंगभूत शक्ति, यानी संगठन के बल पर वाजिब दाम प्राप्त कर लेगा. इससे गांव का दारिद्रय मिटाने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि फिर किसान सिंचाई एवं कृषि-सुधार आदि जैसे कई काम करेगा. आज खेती घाटे का सौदा होने के कारण किसान को कृषि-विकास की कोई प्रेरणा नहीं है. अत: किसानों के वाजिब दाम का प्रश्न भारत के दारिद्रय-निवारण की मुख्य चाबी है. ■

संविधान में राजनीतिक दल का जिक्र नहीं है

राजनीतिक दलों की राय का औचित्य

डॉ. बी आर अंबेडकर

जब संविधान बन गया, तो कुछ राजनीतिक दलों ने उसकी व्यवस्थाओं एवं प्रावधानों को लेकर संविधान सभा पर कुछ सवाल भी उठाए, लेकिन डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने धारदार तर्कों से उन तमाम सवालों को सिरे से खारिज कर दिया.

भाग-3

मैं संविधान पर किसी भी आलोचना को चुनौती देता हूं कि दुनिया की कोई भी संविधान सभा इस बात को साबित करके दिखाए कि वह संविधान में संशोधन के ऐसे आसान तरीके बता सकती है. जो लोग इस संविधान से असंतुष्ट हैं, उन्हें दो तिहाई बहुमत जुटाना होगा और अगर वे दो तिहाई बहुमत संसद में अपने पक्ष में नहीं जुटा सकते, तो उनके मतों को जनता खुद ही नकार देगी.

संविधान की निंदा करने वालों में दो पार्टियां प्रमुख हैं, पहली कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी सोशलिस्ट पार्टी. आख़िर ये पार्टियां संविधान की निंदा क्यों कर रही हैं? क्या वास्तव में यह एक घटिया संविधान है? इस पर मेरा जवाब होगा, नहीं. कम्युनिस्ट पार्टी चाहती थी कि संविधान सामान्य लोगों के तानाशाही सिद्धांतों के आधार पर बने. उसने संविधान की निंदा इसलिए की, क्योंकि यह संविधान संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है. सोशलिस्टों की दो इच्छाएं थीं. पहली यह कि वे चाहते थे कि जब वे सत्ता में आएं, तो संविधान उन्हें इस बात की स्वतंत्रता दे कि वे लोगों की निजी संपत्तियां बिना हर्जाना दिए ही राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दें. सोशलिस्ट दूसरी चीज यह चाहते थे कि संविधान में मूल अधिकारों की कोई सीमा तय न की जाए, ताकि जब वे सत्ता में न आएं, तो उन पर किसी तरह की कोई रोक न हो और वे एक तरह से निरंकुश जैसा व्यवहार करें. वे जो भी करें, उसकी तनिक भी आलोचना न हो और इस तरह से राज्य की हार भी हो जाए.

ये मुख्य कारण हैं, जिनके चलते लोग संविधान की निंदा कर रहे हैं. मैं यह नहीं कहना चाहता कि संसदीय लोकतंत्र का सिद्धांत ही राजनीतिक लोकतंत्र का सबसे बेहतर रूप है. मैं यह नहीं कहना चाहता कि बिना हर्जाने के निजी संपत्तियों के अधिग्रहण का सिद्धांत जायज है. मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि मूल अधिकार कभी भी अपनी पूर्णता में सही नहीं हो सकते और उनकी सीमाओं में बदलाव नहीं लाया जा सकता. मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने संविधान में जो सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, वे आज की पीढ़ी के विचार हैं या अगर आप मेरे इन विचारों को बढ़-चढ़कर मानते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि ये संविधान सभा के सदस्यों के विचार हैं. आप प्रारूप समिति को ये चीजें संविधान में प्रस्तुत करने के लिए क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? आप संविधान सभा के एक सदस्य को भी क्यों दोषी ठहरा रहे हैं?

जेफरसन ने अमेरिकी संविधान के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने संविधान बनाने वालों के लिए बहुत ही उम्दा विचार रखे हैं, जिन्हें खारिज करना आसान नहीं है. उन्होंने एक जगह कहा है कि हम हर पीढ़ी को उनके अधिकारों एवं बहुसंख्यकों की इच्छा के आधार पर एक सूत्र में बांध सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे देश के निवासियों को हम एक सूत्र में नहीं बांध सकते. दूसरी जगह उन्होंने कहा कि वह सुझाव, जिस पर कोई संस्थान राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित हुआ हो, उसे न तो बदला जा सकता है और न ही उसे आधुनिक बनाया जा सकता है. मैं यहां कहना चाहूंगा कि जेफरसन ने जो कहा, उसमें थोड़ी-सी नहीं, बल्कि पूरी सत्यता है. इसलिए इस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता. क्या जेफरसन द्वारा रखे गए सिद्धांतों से संविधान सभा पीछे हट सकती है? यह

निश्चित रूप से आरोप के लायक ही नहीं, बल्कि निंदा के भी लायक है. कोई संविधान में संशोधन से जुड़े नियमों की जांच करता है? संविधान सभा ने संविधान पर अंतिम रूप से मुहर लगाने के लिए सिर्फ़ रोका ही नहीं, जैसा कि कनाडा में हुआ, बल्कि संविधान में संशोधन का बहुत ही सरल तरीका भी सुझाया.

मैं संविधान पर किसी भी आलोचना को चुनौती देता हूं कि दुनिया की कोई भी संविधान सभा इस बात को साबित करके दिखाए कि वह संविधान में संशोधन के ऐसे आसान तरीके बता सकती है. जो लोग इस संविधान से असंतुष्ट हैं, उन्हें दो तिहाई बहुमत जुटाना होगा और अगर वे दो तिहाई बहुमत संसद में अपने पक्ष में नहीं जुटा सकते, तो उनके मतों को जनता खुद ही नकार देगी. हमने विदेशों से संविधान की बहुत सारी चीजें आत्मसात कीं. इनमें सिर्फ़ एक बात महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में मैंने बताया है. एक गंभीर सवाल यह उठाया गया है कि यह बहुत ही केंद्रीयकृत है और राज्य ने नगरपालिका की शक्तियां कम कर दी हैं. यह साफ़ है कि यह विचार सिर्फ़ अतिशयोक्ति ही नहीं है, बल्कि यह गलतफहमी भी पैदा करता है कि आख़िर संविधान क्या उपाय करना चाहता है. केंद्र और राज्य के रिश्तों को देखा जाए, तो यह ज़रूरी हो जाता है कि आधारभूत सिद्धांत को ध्यान में रखा जाए. संघवाद का आधारभूत सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक और प्रबंधकीय अधिकारों का बंटवारा होता है. यह बंटवारा केंद्र के नियम के आधार पर नहीं होता, बल्कि संविधान के नियमों के तहत होता है.

राज्य हमारे संविधान के अंदर है, जो अपनी वैधानिक और प्रबंधकीय शक्तियों के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं करता. केंद्र और राज्य इस मुद्दे पर समान हैं. इसे देखकर यह कठिन लगता है कि संविधान को केंद्रीयकृत कैसे कहा जाता है. इसका मतलब है कि संविधान केंद्र को बहुत बड़ा क्षेत्र, वैधानिक एवं प्रबंधकीय शक्तियां देता है, जो किसी भी संघ संविधान में नहीं मिलता है. संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सिर्फ़ केंद्र को दी गई हैं, न कि राज्यों को, लेकिन ये विशेषताएं संघवाद के लक्षण नहीं बतातीं. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि संघवाद की मुख्य पहचान वैधानिक एवं प्रबंधकीय अधिकारों का केंद्र और संविधान द्वारा गठित इकाइयों के बीच बंटवारा है. हमारे संविधान की यह प्रमुख विशेषता है. इस बारे में कोई गलती नहीं की गई है, इसलिए यह गलत है कि राज्यों को केंद्र के अंदर रखा गया है. न तो केंद्र अपनी इच्छानुसार इस बंटवारे का अतिक्रमण कर सकता है और न ही न्यायपालिका. इस बारे में किसी ने ठीक ही कहा है, न्यायालय इसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन वे इसे हटा नहीं सकते. वे संशोधन कर सकते हैं, नए तथ्य दे सकते हैं, नए बिंदु प्रस्तुत कर सकते हैं और कुछ मामलों में बीच की रेखा खींच सकते हैं, लेकिन यहां भी एक बाध्यता है, क्योंकि वे इसे पारित नहीं कर सकते. वे मौजूद शक्तियों के बेहतर निर्माण में सुझाव दे सकते हैं, लेकिन किसी एक इकाई को इसके लिए अधिकृत नहीं कर सकते कि वह पूरी शक्ति किसी दूसरे को दे दे. ■

(अगले अंक में आप केंद्र और राज्य की शक्तियों के विवाद के बारे में पढ़ेंगे.)

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

ज़्यादातर नेता दुराचारी, भ्रष्ट और देशद्रोही हैं

काफी संघर्ष के बाद भारत को विदेशी गुलामी से निजात मिली. तत्कालीन नेताओं ने आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर लोकतांत्रिक सरकार की परंपरा को संवैधानिक दर्जा दिया. आज भी आम आदमी द्वारा सरकार चुनी जाती है, पर कई वर्षों से चले आ रहे घोटालों और अनैतिक ख़बरों से मन यह सोचने लगा है कि क्या अब यह प्रक्रिया सही है? चुनाव से पूर्व हलफनामे में दर्शाई गई संपत्ति, आश्चर्य की बात तो यह है कि चुनाव जीतने के कुछ वर्षों बाद ही पांच से दस गुनी हो जाती है. अब यदि लोकतांत्रिक सरकार में योजनाओं का गला घोंटा जाए और सदनों में शोर-शराबा मचाकर वेतन एवं भत्तों का भोग चढ़ाने में नेतागण मस्त रहें, तो इस देश का कल्याण कैसे होगा, यह सोचने वाली बात है. वार्ड, पंचायत, निगम आदि छोटे चुनावों में विजयी प्रत्याशी भी कुछ महीनों में ही महंगी गाड़ी, बंगले और अन्य अचल संपत्ति के स्वामी हो जाते हैं. सांसदों एवं विधायकों की तो बात ही न करें, तो ज़्यादा अच्छा है. हर दिन या हर सप्ताह किसी न किसी घोटाले की ख़बर सामने आ ही जाती है और मंत्रिगण सपरिवार उसमें लिप्त पाए जा रहे हैं. हैरानी की बात तो यह है कि जिस संविधान की साख को बचाने की कसम खाकर वे अपने पद पर आसीन होते हैं, उसी की धज्जियां उड़ाने में वक्त नहीं लगाते. इन दुराचारी एवं भ्रष्ट देशद्रोही नेताओं के कारण लोकसेवक कहलाने वाले प्रशासनिक अधिकारीगण भी भ्रष्टाचार की बहती गंगा में हाथ धोने से नहीं कतराते हैं और वे भी सिद्धहस्त हो जाते हैं. देश में इतनी समस्याएं हैं, पर निदान का दायित्व जिनके कंधों पर है, अगर वही अपना काम निष्ठापूर्वक न करें, तो स्थिति भगवान भरोसे ही रहेगी. दरअसल, आज ऐसा ही हो रहा है. बेलगामों की फौज खड़ी हो गई है. देश की आम जनता शंका और अव्यवस्था का दंश झेल रही है. किससे कहें, कहां कहें, स्पष्ट नहीं है और कहें, तो वे सुनेंगे भी कि नहीं, यह एक बड़ा सवाल है.

-विकास पाटनी, झुमरी तिलैया, झारखंड.

ज़्यादा भ्रष्ट है भाजपा

हां, यह सच है कि कांग्रेस से ज़्यादा भ्रष्ट है भाजपा. संतोष भारतीय ने ठीक ही लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब कई गुट बन गए हैं. पहला गुट आडवाणी का है, दूसरा नरेंद्र मोदी का और तीसरा है राजनाथ सिंह का. अभी राजनाथ सिंह बाहर रहकर अपने सियासी दांव-पेंच खेल रहे हैं. दरअसल, वह सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं. लेखक ने जिस तरह से भाजपा की पोल खोलकर रख दी है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि उन्हें भाजपा के बारे में अच्छी जानकारी है. संगठन के अंदरखाने जिस तरह से उठापटक चल रही है, वह सचमुच चिंतनीय है.

-निर्भय कुमार, दिल्ली.

क्या आडवाणी की ख्वाहिश पूरी होगी?

आडवाणी ने अपना इस्तीफ़ा देकर यह साबित कर दिया है कि वह आज भी राजनीति में एक सिद्धहस्त पुरुष हैं, लेकिन उनके इस क़दम से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वह खुद अपनी ही पार्टी की लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं. अब यदि इसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहा जाए, तो मुझे लगता है कि वह गलत नहीं होगा. मोदी का खौफ केवल भ्रष्ट भाजपा नेताओं को ही नहीं है, बल्कि आजम खान जैसे कद्दावर नेता भी उनसे डरे हुए हैं कि अब मुसलमानों का क्या होगा और कांग्रेसियों को तो जैसे सांप सूंघ गया है. आडवाणी के रुख से लगता है कि वह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उनकी यह ख्वाहिश पूरी होगी?

-दिलावर सिंह, मोतिहारी, बिहार.

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएँ इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

पोलैंड में एक घर की सफाई के दौरान वहां रखी द्वितीय विश्वयुद्ध के समय की विमान भेदी मिसाइल फट गई.

सूचना का अधिकार — जीने का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

आपके पत्र, सवाल और समाधान

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

किसी लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के कई फ़ायदे हैं. इस व्यवस्था की अपनी कुछ समस्याएं भी हैं, लेकिन उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समस्या है, तो समाधान भी है. इधर कुछ दिनों में हमें अपने पाठकों के ढेर सारे पत्र मिले हैं, जो इस बात के सबूत हैं कि हमारे पाठक न सिर्फ़ आरटीआई क़ानून का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वे अपनी समस्याओं का समाधान भी इस क़ानून के जरिए चाहते हैं. इसके अलावा, आरटीआई क़ानून से जुड़े अनुभव भी उन्होंने हमसे बांटे हैं. इस अंक में हम उन्हीं पत्रों को प्रकाशित कर रहे हैं और इसके पीछे हमारा मकसद अपने सभी पाठकों को विभिन्न तरह की समस्याओं और उनके समाधान से रूबरू कराना है. उम्मीद है कि इस अंक में प्रकाशित पत्रों को पढ़कर हमारे पाठकगण लाभांवित होंगे.

पीआईओ ने आवेदन रद्द कर दिया

कभी-कभी जनसूचना अधिकारी आवेदन को रद्द करके भेज देते हैं, ऐसी स्थिति में आवेदनकर्ता को क्या करना चाहिए? मैंने कानपुर के चीफ पोस्ट मास्टर के पास अपना एक आरटीआई आवेदन भेजा था, जिसके साथ सूचना शुल्क के तौर पर मनीऑर्डर भी संलग्न था, लेकिन मेरा आवेदन रद्द कर दिया गया. ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए?

-प्रो. ललित एम. त्रिपाठी, शिवली, *कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश.*

कई बार सूचना शुल्क किस स्वरूप में देना है, कितना देना है और किसके नाम से भुगतान करना है, आदि वजहों से सूचना अधिकारी आवेदन वापस कर देते हैं. आप केंद्र सरकार की आरटीआई नियमावली के तहत तय शुल्क, तय प्रारूप में भेजें. चूंकि डाक विभाग केंद्र सरकार के तहत आता है, इसलिए यदि इसके बाद भी आवेदन रद्द किया जाता है, तो आप उक्त जन-सूचना अधिकारी के ख़िलाफ़ शिकायत सीधे केंद्रीय सूचना आयोग में दर्ज करा सकते हैं.

आरटीआई पर सरकारी तंत्र हावी है

मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूं. मैंने कई विभागों में आरटीआई आवेदन दिए हैं और सरकारी विभागों में चल रहे गोरखधंधे के बारे में जनता दरबार और जिलाधिकारी के यहां शिकायतें भी की हैं. यह क़ानून पहले आमजन के लिए था, लेकिन अब इस पर भी सरकारी तंत्र हावी हो चुका है.

-दारोगा सिंह, *तुरकौलिया, पूर्वी चंपारण, बिहार.*

आपका कहना बहुत हद तक सही है, लेकिन यह भी याद रखें कि इस क़ानून ने बहुत से नए प्रतिमान भी स्थापित किए हैं. आपके कई मामले हैं, उनके संबंध में हमारा सुझाव यह है कि अगर आप व्यक्तिगत मामले में आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो सवालों के चयन में समझदारी दिखाएं, यानी सटीक और कम सवाल करें. अनुमानों पर आधारित सवाल न करें. जवाब न मिलने की सूरत में मामले को क़ानून के तहत प्रथम अपील और द्वितीय अपील तक ले जाने का प्रयास करें. यदि आप सार्वजनिक हित के संबंध में आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो यह कोशिश करें कि आपके साथ कुछ और लोग भी उस मुद्दे पर आरटीआई डालें. इससे दबाव बनता है और ऐसी स्थिति में कोई आपको धमकाने की कोशिश भी नहीं करेगा.

सूचना नहीं, धमकी मिल रही है

मैंने जिला पूर्ति अधिकारी जालौन के यहां आरटीआई डालकर कुछ सूचनाएं मांगी थीं. प्रथम अपील के बाद भी सूचना न मिलने पर मैं राज्य सूचना आयोग पहुंचा. आयोग की ओर से नि:शुल्क सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया. फिर भी मुझे अब तक सूचना नहीं मिली, उलटे धमकी दी जा रही है. क्या मैं आयोग से प्रतिपूर्ति धनराशि 25 हज़ार रुपये दिलवाने की मांग कर सकता हूं?

-मुहम्मद अयूब अंसारी, *उरई-जालौन, उत्तर प्रदेश.*

आप आयोग से मुआवज़े की मांग कर सकते हैं, जो कि आपको मिल सकता है. सूचना न देने की वजह से जन सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि सरकारी खजाने में जमा होता है. जुर्माना लगाने का अधिकार आयोग को है. वह चाहे, तो लगा सकता है. यदि आपको धमकी मिल रही है, तो आप इसकी एक शिकायत आयोग में कर सकते हैं.

RIGHT TO INFORMATION

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है:

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

रेलवे में भ्रष्टाचार से संबंधित सवाल

मैंने 24 मई, 2005 की एक प्रतीक्षा सूची के टिकट की धन-वापसी के लिए उत्तर-पश्चिम रेलवे में आरटीआई डाला था, लेकिन मुझसे कहा गया कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए जानकारी नहीं दी जा सकती. अब मुझे क्या करना चाहिए?

-एस आर शर्मा, *हुगली, पश्चिम बंगाल.*

यदि आप इस मामले में केंद्रीय सूचना आयोग नहीं गए हैं, तो इस मामले की शिकायत वहां कर सकते हैं.

सूचना नहीं मिली

मैं एक मामले में मंडल कारागार दरभंगा में बंद हूं. मैं खुद को निर्दोष मानता हूं और चाहता हूं कि इस मामले की जांच सीबीआई करे, ताकि सच सामने आए. इस बाबत मैं जेल में अनशन भी कर चुका हूं. इस संबंध में मैंने मानवाधिकार आयोग पटना में एक आवेदन दिया था. बाद में मैंने आवेदन पर हुई कार्रवाई के संबंध में एक आरटीआई भी डाला, जिसका कोई जवाब नहीं मिला. उलटे पुलिस वाले मेरे घर पर जाकर मेरी मां को धमकी दे आए कि अगर मैंने पुलिस के ख़िलाफ़ शिकायत करना बंद नहीं किया, तो अंजाम बुरा होगा. मैंने इस मामले में बिहार के कई अख़बारों को भी लिखा, लेकिन किसी ने भी इसे नहीं छापा.

-शिवमणि झा, *दरभंगा, बिहार.*

आपके पत्र से हम आपके दोषी या निर्दोष होने की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि सूचना क़ानून का इस्तेमाल करते हुए आपने जिस सूचना की मांग की थी, वह आपको नहीं मिली. इस मामले में आपको राज्य सूचना आयोग में अपील करनी चाहिए, ताकि वांछित सूचना मिल सके. ■

ज़रा हट के

17000 डॉलर में सच्चा प्यार

प्यार बिकता है, आपने यह स्लोगन कहीं पढ़ा है? कहीं नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इसके पहले प्यार को बिकते हुए आपने कहीं देखा या सुना ही नहीं होगा. हां, हो सकता है कि आपने फिल्मों में देखा हो. अगर आपको कोई यह बताए कि आपको अपना सच्चा प्रेम पाने के लिए कितनी कीमत खर्च करनी पड़ती है, तो आपको इस पर विश्वास ही नहीं होगा. इंग्लैंड में हुए एक ताजा सर्वे के अनुसार, सच्चा प्रेम पाने के लिए एक ब्रिटिश नागरिक को औसतन 17,238 डॉलर खर्च करने पड़ते हैं. इंग्लैंड के समाचार पत्र डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड की सबसे बड़ी कैशबैक वेबसाइट क्विडको डॉट कॉम द्वारा 2,000 लोगों पर करवाए गए एक ताजा अध्ययन में पाया गया कि वे सच्चे प्रेम की तलाश में 13 लोगों के साथ डेट पर गए और उन्होंने 11 बार डिनर किया. पहली डेट पर 100 पाउंड से भी अधिक खर्च करने के बावजूद इनमें से सात बार की गई डेटिंग बहुत बुरी साबित रही है.

सर्वे में शामिल अधिकांश लोगों ने स्वीकार किया कि एक बार रिश्ते में खटास आ जाने के बाद अपने विवाह के लिए इस तरह की डेटिंग पर खर्च को बचाने को तरजीह देनी चाहिए. अध्ययन के अनुसार, प्रेम में गिरफ्त युवक का पहला साल काफी महंगा साबित होता है, जिसमें प्रेमी युगल औसतन 3,629 पौंड खर्च करते हैं. जैसे-जैसे प्रेमी युगल सेटल होने लगते हैं, वे एक-दूसरे पर प्रेम प्रकट करने में खर्च में कटौती करने लगते हैं और अगले ही साल इस खर्च में 1,000 पौंड तक की गिरावट आ जाती है. अंतत: जैसे ही प्रेमी युगल विवाह करने का निश्चय कर लेते हैं, इस खर्च में फिर से कमी आती है. सर्वे के अनुसार, पहली बार प्रेम में पड़ने के बाद विवाह के दिन तक प्रेमी युगल औसतन प्रत्येक डेट पर 120 पौंड खर्च कर ही देते हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

घर में रखता था शेर, चीता और बंदर

आप अगर किसी के घर जाएं और दरवाजा खोलते ही आपका सामना शेर जैसे खतरनाक जानवर से हो जाए, तब आप क्या करेंगे? यकीनन आपकी तो जान ही निकल जाएगी. एक आदमी ने अपने घर में जिस तरह से खतरनाक जानवरों को रखा था, उसे देखकर पहली बार में किसी की भी जान जा सकती थी. थाईलैंड की राजधानी बैंकाक के एक घर से 14 सफेद शेर, कई बंदर और एक चीता सहित 200 से ज्यादा जानवरों को छापा मारकर आजाद कराया गया है. वन्य जीवों के अवैध व्यापार के आरोप में शहर के प्रसिद्ध चातुचक बाजार के एक दुकानदार समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अगर आरोप साबित हो जाते हैं, तो उन्हें चार साल तक की कैद और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

पुलिस कर्नल इक इकरसरत ने बताया कि उन्हें पड़ोसियों से दुर्गंध की शिकायत मिली थी और इसके आधार पर छापेमारी की गई, तो मकान में कई जानवर मिले. उन्होंने बताया कि शेरों का आयात चिड़ियाघर में बेचने के नाम पर किया गया, लेकिन वह उन्हें निजी खरीदारों के हाथों बेच रहा था. ■

दादी-नानी की उम्र में मां बनीं

जरा सोचिए, आपकी शादी हो गई हो, बड़े-बड़े बच्चे हों, उन बच्चों के भी बच्चे हों और यदि इसके बाद आप बचानक मां बन जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हां, यह सोलह आने सच है. दरअसल, ऐसा ही हुआ है लीला बाई के साथ. लीला बाई मां बन चुकी हैं, जबकि उनके सिर के बाल सफेद हो चुके हैं और चेहरे पर झुर्रियां साफ साफ झलकती हैं. लीला बाई दादी बन चुकी हैं, लेकिन 60 साल उम्र की यह दादी एक बार फिर मां बन गई हैं. इसे चिकित्सक भी अचरज मान रहे हैं. वैसे, न केवल लीलाबाई स्वस्थ्य हैं, बल्कि उनकी संतान भी पूरी तरह स्वस्थ्य है. मध्य प्रदेश में इंदौर के सूमाखेड़ी में रहने वाली लीलाबाई की उम्र 60 साल है और उनकी तीन बेटियों में से दो की शादी भी हो चुकी है. इतना ही नहीं, वह नानी भी बन गई हैं. इसके बावजूद वह पिछले दिनों मां बन गई हैं. बताते हैं कि लीला बाई का पेट फूलने लगा, तो परिजनों को आशंका हुई कि उन्हें गैस की पीड़ा है. ऐसे में, उन्हें उपचार के लिए चिकित्सालय लाया गया. चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया, तो पता चला कि लीलाबाई गर्भवती हैं. लीला बाई ने एक लड़की को जन्म दिया है. जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. डॉक्टर कहते हैं कि आमतौर पर 40 से 50 साल आयु वर्ग की महिलाएं मुश्किल से मां बन पाती हैं. ऐसा इसलिए, क्योंकि अंडाणु बनने का क्रम रुक जाता है और 60 साल की उम्र में किसी महिला का मां बनना असंभव हो जाता है. इसके बावजूद लीला बाई मां बन गई हैं, यह अचरज की बात है. ■

द्वितीय विश्वयुद्ध की मिसाइल फटी, जान बची

जाको राखे साइयां, मार सके न कोय. यह कहावत पोलैंड के नागरिक पर ठीक बैठती है. जी हां, वह नागरिक गोली, तीर या डंडे से नहीं, मिसाइल से पूरी तरह से बच गई और अब खतरे से बाहर बताई जाती है. दरअसल, हुआ यह कि पोलैंड में एक घर की सफाई के दौरान वहां रखी द्वितीय विश्वयुद्ध के समय की विमान भेदी मिसाइल फट गई. इस हादसे में घर की मालकिन घायल हो गई. पुलिस ने बताया कि स्ट्रजिस्जो इलाके में हुई इस घटना में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है.

उन्होंने कहा कि पहले हमें ऐसा लगा, जैसे यह हादसा गैस सिलेंडर के फटने के कारण हुआ है, लेकिन जल्द ही पता चल गया कि इस महिला के किचन के कपबोर्ड के पीछे द्वितीय विश्वयुद्ध के समय की एक मिसाइल रखी हुई थी. उन्होंने बताया कि दरअसल, इस घर के मालिक को पिछले साल ही एक मिसाइल मिली थी और वह इसे घर ले आया था. ये दोनों सोचते थे कि यह मिसाइल अब निष्क्रिय है, लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी. ■

उड़ने वाली साइकिल

अब तक आपने हवाई जहाज या हेलिकॉप्टर को उड़ते हुए सुना होगा, लेकिन अगर आपको आकाश में कोई साइकिल उड़ती हुई दिखाई दे, तो आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा. आखिर विश्वास हो, तो क्यों हो. सवाल यह उठता है कि क्या कोई साइकिल भी उड़ सकती है, लेकिन यह हकीकत है. चेक गणराज्य की राजधानी पराग्वे में उड़ने वाली साइकिल को मीडिया और आम लोगों के बीच पेश किया गया. साइकिल को उड़ते देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे. ■

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल): अपने ज्ञान और पैसे का घमंड बिल्कुल न करें. इस सप्ताह आपकी अनुमानित शक्ति बढ़ी रहेगी और इस अनुमान से आप कुछ नया कार्य अच्छे से कर पाएंगे. दुश्मन इस सप्ताह आपसे दबे रहेंगे. आप दौड़-धूप भी ज्यादा करेंगे. कुछ ज्ञानी लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी. आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई): इस सप्ताह धार्मिक कार्यों में आपका रुझान रहेगा. आप सामाजिक कार्यों में ज्यादा समय व्यतीत करेंगे. मानसिक संतुलन बना कर चलें और अपना आपा न खोएं. व्यापारी अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश करेंगे. आप अपनी अचल संपत्ति को बढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान लगाएंगे. परिवार के लोग और आपके सहयोगी आपकी मदद करेंगे.

मिथुन (21 मई से 20 जून): यह सप्ताह आपके लिए परिवर्तन का सप्ताह होगा. पूर्व से चला आ रहा कोई लंबित कार्य पूर्ण होगा. पारिवारिक सहयोग पूरा मिलेगा और आप उत्साहित रहेंगे. इस सप्ताह आप लाभ कमाएंगे. वाहन सावधानी से चलाएं. नौकरीपेशा लोगों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई): यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है. धार्मिक कार्यों में काफी रुचि बढ़ेगी. आपका स्वास्थ्य भी कुल मिला कर अच्छा रहेगा. पारिवारिक सहयोग पूर्ण मिलेगा. नौकरीपेशा और व्यापारी दोनों उन्नति करेंगे. नई यात्रा का संयोग बन सकता है. भाई-बहनों के बीच संबंधों में थोड़ी कटुता का आभास होगा.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त): इस सप्ताह आप खान-पान पर नियंत्रण रखें. इसका बुरा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, अच्छे परिणाम मिलेंगे. कानूनी दांव-पेंच से बच कर चलें. माता-पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा. दांपत्य जीवन में मिठास बनाए रखें. नौकरीपेशा लोग उन्नति प्राप्त करेंगे.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर): यह सप्ताह आपके लिए परिवार के साथ घूमने और मौज करने का सप्ताह है. संपत्ति के क्रय का महत्तम योग है. वित्तीय रूप से आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे. व्यक्तिगत उन्नति का समय है, इसका भरपूर उपयोग करें. संतान से संबंधित किसी बात को लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है. स्वास्थ्य हलके उतार-चढ़ाव के साथ ठीक रहेगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर): इस सप्ताह आप किसी नये व्यवसाय के बारे में सोच सकते हैं. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और संतान सुख भी प्राप्त होगा. इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. नौकरी-पेशा लोग अपनी कार्यकुशलता की वजह से सम्मान प्राप्त करेंगे. कल्पना में खोने से बचें और अपनी कार्यशैली का प्रदर्शन करें.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर): इस सप्ताह आप भागदौड़ करने के लिए तैयार रहें. किसी की विरोधाभासी बातों से विचलित न हों. अपनी भावना का सम्मान करें और परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह अच्छे से करें. इस सप्ताह आप सामाजिक और सामूहिक उत्सव में हिस्सा लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. खासकर मौसमी बीमारी परेशानी का कारण बन सकती है.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर): इस सप्ताह आप अपनी भावना को ज्यादा महत्व देंगे. धन आपके लिए गौण रहेगा. सुनने पर ध्यान दें, ताकि आप अपनी बात ठीक से रख सकें. वाहन सावधानी से चलाएं. अपने चिड़चिड़े स्वभाव से बाज आएं. कर्ज देने से बचें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी): कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी संबंध में कोई कटुता न आए. विद्यार्थियों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. यह सप्ताह आपको अपनी योजना के अनुरूप चलने के लिए अच्छा रहेगा. दांपत्य जीवन में सुख का अनुभव करेंगे. अपने निवास पर कुछ नये कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे. अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखें.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी): इस सप्ताह पारिवारिक सदस्यों से सहयोग मिलेगा. काफी प्रयास के बाद किसी कार्य में सफलता मिलेगी. किसी भी तरह की साझेदारी से पहले मंथन जरूर करें. आप अपने वचन को पूर्णरूप से निभाएंगे. व्यापारी और नौकरी-पेशा वर्ग को आर्थिक लाभ मिलेगा. सरकारी विभाग में रुके कार्य संपन्न होंगे.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च): इस सप्ताह आपको मकान और जमीन-जायदाद के मामलों में लाभ होगा. पुराने रिश्तों को सुधारने का सफल प्रयास करेंगे. केवल खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आर्थिक दबाव महसूस करेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है. मनोरंजन के लिए आप समय निकाल पाएंगे.

cshekhar_3@hotmail.com

पश्चिमी देशों की ओर से आर्थिक पाबंदी की मार झेल रहा ईरान दुनिया से कट गया है, जबकि इस आधुनिक दौर में आर्थिक विकास के लिए सभी की ज़रूरतें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं.

भारत-सऊदी अरब

नितामक़ा ने बढ़ाई चिंता

50 हज़ार कामगार होंगे बेरोज़गार

सऊदी अरब सरकार ने निताक़ा नामक क़ानून बनाकर वहां कार्यरत विदेशी कामगारों की चिंता बढ़ा दी है. लगभग 50 हज़ार भारतीय कामगार इस क़ानून की चपेट में आ सकते हैं. और अगर ऐसा हुआ, तो यह दोनों देशों के हित में बिल्कुल नहीं होगा.

एक ऐसे समय में, जबकि रुपये एवं सोने की क़ीमतों में भारी गिरावट आ रही है और देश का आर्थिक ढांचा लगातार चरमरा रहा है, सऊदी अरब से 50 हज़ार भारतीय कामगारों की स्वदेश वापसी का मसला स्थिति को और गंभीर बना देता है. जहां तक सऊदी अरब में भारतीय कामगारों के निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक निवास और रोज़गार का सवाल है, तो उससे केवल भारत के हित ही जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि स्वयं सऊदी अरब के पक्ष में भी यही है कि वह विभिन्न स्तर के भारतीय कामगारों से लाभांवित होता रहे. यह केवल 50 हज़ार कामगारों की बात नहीं, बल्कि भारत-सऊदी अरब के रिश्तों की ज़मानत भी है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है. भारत के साथ अरबों का रिश्ता काफी पुराना है, लेकिन यह रिश्ता पहले कारोबारी स्तर तक ही सीमित था. पैग़ंबर मोहम्मद साहब के काल में ही उनके साथी समुद्री रास्ते से मालाबार, जो अब केरल कहलाता है, आने शुरू हो गए थे. उस दौर की निशानी के रूप में कोडंगलूर में वर्ष 629 में बनी चेरामान जुमा मस्जिद आज भी मौजूद है, जो कि एशिया एवं देश की प्रथम मस्जिद कहलाती है.

बहरहाल, भारत एवं सऊदी अरब के रिश्ते समय के साथ-साथ स्थिर होते गए. 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो विदेश नीति में सऊदी अरब को विशेष महत्व दिया गया और उसके साथ व्यापारिक संबंध अधिक मज़बूत किए गए. दोनों देशों के संबंध इतने घनिष्ठ हो गए कि सऊदी अरब के शाह सईद अब्दुल अज़ीज़ ने 1955 में भारत का 17 दिवसीय दौरा किया और उस दौरान उन्होंने भारत के कई शहरों का भ्रमण किया. उसी समय दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों पर समझौते हुए. उसके बाद 1956 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सऊदी अरब का दौरा किया और तब उन्हें मालब जेद्दा में एक बड़े जमावड़े को संबोधित करने का मौक़ा मिला. यह सम्मान इससे पहले किसी भी विदेशी नेता को नहीं मिला था, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान देकर दोनों देशों के रिश्ते ज़ाहिर किए गए. उसके बाद तो जैसे दोनों देशों के रिश्तों में पंख लग गए. ये रिश्ते न केवल व्यवसाय की हद तक सीमित रहे, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में भी मज़बूत होते चले गए. दोनों ओर से प्रतिनिधिमंडलों का आना-जाना शुरू हुआ. जनवरी 2006 में शाह अब्दुल अज़ीज़ को भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और फिर नवंबर 2010 में भारतीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने सऊदी अरब का दौरा किया, जहां उन्हें वहां की संसद को संबोधित करने का अवसर मिला, जो बड़े सम्मान की बात थी. मतलब यह कि प्राचीन काल से लेकर आज तक दोनों देशों के रिश्ते बहुत मज़बूत हैं.

भारत सऊदी अरब के साथ उस समय भी था, जब उसकी गिनती ग़रीब देशों में होती थी और वहां तेल की पैदावार आज जैसी नहीं थी और वही संबंध आज भी हैं, जबकि वह विकासशील देशों की कतार में शामिल है. 1973 में जिस समय वहां तेल की खोज हुई, उस समय सऊदी अरब के पास विशेषज्ञों की कमी थी. उसे ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता थी, जो उसकी अर्थव्यवस्था संभालने में सहारा दें, लिहाज़ा भारत ने अपने विशेषज्ञों एवं अन्य लोगों को बड़ी संख्या में भेजकर उसे अर्थव्यवस्था संभालने में बड़ी मदद की. यह सिलसिला तब से लेकर अब तक जारी रहा. हालांकि भारतीय कामगारों का सबसे बड़ा समूह सऊदी अरब में ही काम कर रहा है. इस समय सऊदी अरब के कुल 7.5 मिलियन विदेशी कर्मचारियों में से लगभग 2 मिलियन कर्मचारी भारतीय हैं, जो वहां के विभिन्न शहरों में विभिन्न पेशों से जुड़े हैं और सऊदी अरब के विकास के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. उनके द्वारा भारत आने वाला पैसा सालों से आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, बिहार एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था मज़बूत कर रहा है.

भारतीय कामगारों की एक बड़ी संख्या खाड़ी देशों में काम कर रही है और विभिन्न पेशों से जुड़ी हुई है. संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 18 लाख, कुवैत में 6.5 लाख, ओमान में 6 लाख, क़तर में 5 लाख, बहरीन में 5 लाख, इराक़ में 16 हज़ार, लिबनान में 10 हज़ार, इर्दन में 90 हज़ार, लीबिया में एक हज़ार कामगार भारतीय हैं, जो अपने देश को एक बड़ी रक़म भेजते हैं. विदेशों में रहने वाले भारतीय कामगारों ने पिछले साल लगभग 70 अरब डॉलर देश में भेजे, जिनमें से 20 अरब डॉलर केवल सऊदी अरब के मज़दूरों एवं हस्तशिल्प कारीगरों ने भेजे. ज़ाहिर है, यह विदेशी मुद्रा देश की अर्थव्यवस्था मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन इतने पैसे बाहर चले जाने से सऊदी अरब पर बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि अब वहां पहले की तरह काला सोना, यानी पेट्रोल का भंडार मौजूद नहीं है. पिछले साल रियाज़ के कई क्षेत्रों में पेट्रोल के कुएं सूख गए.

दूसरी ओर, स्थायी नागरिक भी अब न केवल शिक्षित हो रहे हैं, बल्कि वे काम भी करना चाहते हैं. स्थानीय लोगों में बेरोज़गारी बढ़ रही है, इसलिए सरकार अरब नागरिकों को रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना चाहती है और विदेशी कामगारों की संख्या घटाना चाहती है, ताकि जो मोटी धनराशि विदेशी कामगारों द्वारा बाहर जा रही है, वह देश में ही रहे और स्थानीय नौजवानों को रोज़गार मिले. इसके लिए उसने निताक़ा नामक एक नया क़ानून बनाया है, जिसके अनुसार, ऐसा कोई भी कर्मचारी या मज़दूर, जिसे अब तक किसी सऊदी का संरक्षण हासिल नहीं हुआ है और वह आज़ाद वीज़ा पर देश में रह रहा है, तो उसे ऐसे में, किसी सऊदी का संरक्षण हासिल करना होगा. जो लोग छोटा कारोबार कर रहे हैं, उन्हें 10 प्रतिशत कर्मचारी सऊदी रखने होंगे. जो विदेशी कामगार अक़ामा पर दर्ज काम के अलावा, कोई और काम कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपने काम का उल्लेख अक़ामा पर करना होगा और संबंधित काम तक ही सीमित रहना होगा. जिनके पास पासपोर्ट नहीं है और अवैध रूप से देश में रह रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द देश में निवास करने के लिए वैध तरीक़ा अपनाना होगा. अगर ऐसे लोग निर्धारित अवधि के अंदर ज़रूरी काग़ज़ात हासिल नहीं करते हैं, तो उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाएगा. अगर किसी संरक्षक, संस्था और कंपनी ने बिना ज़रूरी कागज़ातों के, ऐसे कर्मचारियों को अपने यहां काम दिया, तो उसे 1000 रियाल जुर्माना देना पड़ेगा.

इस नए क़ानून की भेंट 50 हज़ार से अधिक भारतीय कामगार चढ़ने जा रहे हैं. अगर उन्हें भारत वापस भेज दिया जाता है, तो न केवल यहां विदेशी मुद्रा की आवक में कमी होगी, बल्कि बेरोजगारों की इतनी बड़ी संख्या समस्याएं भी पैदा करेगी. हालांकि इस संदर्भ में भारत प्रयासरत है और विदेशी मंत्री सलमान ख़ुर्शीद वहां के विदेशी मंत्री फैसल से मुलाक़ात कर चुके हैं. उन्होंने कई अन्य मसलों पर भी बातचीत की, जिनमें क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के अलावा, ऊर्जा, सुरक्षा, आतंकवाद के ख़िलाफ़ आपसी सहयोग बढ़ाने और सीरिया-ईरान की मौजूदा परिस्थितियां आदि मुद्दे शामिल थे. उन्होंने ख़ास तौर पर कामगारों की समस्या पर चिंता जताई, जो निताक़ा क़ानून से पैदा हो रही है. सऊदी अरब के विदेशी मंत्री शहज़ाद सईद अल फैसल ने निताक़ा से संबंधित उनकी चिंताएं दूर करने की कोशिश की और कहा कि यह क़ानून भारतीय कामगारों के हित में है. इससे अब ग़ैर-क़ानूनी रूप से रह रहे लोगों को वैध रूप से दूसरे अन्य अच्छे रोज़गार तलाश करने का अवसर मिलेगा और जो लोग विकल्प नहीं ढूंढ पाएंगे, उन्हें अपने देश वापस जाना होगा.

बहरहाल, निताक़ा क़ानून ने भारत समेत कई देशों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है, क्योंकि स्वदेश लौटने वाले कामगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी. इस क़ानून से स्वयं सऊदी अरब भी कई समस्याओं से घिर सकता है, क्योंकि उसके पास आज भी दक्ष लोगों की कमी है. नई पीढ़ी में इतनी क्षमता नहीं है कि वह बड़ी तकनीकी ज़िम्मेदारियां पूरी तरह संभाल सके. ऐसे में अगर उस पर बड़ी ज़िम्मेदारियां डाली गईं, तो नुक़सान की आशंका अधिक रहेगी. दूसरी ओर नई पीढ़ी छोटे-मोटे काम करने के लिए मानसिक रूप से अभी तक तैयार नहीं है. अब अगर हर क्षेत्र में 10 प्रतिशत नौकरियां सऊदी नागरिकों के लिए अनिवार्य कर दी जाती हैं, तो समस्या यह पैदा होगी कि संस्थाएं एवं कंपनियां सऊदी नौजवानों को न तो तकनीकी ज़िम्मेदारी सौंपने का ख़तरा मोल लेंगी और न ही उन्हें निचले स्तर पर काम करने के लिए सऊदी नौजवान मिलेंगे. इससे न केवल संस्थाओं और कंपनियों का नुकसान होगा, बल्कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है. यही वजह है कि स्वयं सऊदी अरब का मीडिया भी निताक़ा क़ानून को संदेह की नज़र से देख रहा है. अगर सऊदी अरब इन समस्याओं से निजात पाना और अपने नागरिकों को रोजगार देना चाहता है, तो उसे कोई कारगर नीति बनानी चाहिए और भारत के पेशेवर लोगों, जो लंबे समय से उसकी अर्थव्यवस्था मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, की विशेषज्ञता से तब तक लाभांवित होते रहना चाहिए, जब तक कि उसके अपने नागरिक पूर्ण रूप से हर क्षेत्र में दक्ष न हो जाएं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ईरान

उम्मीदों पर कितने खरे उतरेंगे हसन रूहानी

वसीम अहमद
feedback@chauthiduniya.com

ईरान में 50 के दशक के बाद कई छोटी-बड़ी घटनाएं हुईं, लेकिन 1979 में ईमाम ख़ुमैनी के नेतृत्व में जो क्रांति हुई, वह ऐतिहासिक थी, जिसमें दो साल से क़ायम साम्राज्यवाद का तख्ता पलट गया. ईरान के शाह भाग निकले और ईमाम ख़ुमैनी अपना 16 वर्ष का निर्वासन पूरा करके ईरान वापस आए. उसके बाद जो क़ानून बना, उसके अनुसार, संपूर्ण अधिकार विलायते फ़कीह के पास होते हैं, जो देश का सर्वमान्य नेता होता है और सेना का कमांडर इन चीफ भी. ईमाम ख़ुमैनी सर्वप्रथम इस पद पर आसीन हुए और अब अली ख़ामनेई उनके उत्तराधिकारी हैं. यहां राष्ट्रपति प्रणाली भी है. उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम अबुल हसन बनी सदर देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए और उनके बाद अली अकबर हाशमी रसनजानी, सैयद मोहम्मद ख़ात्मी एवं अहमदी निजाद समेत कुछ लोगों ने यह पद संभाला. हाल में राष्ट्रपति पद का चुनाव संपन्न हुआ और हसन रूहानी ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए. हसन रूहानी की जीत ने नई आशाओं को जन्म दिया है. माना जा रहा है कि वह कुछ ऐसे क़दम उठाएंगे, जिनसे न केवल ईरान की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बल्कि दुनिया के अन्य देशों के साथ उसके संबंध भी मज़बूत होंगे. हालांकि इसके लिए उन्हें देश की विदेश नीति में भारी फेरबदल करके काफी सूझबूझ से काम लेना होगा, क्योंकि ईरान का क़ानून धार्मिक शिक्षा को ही अपने राजनीतिक एवं सामाजिक रिश्तों की बुनियाद बताता है. रूहानी को देश के प्रमुख नेता आयतुल्लाह ख़ामनाई का विश्वास जीतकर आगे बढ़ना होगा. उनकी सफलता को सिर्फ़ देश ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सकारात्मक दृष्टि से देखा रहा है. उनके विचार एवं पूर्व में दिए गए बयान बताते हैं कि वह एक उदारवादी नेता हैं और वैश्विक समुदाय उनसे यही आशा कर रहा है कि वह अपनी विदेश नीति में उदारवाद को बढ़ावा देंगे.

पश्चिमी देशों की ओर से आर्थिक पाबंदी की मार झेल रहा ईरान दुनिया से कट गया है, जबकि इस आधुनिक दौर में आर्थिक विकास के लिए सभी की ज़रूरतें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से जुड़े रहना किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ईरान सबसे अलग-थलग हो गया है. यह बात रूहानी चुनाव के दौरान स्वीकार भी कर चुके हैं. इसीलिए चुनाव जीतने के बाद तेहरान में उन्होंने

कहा कि अमेरिका के साथ 34 सालों से ख़राब रिश्तों को पुनर्स्थापित किया जाएगा. खाड़ी देशों, विशेषकर सऊदी अरब के साथ संबंध बहाल किए जाएंगे. हालांकि उन्होंने परमाणु संवर्धन के मामले में किसी कटौती से इंकार किया. ग़ौरतलब है कि अहमदी निजाद ने इस मसले पर कड़ा रुख़ अपनाया था, जिससे न केवल पश्चिमी देशों, बल्कि भारत जैसे मित्र देशों के साथ उसके संबंधों में खटास पैदा हो गई थी और सैयद मोहम्मद ख़ात्मी के दौर में भारत-ईरान के रिश्तों में जो गर्मजोशी थी, उसमें कमी आ गई थी. खैर, जनता हसन रूहानी को बहुत आशा भरी नज़रों से देख रही है.

क्या कहते हैं भारतीय मुस्लिम नेता

प्रकांड विद्वान एवं प्रसिद्ध शिया मुस्लिम नेता डॉ. कलबे सादिक कहते हैं कि ईरान में हुए चुनाव लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में उभर कर सामने आए हैं. उन्होंने कहा, यह कहना सही नहीं है कि रूहानी के राष्ट्रपति चुने जाने से इस्लाम के मूल सिद्धांतों में कोई बदलाव आएगा. ईरान की पश्चिमी देशों से 1979 से दूरियां चली आ रही हैं, उनमें निश्चित ही कमी आएगी और वैश्विक शक्तियों की ओर से आर्थिक पाबंदी एवं न्यूक्लियर जैसी समस्याओं के हल की संभावनाएं बढ़ेंगी. भारत से भी ईरान के संबंध रूहानी के शासनकाल में अधिक मज़बूत होंगे. जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अमीर मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने कहा कि जो कुछ मीडिया में उनके बारे में देखने-सुनने को मिल रहा है, उससे यही कहा जा सकता है कि वह उदारवादी हैं और सुधारवादी भी. आशा है कि वह पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध बनाते हुए देश को आर्थिक संकट से उबारेंगे और भारत-ईरान संबंधों को आगे बढ़ाएंगे. प्रसिद्ध विद्वान मौलाना कलबे रूशैद ने कहा कि ईरान से पश्चिमी देशों की दूरियां कम होंगी और भारत के साथ ईरान के संबंध पहले से अधिक मज़बूत होंगे. लखनऊ विश्वविद्यालय में फारसी विभाग के प्राध्यापक डॉ. सैयद गुलाम नबी कहते हैं कि हसन रूहानी उदारवादी शख्स के रूप में प्रसिद्ध हैं. आशा की जाती है कि वह ईरान की पश्चिमी देशों, ख़ासकर अमेरिका से दूरियां कम करेंगे और देश को आर्थिक संकट से उबारेंगे. ईरान की पश्चिमी देशों से दूरी का असर भारत पर भी पड़ा, लेकिन अब अगर सुधार आता है, तो भारत एवं ईरान के रिश्तों में भी मज़बूती आएगी. ■

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
दो टूक : संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

बड़ा सवाल यह है कि क्या कभी हमने यह सोचा है कि बाबा बर्फानी क्यों पिघल रहे हैं और इसका गुनहगार कौन है?

प्रार्थनाष्टक

गुरुवार दिवस गुरु का मानो, सद्गुरु ध्यान चित्त में ठानो.
स्थोथरा पठन हो अति फलदाई, महाप्रभावी सदा सहाई.
व्रत एकादशी पुण्य सुहाई, पठन सुदिन इसका कर भाई.
निश्चय चमत्कार थम पाओ, शुभ कल्याण कल्पतरु पाओ.
उत्तम गति स्तोत्र प्रदाता, सदगुरु दर्शन पाठक पाता.
इह परलोक सभी हो शुभकर, सुख-संतोष प्राप्त हो सत्वर.
स्तोत्र परायण सद्य: फल दे, मंद बुद्धि को बुद्धि प्रबल दे.
हो संरक्षक अकाल मरण से. हो शतायु स्तोत्र पठन से.
निर्धन धन पाएगा भाई, महा कुबेर सत्य शिव साई.
प्रभु अनुकंपा स्तोत्र समाई. कवि वाणी शुभ सुगम सहाई.
संतविहीन पाएं संतान, दायक स्तोत्र पठन कल्याण.
मुक्त रोग से होगी काया, सुखकर हो साई की छाया.
स्तोत्र पाठ नित मंगलमय है, जीवन बनता सुखद प्रखर है.
ब्रह्म विचार गहन तर पाओ, चिंतामुक्त जियो हर्षाओ.
आदर उर का इसे चढ़ाओ, अंत दृढ़ विश्वास बसाओ.
तर्क-वितर्क विलग कर साधो, शुद्ध विवेक बुद्धि अवराधो.
यात्रा करो शिरडी तीर्थ की, लगन लगी को नाथ चरण की.

दीन-दु:खी का आश्रय जो हैं, भक्त-काम-कल्प-द्रुम सोहें.
सुप्रेरणा बाबा की पाऊं, प्रभु आज्ञा पा स्तोत्र रचाऊं.
बाबा का आशीष न होता, क्यों यह गान पतित से होता.
शक संवत अठरह चालीसा, भादों मास शुक्ल गौरीशा.
शशिवार गणेश चौथ शुभ तिथि, पूर्ण हुई साई की स्तुति.
पुण्य धार रेवा शुभ तट पर, माहेश्वर अति पुण्य सुथल पर.
साईनाथ स्तवन मंजरी, राज्य अहिल्या भू में उतारी.
मांधाता का क्षेत्र पुरातन, प्रगटा स्तोत्र जहां पर पावन.
हुआ मन पर साई अधिकार, समझो मंत्र साई उद्गार.
दासगणु किंकर साई का, रज कण संत साधु चरणों का.
लेखबद्ध दामोदर करते, भाषा गायन भूपति करते.
साईनाथ स्तवन मंजरी, तारक भवसागर हृदय तंत्री.
सारे जग में साई छाए, पांडुरंग गुण किंकर गाए.
श्रीहरिहरापर्णमस्तु शुभं भवतु, पुंडलिक वरदा विट्ठल.
सीताकांत स्मरण जय-जय राम, पार्वतीपते हर-हर महादेव.
श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय.
श्री सद्गुरु साईनाथपर्णमस्तु.

अमरनाथ यात्रा

पिघल रहे हैं बाबा बर्फानी

भक्तों में इस बात को लेकर बेहद मायूसी है कि बर्फानी बाबा पिघल रहे हैं, तो ऐसे में दर्शन होंगे या नहीं. बाबा के पिघलने के पीछे दोषी दरअसल, उनके भक्त भी हैं, जो पर्यावरण को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

अमरनाथ में 3888 मीटर की ऊंचाई पर प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग 40 प्रतिशत से ज़्यादा पिघल गया है, जो सामान्य तौर पर हर साल श्रावण मास के ख़त्म होते-होते पिघलता है. ऐसे में मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि घाटी में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने की वजह से बाबा बर्फानी के दर्शन न होने का ख़तरा अब और बढ़ता जा रहा है. दरअसल, रक्षाबंधन तक क़रीब दो महीने चलने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है. अमरनाथ की यात्रा 28 जून से शुरू हो चुकी है, जो कि 21 अगस्त तक चलेगी, लेकिन अभी से बाबा बर्फानी के पिघलने के कारण शिवभक्तों की चिंता बेहद बढ़ गई है. हालांकि पिछले कुछ दिनों से पारा गिर रहा है, लेकिन फिर भी भक्तों को चिंता है. वैसे, आने वाले दिनों में भी तापमान में गिरावट आने की संभावना है. हालांकि अगर ऐसा हुआ, तो बाबा बर्फानी का पिघलना रुक सकता है. बड़ा सवाल यह है कि क्या कभी हमने यह सोचा है कि बाबा बर्फानी क्यों पिघल रहे हैं और इसका गुनहगार कौन है? इसका जवाब यही होगा कि बर्फानी बाबा के पिघलने के पीछे उनके भक्त ही ज़िम्मेदार हैं. इतिहास गवाह है कि जब-जब प्रकृति के साथ मानव ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो ऐसे में वह भूकंप, बाढ़, हिम-स्खलन और बर्फ पिघलने जैसी भयावह त्रासदियों के रूप में हमारे सामने आई. बर्फानी बाबा का पिघलना प्रकृति के साथ हमारे क्रूर मजाक का परिणाम है, जिसे हम शायद एक सामान्य घटना समझ रहे हैं, लेकिन प्रकृति से खिलवाड़ करने वाले लोगों को यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि यह भविष्य के लिए ख़तरे की घंटी है, जिसे नज़रअंदाज करना काल के गाल में जाने के समान होगा. क्या आपने कभी गौर किया है कि लाखों की संख्या में बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए जाने वाले लोग आसपास के क्षेत्रों में कैसे गंदगी फैलाते जाते हैं. दरअसल, वे जो कुछ भी खाते-पीते हैं, उसके छिलके और पॉलीथीन रास्ते में ही फेंकते हुए आगे बढ़ते हैं.

अमरनाथ यात्रा

अमरनाथ यात्रा पर जाने के दो रास्ते हैं. एक पहलगाम होकर और दूसरा सोनमर्ग बलटाल से. यहां से आगे जाने के लिए अपने पैरों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है. पहलगाम तक जाने के लिए जम्मू-कश्मीर पर्यटन केंद्र से सरकारी बस उपलब्ध है. यात्रा में थकान तो होती है, लेकिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफर की सारी थकान पल भर में छू-मंतर हो जाती है.

किंवदंती

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व और सृष्टि के सृजन के बारे में बताया था. दरअसल, पार्वती लगातार अपने पति से अमरत्व और सृष्टि के निर्माण का राज जानना चाहती थीं, लेकिन भगवान शिव उस स्थान की तलाश में थे, जहां कोई तीसरा व्यक्ति सुन न सके. इसलिए उन्होंने इस गुफा को चुना.

महत्वपूर्ण तथ्य

- 5000 साल पुरानी है अमरनाथ गुफा. इसकी खोज गड़रिया बूटा मलिक ने की थी. हालांकि एक अन्य किंवदंती के अनुसार, भृगु ऋषि ने सबसे पहले यहां शिवलिंग के दर्शन किए थे.
- अमरनाथ गुफा 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. यह जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से क़रीब 141 किलोमीटर दूर है.
- 1996 में अमरनाथ यात्रा के दौरान खराब मौसम के कारण 250 यात्री मारे गए थे. यह अमरनाथ यात्रा के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक त्रासदी मानी जाती है.

यात्रा विशेष

अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू हो चुकी है. इस वर्ष अमरनाथ यात्रा कुल 55 दिनों की रहेगी. 21 अगस्त, यानी रक्षाबंधन के दिन इस साल के आख़िरी दर्शन होंगे. यात्रा के मद्देनज़र अब तक क़रीब दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं का पंजीकरण हो चुका है. क़रीब ढाई महीने पूर्व पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी.

रोक सकते हैं बाबा को पिघलने से

- घर में टीवी एवं संगीत साधनों की आवाज़ धीमी रखें.
- कार का हॉर्न अनावश्यक न बजाएं.
- लाउड स्पीकर का प्रयोग न करें.
- शादी-विवाह में बैंड-बाजे-पटाखे आदि व्यवहार में न लाएं.
- ध्वनि प्रदूषण संबंधी सभी क़ानूनों का पालन करें.
- घर, फैक्ट्री एवं वाहन के धुएं को सीमा में रखें.
- पटाखों का इस्तेमाल न करें.
- कूड़ा-कचरा जलाएं नहीं, नियत स्थान पर डालें.
- ज़रूरी हो, तो थूकने के लिए बहती नालियों या थूकदान का इस्तेमाल करें.
- नालों-कुओं-तालाबों-नदियों में गंदगी न करें.
- सार्वजनिक जल वितरण के साथ छेड़छाड़ न करें.
- पानी की एक भी बूंद बर्बाद न करें.
- रासायनिक की जगह जैविक खाद, प्लास्टिक की जगह कागज, पोलिस्टर की जगह सूती कपड़े या जूट आदि का इस्तेमाल करें.
- प्लास्टिक की थैलियां आदि रास्ते में न फेंकें.
- ज़्यादा से ज़्यादा पेड़-पौधे, हरियाली लगाएं.

क्यों पिघले बर्फानी बाबा

बर्फानी बाबा के पिघलने के पीछे मूल कारण प्रदूषण है, जिसके लिए उनके भक्त भी ज़िम्मेदार हैं. ये कारण हैं बाबा के पिघलने के:-

- वातावरण में रसायन और अन्य सूक्ष्म कणों की मुक्ति
- आम गैसीय प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी), उद्योगों एवं मोटर वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक.
- घरेलू सीवेज और क्लोरीन जैसे रासायनिक प्रदूषक पौधों एवं पानी में रहने वाले जीवों के लिए हानिकारक होते हैं.
- ठोस कचरे के फैलने और रासायनिक पदार्थों के रिसाव के कारण.
- अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश.
- अत्यधिक शोर.
- रेडियोधर्मी प्रदूषण, यानी परमाणु ऊर्जा उत्पादन, परमाणु हथियारों के अनुसंधान, निर्माण एवं तैनाती के दौरान उत्पन्न होने वाला प्रदूषण.

कैसे पहुंचें?

निकटस्थ हवाई अड्डा श्रीनगर है. अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो आपको जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा. सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं, तो आप जम्मू और श्रीनगर, दोनों जगह से जा सकते हैं.

हेलिकॉप्टर सेवा

हेलिकॉप्टर सेवा सस्ती की गई है. बालटाल-पंचतरनी-बालटाल के लिए एक तरफ़ की लगभग 1800 रुपये और पहलगाम-पंचतरनी-पहलगाम के लिए 2700 रुपये में बुकिंग होती है. 2 से 12 वर्ष के बच्चों का आधा किराया लगता है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

गॉड ऐंड आई

ईश्वर हमारे दिल में हैं : संजीदा शेख

टीवी ऐक्टर संजीदा शेख बालाजी प्रोडक्शन का धारावाहिक क्या होगा निम्मो का, से रातोंरात टीवी स्टार बन गईं. डांस रियलिटी शो नच बलिये-3 के फाइनल में आमिर अली के साथ शो का खिताब जीतकर संजीदा ने खूब प्रशंसा बटोरी. ऐक्टिंग के क्षेत्र में संजीदा संयोग से ही आई थीं और इसीलिए इसे वह भगवान का आशीर्वाद मानती हैं. बातचीत के दौरान ईश्वर में आस्था है या नहीं, इस पर उन्होंने कुछ बातें बताईं ...

क्या आपकी ईश्वर में आस्था है?

हां, मैं ईश्वर को जरूर मानती हूं, लेकिन खुद को ईश्वर की अंधभक्त भी नहीं मानती. देखिए, मैं कट्टर धार्मिक इंसान नहीं हूं कि मंदिर-मस्जिद, चर्च-गुरुद्वारा में जाकर मत्थे टेकती फिरूं. मुझे पता है कि असली धार्मिकता आपके दिल और मस्तिष्क में होती है. दरअसल, जब भी मेरे मन में कोई अच्छी सोच आती है और अच्छी भावना जन्म लेती है, तो मुझे लगता है, ईश्वर मेरे पास हैं और वह मुझे गाइड कर रहे हैं.

मेरे लिए अपना काम ईमानदारी से करने के साथ-साथ माता-पिता और बुजुर्गों की सेवा करना, उनका ध्यान रखना ही असली पूजा है. यही वजह है कि मैं अपने पैरेंट्स को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती हूं. माता-पिता की सेवा करने के दौरान मुझे अच्छी तरह एहसास हो जाता है कि ईश्वर हमारे दिल में है और हमारे पास है, जो हमें नेक रास्ते पर चलना सिखाता है.

क्या आप मानती हैं कि आज जहां आप हैं, उसमें ईश्वर का भी हाथ है?

हां, यह आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ऐक्टिंग की दुनिया में संयोग से आई थी और ऐसा ईश्वर के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है. मैंने कभी ऐक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था. मैं मुंबई अपने एक मित्र के डांस स्कूल की ओपनिंग के लिए आई थी और फिर उसी स्कूल में धीरे-धीरे डांस सिखाना शुरू कर दिया. इस दौरान साउथ की तीन फिल्मों में काम भी किया. बाद में एक समारोह में एकता कपूर ने मुझे देखने के बाद स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया और क्या होगा निम्मो का, में निम्मो की भूमिका के लिए. बाद में उन्होंने मुझे वह भूमिका दे दी. उसके बाद छोटा पर्दा और शोज ही मेरे जीवन का अहम हिस्सा बन गए. चूंकि ऐक्टिंग में आने की कोई प्लानिंग नहीं थी, इसके बावजूद यदि इस फील्ड में सक्रिय हूं और यहीं रम भी गई हूं, तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं ऊपरवाले की ही मर्जी है.

कर्म या किस्मत किस पर भरोसा करती हैं आप?

मेरे लिए अपना कर्म ईमानदारी से करना एक तरह से ईश्वर की पूजा करने के बराबर है, क्योंकि मैं कर्म के सिद्धांत में यकीन करती हूं. कर्म के सिद्धांत को मानने के कारण ही मैं अपना काम होमवर्क के असाइनमेंट की तरह ही करती हूं. सलीके से काम करना मुझे पसंद है और इसमें मुझे मजा भी आता है. जब आपके साथ सब कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा ईश्वर के आशीर्वाद के बिना संभव ही नहीं है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

अनंत विजय

सूक्तियों की कसौटी पर प्रेमचंद

हर साहित्यकार का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ अति उत्साही आलोचक आज की सामाजिक स्थिति को आधार बनाकर लेखक का मूल्यांकन करने में ही विश्वास करते हैं. नतीजतन वे फौरी चर्चा हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह उतने ही हास्य के पात्र भी बन जाते हैं. आइए जानते हैं कि लेखक ने यह टिप्पणी क्यों की?

जिस तरह से महात्मा गांधी दुनिया भर के राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर लिखने वाले लेखकों को लुभाते हैं, उसी तरह से हिंदी साहित्य में रुचि रखनेवालों या फिर देश के हिंदी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ने-पढ़ाने वालों को प्रेमचंद अपनी ओर से आकर्षित करते हैं. प्रेमचंद ने हिंदी में विपुल लेखन किया है. वह जब लिख रहे थे, तो उस वक्त देश की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी, उसको ध्यान में रखकर उनकी रचनाओं को कसौटी पर कसा जाना चाहिए था, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि कुछ अति उत्साही आलोचक आज की सामाजिक स्थिति को आधार बनाकर उनका मूल्यांकन करने में विश्वास करते हैं. नतीजा यह होता है कि प्रेमचंद की धज्जियां उड़ाकर, उन्हें दलित और महिला विरोधी करार देकर वह फौरी चर्चा तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उतने ही वह हास्य के पात्र भी बन जाते हैं. हर साहित्यकार का मूल्यांकन उसके लेखन काल और देश में उस वक्त की परिस्थियों के आधार पर किया जाना चाहिए. जैसे प्रेमचंद ने लिखा था-सौभाग्यवती स्त्री के लिए उसका पति संसार का सबसे प्यारा वस्तु होता है. अब अगर प्रेमचंद की इस उक्ति को स्त्री विमर्श के नाम पर हाथ में एके-47 लेकर लेखन करनेवाली लेखिकाओं की कसौटी पर कसेंगे, तो बेचारे प्रेमचंद कहीं के भी नहीं रहेंगे. आज की स्त्री विमर्शकार के लिए पति तभी तक संसार का सबसे प्यारा वस्तु हो सकता है, जब तक वह अपनी पत्नी को तमाम तरह की आजादी दे, बराबरी का हक दे और खासकर, उसके फैसलों में दखल न दे. प्रेमचंद के युग से लेकर अब तक पति की परिभाषा पूरी तौर पर बदल चुकी है. प्रेमचंद के युग से लेकर पति ने लंबी यात्रा तय की है. दरअसल, अब पति परमेश्वर से सहजीवी और साथी होते-होते लगभग खलनायक हो गया है.

प्रेमचंद अपने कथा साहित्य में इतने पर ही नहीं रुकते हैं. वह कहते हैं- 1. पति की आड़ में सबकुछ जायज है. मुसीबत तो उसकी है, जिसे कोई आड़ नहीं. 2. औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में भी तो नहीं रहती. 3. पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं, तो वह महात्मा बन जाता है. नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं, तो वह कुलटा हो जाती है. 4. ब्याह तो आत्मसमर्पण है. 5. प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है, तभी ब्याह है, उसके पहले ऐय्याशी है. इन पांच सूक्तियों के आधार पर अगर प्रेमचंद का मूल्यांकन किया जाए, तो उनका लेखन पूरी तौर पर मर्दवादी लेखन कहा जाएगा और स्त्री विमर्शकार उनको स्त्री विरोधी साबित कर देंगे. कईयों ने कोशिश भी की है, जबकि सच यह नहीं है. जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि प्रेमचंद को समग्रता में समझने के लिए तत्कालीन सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है.

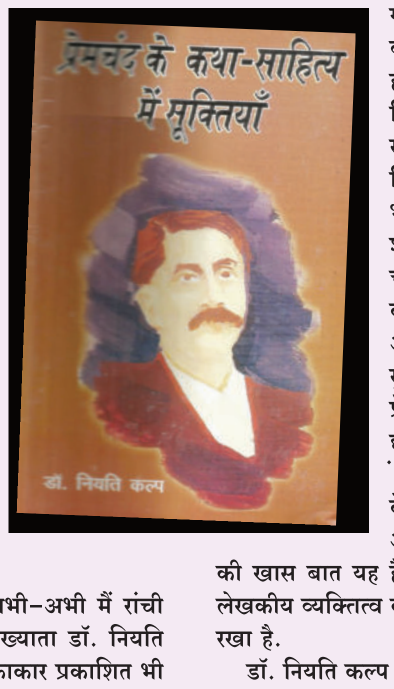

यह पूरा संदर्भ इसलिए दे रहा हूं कि अभी-अभी मैं रांची विश्वविद्यालय के मारवाड़ी कॉलेज में व्याख्याता डॉ. नियति कल्प का शोध प्रबंध पढ़ रहा था, जो पुस्तकाकार प्रकाशित भी है. दरअसल, पिछले महीने मैं भागलपुर गया था. भागलपुर मुझे अपने शहर जैसा ही लगता है, क्योंकि वहीं से मैंने कॉलेज की पढ़ाई की थी. वहीं एक समारोह के दौरान मुझे नियति कल्प की किताब मिली-प्रेमचंद के कथा साहित्य में सूक्तियां. लगभग पौने चार सौ पृष्ठों की इस किताब में बहुत मेहनत से प्रेमचंद के कथा साहित्य से सूक्तियां छांटकर व्याख्यायित किया गया है. नियति ने समग्रता में सूक्तियों को देखा है और स्त्री के लिए लिए गए अच्छे वाक्यों को भी इस किताब में व्याख्यायित किया है 1. स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है, जितना प्रकाश अंधेरे से. 2. स्त्री जितना क्षमाशील हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता. 3.नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल सकती है, कड़वाहट भी. उसके अंदर पड़नेवाले बीज में जैसी शक्ति हो. 4. नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है. परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीट है. प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर. अब अगर इन सूक्तियों के आधार पर प्रेमचंद की विवेचना करें, तो उनकी अलग छवि उभरती है. एक ऐसे लेखक की, जो स्त्री के पक्ष में मजबूती से खड़ा है, उस वक्त के पितृसत्तात्मक समाज के बगैर दबाव में आए, लेकिन नियति कल्प की इस किताब की खास बात यह है कि उसने सूक्तियों के बहाने प्रेमचंद के लेखकीय व्यक्तित्व को बगैर किसी पूर्वाग्रह के पाठकों के सामने रखा है.

डॉ. नियति कल्प ने अपनी इस किताब को छह खंडों में बांटा है. पहले अध्याय में सूक्ति का सैद्धांतिक विवेचन किया गया है, जिसमें सूक्तियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है. दूसरे अध्याय में प्रेमचंद के साहित्य संसार पर आलोचनात्मक नजर डाली गई है. इस अध्याय को पढ़ने से इस किताब और प्रेमचंद के साहित्य संसार का एक बैकग्राउंड पाठक को मिलता है. उसके बाद के अध्यायों में प्रेमचंद के कथा साहित्य में सामाजिक सूक्तियां, भावनात्मक सूक्तियां, दार्शनिक और राजनीतिक सूक्तियां और अन्य सूक्तियों को व्याख्यायित किया गया है. नियति कल्प की यह किताब साहित्य के विद्यार्थियों के अलावा, साहित्य में रुचि रखनेवालों पाठकों के लिए एक संदर्भ ग्रंथ की तरह है, लेकिन एक चीज, जो इस किताब में मुझे खटकी, वह है इसकी भाषा. नियति कल्प भारत के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा प्रयोग में लाई जानेवाली भाषा से खुद को मुक्त नहीं कर पाई है. दरअसल, यह नियति की कमी नहीं है, यह कमी हमारी शिक्षण प्रणाली और विश्वविद्यालयों की है. हमारे विश्वविद्यालय के हिंदी विभागों को यह समझने की जरूरत है कि हिंदी एक भाषा के तौर पर काफी विकसित हो चुकी है. ऐसे में विभाग को भाषा के विकास के साथ कदम से कदम मिलाने की जरूरत है. नियति ने इस किताब में क्लासिक हिंदी का प्रयोग किया है. हालांकि शोध प्रबंध में इसकी ही अपेक्षा की जाती है. हिंदी के विभागों में काम करनेवाले ज्यादातर आलोचकों को ही देख लें, तो वह मुक्तिबोध के आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं. लौट-लौटकर मीराबाई और कबीर तक जा पहुंचते हैं. कुछ आलोचक हिम्मत जुटाते भी हैं, तो फिर से मैथिलीशरण गुप्त और सूरदास की तरफ पहुंच जाते हैं. लगता है कि प्राध्यापकीय आलोचना में अतीतोन्मुख होने की होड़ है. मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि जिस तरह से निर्मल वर्मा और मुक्तिबोध को नामवर जी जैसे आलोचक मिले, क्या नई पीढ़ी को वैसा कोई आलोचक मिल पाएगा. फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं देता. आज विश्वविद्यालयों में इस बात की सख्त जरूरत है कि युवा शिक्षकों को इस बात के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए कि वह नई पीढ़ी के लेखकों की रचनाओं को आलोचना की कसौटी पर कसें. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

बिना वृक्ष नहीं कल्याण

सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य का प्रकृति से गहरा रिश्ता रहा है, लेकिन आज हम उसी प्रकृति की अनदेखी कर रहे हैं, जिसकी गोद में कभी हमारे पूर्वजों ने मोक्ष प्राप्त किया. सचमुच, बिना प्रकृति हमारा कल्याण संभव नहीं है.

निर्मलेंदु
feedback@chauthiduniya.com

कहते हैं वेद, पुराण, बिना वृक्ष के नहीं कल्याण

दरअसल, लेखक ने यही साबित करने की कोशिश की है कि बिना वृक्ष के हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता. यह स्लोगन हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने जंगल में एक साइन बोर्ड पर लिखा था. उस साइन बोर्ड पर लिखे ये नौ शब्द पर्यावरण की उत्पत्ति का एक वैकल्पिक सिद्धांत पेश करते हैं. तात्पर्य यह है कि आधुनिक इतिहासकार शायद जो बात कहेंगे, उसके ठीक उलट लेखक सुझाते हैं कि प्राचीन हिंदू पहले पर्यावरणवादी थे. लेखक यह समझाना चाहते हैं कि प्राचीन हिंदुओं के मिथकों, लोकगाथाओं और कर्मकांडों में एक अनगढ़ पर्यावरणीय चेतना दिखती थी, जहां भगवान पशुओं से खेलते थे. उनका तर्क यही है कि मनुष्य जंगलों में ही मोक्ष प्राप्त करता था और वहीं नन्हे पौधों और कीटों की प्रजातियों के साथ लोग सम्मान से पेश आते थे.

उन्होंने तर्क दिया कि मनुष्य, पशु और वृक्ष समुदाय समान नियमों के अधीन हैं, हालांकि ये नियम बदलते रहते हैं, जो संतुलन और सबकी उन्नति के लय को लगातार कायम रखते हैं. रामचंद्र गुहा का मानना यह है कि प्रकृति, वनस्पति और मनुष्यों समेत, जीव पर्यावरण के बीच एक संतुलन है, जिसमें प्रकृति आनंद से रहती है. दरअसल, यह क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के एक सिलसिले के जरिए कायम है, जो मनुष्यों को उसके शेष सजीव क्षेत्रों से जोड़ती ही नहीं है, बल्कि यह ऊपर से नीचे तक और अपने चारों तरफ़ की अदृश्य जैविक और सामाजिक नियति तक पहुंचाती भी है. उनका मानना है कि प्रकृति और मानव समाज के पूरे परिधान को नुकसान पहुंचाए बिना एक भी धागा तोड़ा नहीं जा सकता. हालांकि मनुष्य अक्सर अपनी अज्ञानता या स्वार्थ के कारण इस ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर देता है, लेकिन इसमें संदेह नहीं है कि यह सामाजिक प्रगति और समाज की शक्तियों के आपसी अंतर्संबंधों और एकता के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर पैटर्नों के चेतन के निर्माण में निहित है.

लेखक का सुझाव है कि पर्यावरणवादी चेतना को औद्योगिक समाज की तरक्की के प्रति एक विशिष्ट प्रतिक्रिया के रूप में भी देखना चाहिए. मतलब यह है कि बिना मानवीय हितों का समुचित प्रावधान किए वन्यजीवों के संरक्षण की किसी भी भव्य योजना का नाकाम होना तय है. विकासशील देशों में संरक्षण अक्सर वैज्ञानिक आदर्शवाद और व्यवहारिक यथार्थ के बीच एक समझौता है. अब इस विषय को इस रूप में देख सकते हैं कि संरक्षण और जीव विज्ञान एक-दूसरे पर निर्भर हैं और इसीलिए उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीव विज्ञान संरक्षण के सभी चरणों के केंद्र में है और इसकी सफलता और असफलता का अंतिम निर्णायक भी है.

रामचंद्र गुहा एक चिरपरिचित नाम है. वह एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं. उनका जन्म देहरादून में हुआ. पिछले दस सालों के दौरान तीन महाद्वीपों में पांच अकादमिक पदों पर रहने और कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के बाद वह अंततः एक पूर्णकालिक लेखक बन गए.

समीक्ष्य कृति : उपभोग की लक्ष्मण रेखा
लेखक : रामचंद्र गुहा
प्रकाशक : पेंगुइन बुक्स
मूल्य : 350 रुपये

रामचंद्र गुहा एक चिरपरिचित नाम है. वह एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं. उनका जन्म देहरादून में हुआ. पिछले दस सालों के दौरान तीन महाद्वीपों में पांच अकादमिक पदों पर रहने और कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के बाद वह अंतत: एक पूर्णकालिक लेखक बन गए. उन्होंने पर्यावरणवाद पर ज़्यादा लिखा. उन्होंने इस किताब के माध्यम से यह बताने और हमें सावधान करने की कोशिश की है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, हमें उपभोग की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए. इस किताब में भारत और अमेरिका में दो दशकों से अधिक समय तक चले शोध पर आधारित पर्यावरणवाद के तुलनात्मक इतिहास के बारे में बताया गया है और चूंकि पर्यावरण आज पूरे विश्व के लिए ज्वलंत समस्या बन गया है, इसलिए यह किताब हम सबके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है. ■

नज़रुल इस्लाम

अंग्रेजी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक विद्रोही कवि

जीवन जैसे-जैसे दुरूह होता जाएगा, नज़रुल इस्लाम जैसे युग द्रष्टा कवि की याद उतनी ही तीव्र होती जाएगी. दरअसल, उन्होंने न सिर्फ अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में चेतना जगाया, बल्कि सर्वधर्मसमभाव का एक ऐसा उदाहरण भी पेश किया, जो आज भी लोगों के लिए अनुकरणीय है.

नज़रुल इस्लाम भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कविताएं और उनके विचार आज के ऐसे माहौल में भी हमेशा जीवंत बनी हुई हैं. जहां परिवारों में विश्वास, आपसी प्रेम और लगाव की कमी हो, नज़रुल की कविताएं एक मरहम से कम नहीं. मजहबी जुनून, सांप्रदायिकता, सौहार्द में गहरी कमी, आक्रामकता का बढ़ता स्तर, ये सामाजिक जिंदगी की ऐसी चुनौतियां हैं, जो धीरे-धीरे विकराल होती जा रही हैं. जीवन जैसे-जैसे दुरूह होता जाएगा, नज़रुल इस्लाम जैसे युग द्रष्टा की याद भी उतनी ही तीव्र होती जाएगी. उन्होंने न सिर्फ अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों में चेतना जगाने का काम किया, बल्कि सर्वधर्मसमभाव का एक ऐसा उदाहरण पेश किया, जो आज भी लोगों के लिए अनुकरणीय है. मुस्लिम होते हुए भी वह मां काली के बहुत बड़े भक्त थे. उन्होंने मां काली पर सैकड़ों कविताएं लिखीं. आजादी के आंदोलन में उनकी कविताएं जोश भर देती थीं. यही कारण था कि अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी कविताओं पर प्रतिबंध लगा दिया था. उनकी कविताएं आज भी प्रासंगिक हैं.

नज़रुल इस्लाम अग्रणी बांग्ला कवि, संगीतज्ञ, संगीत लेखक और दार्शनिक भी थे. वह बांग्ला भाषा के अन्यतम साहित्यकार, देशप्रेमी तथा बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं. उनकी महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों ही जगह उनकी कविता और गान को समान आदर प्राप्त है. उनकी कविता में विद्रोह के स्वर होने के कारण उनको विद्रोही कवि के नाम से भी जाना जाता है. नज़रुल ने मनुष्य का मनुष्य पर अत्याचार, सामाजिक अनाचार तथा शोषण के विरुद्ध प्रतिवाद को ही अपनी कविताओं का मुख्य विषय बनाया. आज के अधिकांश कवि वोटपरस्त राजनीतिक दलों को ध्यान में रखकर सांप्रदायिकता को कोसते हैं, लेकिन नज़रुल इस्लाम ने इन सब विवादों से हमेशा दूरी बनाए रखा. पार्टी के चुनाव घोषणा पत्रों को ध्यान में रखकर लेखक संगठन सांप्रदायिकता की निंदा या विरोध करेंगे, तो रचनाओं में तत्कालीन चुनौतियों का उल्लेख जरूर नजर आएगा. ऐसे में पाठक में एक अतृप्तता और गहरी खीज उभरती है. वह लेखक को भी पक्षपात लेखन की श्रेणी में डाल देता है, लेकिन नज़रुल ने न तो अपने पाठकों के साथ यह अन्याय किया और न ही पाठकों ने उनको इस कटघरे में खड़ा किया. नज़रुल का लेखन बेहद प्रभावी था. उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से ठेठ सामाजिक, ठेठ इंसान के संदर्भ में बेहतरीन रचनाएं दिए. इस बात का उन्होंने हमेशा ख्याल भी रखा कि बतौर लेखक कहीं वह अपनी सामाजिक रचनात्मकता का शोषण तो नहीं करवा रहे हैं. हालांकि आज के लेखकों को इन बातों से कोई सरोकार नहीं. वे बस लिखना जानते हैं. क्या लिखना है, यह उन्हें नहीं पता. नज़रुल इस्लाम अध्यात्म और भौतिक स्वरूप से गहरा सामाजिक सरोकार पेश करते हैं. उन्हें यह पता था कि किसी साहित्य का लेखन, चाहे वह किसी भी विधा का हो, जब रचा जाता है, तो वह सिर्फ कुछ पन्नों पर लिखी इबारत मात्र नहीं होती, बल्कि वह समाज के निर्माण का, उसे निरंतर मुक्त करते हुए सृजनात्मक मूल्यों का निर्माण भी करता है. नज़रुल की कविताओं की ख्याति, देश में ही नहीं, विदेशों में भी फैली. यही कारण है कि बांग्लादेश सरकार ने उन्हें आदर के साथ अपने यहां बुलाया और बांग्लादेश की राष्ट्रीयता दी. ■

नजरुल का जन्म भारत के पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला में आसनसोल के पास चुरुलिया गांव में हुआ था. उनका बचपन अभावों में गुजरा. किशोरावस्था में विभिन्न थिएटर दलों के साथ भी उन्होंने काम किया, जिसके कारण वह कविता, नाटक एवं साहित्य में काफी निपुण हो गए. नजरुल ने लगभग 3000 गानों की सिर्फ रचना ही नहीं की, बल्कि उनमें से अधिकांश को स्वर भी दिया, जिसे आज नज़रुल संगीत या नज़रुल गीति के नाम से भी जाना जाता है. बांग्लादेश सरकार के आमंत्रण पर वह सपरिवार ढाका आए. उस समय उनको बांग्लादेश की राष्ट्रीयता प्रदान की गई. यहीं उनकी मृत्यु हुई.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

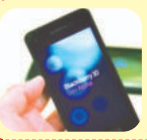

यह ब्लैकबेरी का पहला बीबी10 स्मार्टफोन है. किसी भी नोटिफिकेशन का इस्तेमाल बेहद आसान है.

स्वाइप का 6 इंच वाला एमटीवी वोल्ट 1000

कैलिफॉर्निया की स्वाइप टेलिकॉम ने नया बजट फैबलेट एमटीवी वोल्ट 1000 लॉन्च किया है. फैबलेट की कीमत 11,999 रुपये रखी गई है. ड्यूल सिम वाले इस फैबलेट में 1 गीगाहर्ट्ज ड्यूल-कोर प्रोसेसर और 1 जीबी रैम है. यह एंड्रॉयड 4.1 पर चलता है. इसमें 480854 पिक्सल वाला 6 ईंच का डिस्प्ले है. इसमें 4 जीबी की इंटरनल स्टोरेज है और 32 जीबी तक मेमरी कार्ड लगाया जा सकता है. पीछे की तरफ 8 मेगापिक्सल और आगे की तरफ 1.3 मेगापिक्सल कैमरा है. कनेक्टिविटी ऑप्शंस में ब्लूटूथ 4.0, वाई-फाई और यूएसबी 2.0 शामिल हैं. इसमें 2850 एमएच की बैटरी लगी है. एमटीवी से साझेदारी होने के नाते इसमें इनबिल्ट टीवी प्लेयर पर कहीं भी एमटीवी देखा जा सकेगा. इसमें एफएम रेडियो भी है.

ऑनलाइन शॉपिंग

देश में भले ही स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए शॉपिंग ऐप्स केबजाय वेबसाइट्स पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं. रिसर्च कंपनी नील्सन के सर्वे के मुताबिक, देश में लगभग 25 फीसद स्मार्टफोन यूजर्स अपने हैंडसेट पर शॉपिंग ऐप्स केबजाय ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं. नील्सन का कहना है कि शॉपिंग ऐप्स अभी शुरुआती दौर में है और केवल 3 फीसद स्मार्टफोन यूजर्स इनका इस्तेमाल करते हैं. हर चार में से एक स्मार्टफोन यूजर महीने में कम से कम एक बार शॉपिंग वेबसाइट्स को ऐक्सेस करता है. सर्वे में फ्लिपकार्ट को सबसे लोकप्रिय शॉपिंग वेबसाइट पाया गया.

देश में लगभग 25 फीसद स्मार्टफोन यूजर्स अपने हैंडसेट पर शॉपिंग ऐप्स के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं. नील्सन का कहना है कि शॉपिंग ऐप्स अभी शुरुआती दौर में है और केवल 3 फीसद स्मार्टफोन यूजर्स इनका इस्तेमाल करते हैं.

बड़ी स्क्रीन वाले सस्ते एप्पल आईफोन

एप्पल इंक बड़ी स्क्रीन वाले आईफोन लॉन्च करने वाली है. वह जल्द ही इसके सस्ते मॉडल भी ला सकती है. सैमसंग को देखते हुए एप्पल ने भी अब इस तरह के फोन बाजार में लाने का मन बना लिया है. एप्पल का कभी स्मार्टफोन मार्केट पर दबदबा था. हाल ही में उसे सैमसंग से कड़ा चैलेंज मिल रहा है. मार्केट शेयर के मामले में एप्पल आज सैमसंग से पीछे है. इसके बड़ी स्क्रीन वाले गैलक्सी टैबलेट बहुत कामयाब रहे हैं. सैमसंग अलग-अलग प्राइस रेंज में ऐसे कई प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है. अगले साल एप्पल कम से कम दो बड़े आईफोन लॉन्च कर सकती है. इसमें से एक की स्क्रीन 4.7 ईंच और दूसरे की 5.7 ईंच होगी. अभी मार्केट के बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन में आईफोन 5 का स्क्रीन साइज सबसे कम है. दरअसल, अब ज्यादा कन्ज़्यूमर्स मोबाइल फोन पर इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं. सैमसंग गैलक्सी एस 4 और गैलक्सी नोट 2 की स्क्रीन साइज क्रमशः 5 ईंच और 5.5 ईंच है. इस साल एप्पल दो नए मॉडल्स ला सकती है. इन्हें आईफोन 5एस कहा जा रहा है. इसमें नई फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा. प्लास्टिक केसिंग के साथ इसका सस्ता वर्जन भी लॉन्च किया जा सकता है. यह बात सप्लाई चेन से जुड़े लोगों ने बताया. एप्पल सस्ते फोन को 5-6 कलर में ला सकती है. ये इसके महंगे फोन से अलग दिखेंगे. अब तक कंपनी आईफोन को ट्रेडिशनल ब्लैक ऐंड व्हाइट कलर में ही लाई है.

अगले साल एप्पल कम से कम दो बड़े आईफोन लॉन्च कर सकती है. इसमें से एक की स्क्रीन 4.7 ईंच और दूसरे की 5.7 ईंच होगी. अभी मार्केट के बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन में आईफोन 5 का स्क्रीन साइज सबसे कम है.

गूगल का नया टैबलेट

गूगल के नेक्सस-7 टैबलेट का काफी समय से इंतजार हो रहा था. आखिरकार इंतजार खत्म हो गया. गूगल का यह नेक्सस-7 टैबलेट भारत में 15,999 रुपये में उपलब्ध है. गूगल ने जून 2012 में पहली बार नेक्सस-7 से पर्दा उठाया था और अगले ही महीने इसे बाजार में उतार दिया. लॉन्च होने केसिर्फ तीन महीनों केअंदर ही यह सबसे ज्यादा बिकने वाला टैबलेट बन गया. गूगल नेक्सस-7 में 1.3 गीगाहर्ट्ज में टेग्रा 3 क्वाडकोर प्रोसेसर लगा है. इस टैबलेट में 1280 800 पिक्सल की 7 ईंच की टच स्क्रीन है. 1 जीबी रैम से लैस इस टैबलेट में चैटिंग के लिए 1.2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है. फिलहाल नेक्सस-7 का एक ही मॉडल भारत में उपलब्ध कराया गया है. वाईफाई से लैस इस टैबलेट में 16 जीबी की इंटरनल स्टोरेज है, लेकिन 3जी सपोर्ट न होने से इसके प्रशंसकों को निराशा हाथ लग सकती है. नेक्सस-7 की सीधी टक्कर एप्पल के आईपैड और सैमसंग के गैलक्सी के अलावा, भारतीय बाजार में बिकने वाले अन्य सस्ते टैबलेट से होगी.

ब्लैकबेरी का नया मोबाइल

ब्लैकबेरी के दीवानों के लिए अच्छी खबर है. स्मार्टफोन केबाजार में ब्लैकबेरी ने एक नया फोन बीबी 10 स्मार्टफोन पेश किया है. पावर बटन हैंडसेट के ऊपरी हिस्से में दिया गया है, जबकि दाईं ओर वॉल्यूम कंट्रोल बटन है. यह ब्लैकबेरी का पहला बीबी10 स्मार्टफोन है. ब्लैकबेरी केइस नए फोन का डिजाइन बहुत हद तक एप्पल आई फोन 5 की तरह है. इसका ऑनस्क्रीन की बोर्ड भी बेहतरीन है. सिर्फ अंगूठे से भी इसमें टाइप कर सकते हैं. वर्चुअल की बोर्ड टाइपिंग केदौरान कुछ शब्दों की सलाह भी देता है. इसका ब्राउजर फ्लैश साइट को भी सपोर्ट करता है. कैमरा मोड में टाइम शिफ्ट फीचर इस फोन की बेहतरीन खूबी है. कैमरा ऑन करते ही यह सेकेंड में कई तस्वीरें ले सकता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इससे हम कई मोड को एक साथ कैप्चर कर सकते हैं. यह फोन देखने में भी बेहद खूबसूरत है, जो किसी को भी लुभा सकता है. फोन की बाईं ओर माइक्रो यूएसबी और माइक्रो एचडीएमआई पोर्ट दिए गए हैं. फोन के साथ आप मल्टी टास्किंग कर सकते हैं, लेकिन एक साथ सिर्फ 8 एप्स ही बैकग्राउंड में चल सकते हैं. यह ब्लैकबेरी का पहला बीबी10 स्मार्टफोन है. किसी भी नोटिफिकेशन का इस्तेमाल बेहद आसान है. लेफ्ट से राइट की ओर स्वाइप करके ब्लैकबेरी हब का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां सभी मेल, मैसेज, सोशल नेटवर्किंग मैसेज उपलब्ध रहते हैं. ब्लैकबेरी ने इस फोन में 1850 एमएच की बैटरी की दी है. फोन में एप्स का इस्तेमाल भी आसान है. स्क्रीन पर ऊपर की ओर वाइप करके फोन को अॅनलॉक किया जा सकता है.

एक्टिवा आईः आरामदेह सवारी

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने अपना नया सेगमेंट स्कूटर एक्टिवा-आई पेश किया है. कीमत है 44,200 रुपये. इस सीरीज में कंपनी का यह सबसे किफायती मॉडल है. इंडियन स्कूटर मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल एक्टिवा से इसकी कीमत 5000 रुपये कम है. एक्टिवा के ही समान बगैर गियर वाले इस स्कूटर में 110 सीसी का इंजन है, जिसमें 8.15 पीएस 7,500 आरपीएम और टॉर्क 8.74 एनएम 5,500 आरपीएम की क्षमता है. एक्टिवा-आई स्कूटर में 110 सीसी का इंजन है. इसमें 7,500 आरपीएम पर 8.15 पीएस की क्षमता है, जबकि टॉर्क केमामले में 5,500 आरपीएम पर 8.74 एनएम की क्षमता है. एक्टिवा की ही तरह इसमें भी कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, ट्यूबलेस टायर, मेंटिनेंस फ्री बैटरी और विस्कस एयर फ़िल्टर है. होंडा ने एक्टिवा-आई स्कूटर का माइलेज 60 किलोमीटर प्रति लीटर का दावा किया है. माइलेज बढ़ाने के लिए होंडा ने इसमें होंडा इको टेक्नोलॉजी यूज किया है. एक्टिवा-आई स्कूटर में सीट केनीचे 18 लीटर का स्पेस कपैसिटी दिया गया है. साथ ही इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी इंडियन सड़क को ध्यान में रखते हुए 165 एमएम रखा गया है, जबकि पुराने एक्टिवा का ग्राउंड क्लियरेंस 153 एमएम का था. महिला चालकों को ध्यान में रखते हुए इसमें लगा इर्गोनोमिक ग्रैब रेल कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि 15 फीसद कम ताकत का इस्तेमाल कर आप इसे स्टैंड पर खड़ा रख सकते हैं. नया स्कूटर पेश करने केअवसर पर कंपनी केअध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरामत्सु ने कहा कि ऑटोमेटिक स्कूटर बनाने वाली अग्रणी कंपनी ने एक्टिवा-1 नाम का छोटा स्कूटर पेश किया है. बाजार में अग्रणी स्थिति बरकारार रखने केलिए कंपनी ने रणनीतिक रूप से यह स्कूटर पेश किया है. एचएमएसआई तीन प्रकार के बगैर गियर वाले स्कूटर बनाती है. इनमें डियो, एक्टिवा और एविएटर शामिल हैं. सभी की इंजन क्षमता 110 सीसी है और इनकी कीमत 44,718 रुपये से 53,547 रुपये के बीच है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फैमिली जर्नी के लिए शानदार महिंद्रा क्वांटो

क्वांटो की ड्राइविंग पोजिशन काफी बेहतर है. ऐसे में इसकी हैंडलिंग आसान हो जाती है. एसयूवी होने के बावजूद शहर की भीड़ भरी सड़कों पर कार को ड्राइव करने में खास मुश्किल नहीं आती. क्वांटो का इंटीरियर सामान्य है. फैमिली की जरूरत को देखते हुए यह स्पेशियस है. लैगरूम स्पेस भी बड़ा है. वहीं रियर सीट पर भी सुविधानुसार होल्डर्स दिए गए हैं. छोटी एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी होने के बावजूद क्वांटो रिच लुक देती है. इसका फ्रंट लुक काफी अपीलिंग है. वहीं हेडलाइट और रियर लाइट स्पोर्टी लुक वाली है.

इसके कंफर्ट का असली एहसास लॉन्ग ड्राइव के बाद ही पता चलता है. इसके रियर सीट को और कंफर्टेबल बनाया जा सकता था. शायद आकार कम करने के लिए दूसरी एसयूवी के मुकाबले कम जगह दी गई है. लंबे सफर में यह आरामदायक है. इसकी सीटें काफी सॉफ्ट हैं. हैंड व हैंड रेस्ट भी काफी अच्छे हैं. फ्रंट व मिडिल लेग स्पेस अच्छा है, जो लंबे सफर में थकान महसूस नहीं होने देता. ओवरऑल महिंद्रा क्वांटो बहुत बढ़िया गाड़ी है. हालांकि इसमें दो चीजों की कमी खलती है. एक तो इसकेटायर बहुत छोटे हैं. इन्हें थोड़ा और बड़ा करना चाहिए, जिससे कि असली एसयूवी का लुक आ सके. दूसरा एसी ब्लोअर की कमी बहुत खलती है. सबसे पीछे सीट पर लेग स्पेस कम है. इससे वहां बैठने वाले को थोड़ी परेशानी होती है. स्टीयरिंग लाइट की वजह से सिटी में भी ड्राइविंग आसान हो जाती है. स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, इसलिए उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार सेट किया जा सकता है.

फन ऑफ ड्राइविंग के लिहाज से इस कीमत पर बेहतर विकल्प है. भारतीय रोड के हिसाब से सस्पेंशन बहुत ही अच्छे हैं. टायर थोड़े और हाई प्रोफाइल होने चाहिए थे. भारत में हाई प्रोफाइल टायरों का ज्यादा चलन है.

लंबे सफर में यह आरामदायक है. इसकी सीटें काफी सॉफ्ट हैं. हैंड व हैंड रेस्ट भी काफी अच्छे हैं.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

चला फुटबॉल आईपीएल बनने

क्या फुटबॉल प्रेमियों का सपना पूरा होगा

क्या आपको लगता है कि लॉयनेल मैसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, काका एवं नेमियार जैसे खिलाड़ी कभी किसी भारतीय क्लब के लिए भारत की धरती पर भारतीय खिलाड़ियों के साथ खेलते दिखाई देंगे? जी हां, यदि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और आईएमजी-रिलायंस की चली, तो ऐसा हो सकता है. देश में आईपीएल की तर्ज पर फुटबॉल लीग के आयोजन का खाका तैयार हो रहा है, जिसमें फुटबॉल के सबसे चमकीले सितारे अपनी चमक बिखेरते नज़र आएंगे. लेकिन इस राह में रोड़े बहुत हैं, जिनसे पार पाना और फुटबॉल प्रेमियों का यह सपना पूरा करना एआईएफएफ के लिए आसान नहीं होगा.

नवीन चौहान
naveenchaouhan@chauthiduniya.com

पिछले कुछ समय से भारतीय फुटबॉल पर दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं. भारत में आईपीएल की तरह ईपीएल (इंग्लिश प्रीमियर लीग) भी लोकप्रिय है. इंग्लिश प्रीमियर लीग ब्रिटेन में क्लबों के बीच खेली जाने वाली वह फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसमें विश्व के सबसे चर्चित खिलाड़ी खेलते नज़र आते हैं, लेकिन इस लोकप्रियता का फ़ायदा देश में नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खेप तैयार करने में नहीं हो सका. भारत में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने और उसके कायाकल्प के लिए आईपीएल की तर्ज पर खेली जाने वाली एक नई प्रतियोगिता के आयोजन का रोडमैप तैयार किया जा रहा है. यदि आईएमजी–रिलायंस की चली, तो यह देश में आईपीएल की तर्ज पर आठ शहरों की आठ टीमों के फार्मेट पर खेली जाएगी और इसमें दुनिया भर के कई जाने–माने एवं लोकप्रिय खिलाड़ी भारत की सरज़मीं पर भारतीय खिलाड़ियों के साथ खेलते नज़र आएंगे. वर्तमान में एआईएफएफ (ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन) की आई–लीग प्रतियोगिता में एक टीम में चार विदेशी खिलाड़ियों के खेल सकने का प्रावधान है. नई प्रतियोगिता में इस संख्या में इज़ाफा किया जा सकता है.

पिछले महीने ही एआईएफएफ ने आईएमजी–रिलायंस द्वारा एक नई प्रतियोगिता आयोजित करने के सुझाव को हरी झंडी दिखा दी थी, जिसका आयोजन एक जनवरी से 31 मार्च के बीच किया जाएगा. आईएमआर–रिलायंस फुटबॉल की दुनिया के कुछ बड़े नामों, डेविड बेकहम, थेरी हेनरी, माइकल ओवन एवं राउल गोंजालेज जैसे खिलाड़ियों को नई लीग से जोड़ने के लिए उत्सुक है. आईएमजी–रिलायंस के प्रतिनिधि पहले ही इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी डेविड बेकहम एवं पूर्व स्पेनिश खिलाड़ी राउल से इस नई प्रतियोगिता में भाग लेने के सिलसिले में मुलाकात कर चुके हैं. इस बात का खुलासा ब्रिटेन के एक अख़बार में प्रकाशित ख़बर से हुआ था. वैसे भी, आईएमआर–रिलायंस उन स्टार फुटबॉलरों को टार्गेट बना रहा है, जिन्होंने हाल में संन्यास की घोषणा की है.

इस प्रतियोगिता के प्रारंभ होने के पहले ही आई–लीग में भाग लेने वाली 14 टीमों के संगठन आई–लीग प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब एसोसिएशन (आईपीएफसीए) ने एआईएफएफ के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया है. उसने मुंबई में हुई अपनी एक बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि कोई भी टीम अपने खिलाड़ियों को आईएमजी–रिलायंस की प्रतियोगिता के लिए न तो लोन पर रिलीज करेगी और न ही किसी और तरीके से. आईपीएफसीए के जनरल सेक्रेटरी चिराग तन्ना का कहना है कि अभी तक आई–लीग को प्रमोट करने की एआईएफएफ ने पूरी कोशिश नहीं की है. इसके बाद, यदि यह नई प्रतियोगिता सफल हो जाती है, तो उसका हमसे लगाव और भी कम हो जाएगा. अब तक आई–लीग के अनुभवों के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि दो–तीन महीने की इस लीग से भारतीय फुटबॉल का कोई भला नहीं होगा. यह प्रतियोगिता व्यवसायिक तौर पर भले ही सफल हो जाए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर फुटबॉल का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा. हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि आई–लीग हमारे देश की एक प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता है, इसलिए हमें पहले इसके स्टेटस को बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा. आईएमजी–रिलायंस के एक अधिकारी का कहना है कि आई–लीग क्लबों के इस रुख से ज़्यादा फ़र्क़ नहीं पड़ता है. हम उन पर किसी भी तरह आश्रित नहीं हैं. अगर वे हमारे साथ आते हैं, तो यह सुखद होगा, नहीं तो हमारे पास दूसरे विकल्प भी हैं.

भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने नए टूर्नामेंट की शुरुआत के बारे में पूछे जाने पर कहा, मैं यह ख़बर सुनकर खुश हूं और इस बात का इंतज़ार कर रहा हूं कि यह किस तरह होने जा रहा है. मेरे लिए फुटबॉल का ग्लैमराइज होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन जो प्रतिभाएं हमारे देश में उपलब्ध हैं, उनसे दूर होने की क़ीमत पर नहीं. यह ज़रूरी है कि हम खेल को ग्लैमराइज करें, लेकिन आई–लीग का वजूद बनाए रखें. जो भी निर्णय लिया गया है, वह भारतीय फुटबॉल के लिए अच्छा है. मैं नहीं चाहता कि खिलाड़ियों के लिए ऐसी स्थिति खड़ी हो, जिससे उन्हें दो में से एक विकल्प चुनना पड़े. मुझे लगता है कि आईपीएफसीए और एआईएफएफ एक साथ बैठकर इसका समाधान निकाल लेंगे. दरअसल, भारत में आईपीएल के पदार्पण के बाद खेल के क्षेत्र में सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों तरह के बदलाव देखने को मिले हैं. फिक्सिंग और सट्टेबाजी के मामले में आईपीएल बुरी तरह बदनाम हुआ है. इसके बावजूद देश के अन्य खेल संगठन खेलों के प्रसार के लिए आईपीएल से प्रेरणा लेते दिख रहे हैं. अब इस रास्ते पर भारतीय फुटबॉल भी चलता नज़र आ रहा है. हमारे देश में क्रिकेट और फुटबॉल में बहुत फ़र्क़ है. फुटबॉल के लिए हमारे यहां विश्वस्तरीय मैदानों की बहुत कमी है. कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम को छोड़कर कुछ मैदान ही विश्वस्तरीय मानकों को पूरा कर पाते हैं. ऐसे में, नए मैदानों का निर्माण या पुराने मैदानों का कायाकल्प करना सबसे बड़ी चुनौती होगी. इसके अलावा, फुटबॉल को भारत में क्रिकेट की तरह अखिल भारतीय लोकप्रियता हासिल नहीं है. अभी एआईएफएफ को खिलाड़ियों के ट्रांस्फर और क्लब रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव करने हैं. इसके लिए उसे अपने संविधान में भी कुछ फेरबदल करने पड़ेंगे.

एआईएफएफ चाहता है कि नवगठित आठ क्लब केंद्रीय रूप से रजिस्टर्ड हों, जबकि वर्तमान नियमों के अनुसार, क्लबों का रजिस्ट्रेशन राज्यों के फुटबॉल एसोसिएशन में हो सकता है. आईएमआर–रिलायंस को खिलाड़ी भी आई–लीग से दो महीने के लिए लोन पर लेने होंगे. इसके अलावा, खिलाड़ियों के ट्रांस्फर के नियमों में भी व्यापक बदलाव करने होंगे. वह भी तब, जबकि आईपीएफसीए खिलाड़ियों को देने से मना कर चुका है. इस पूरी प्रक्रिया में खिलाड़ियों के भले और फुटबॉल के प्रसार की बातें कहीं गुम न हो जाएं. भारत में फुटबॉल प्रेमियों की संख्या बेहद कम है. बंगाल, गोवा एवं महाराष्ट्र, इन्हीं तीन राज्यों में फुटबॉल बेहद लोकप्रिय है. बाकी राज्यों में आबादी का पांच प्रतिशत भी फुटबॉल का प्रशंसक नहीं है. ऐसे में, सवाल यह उठता है कि क्या यह नई प्रतियोगिता आईपीएल की तरह कामयाब हो पाएगी? क्या इसके बाद क्रिकेट की तरह फुटबॉल देश के घर–घर में देखा जाने लगेगा? उत्तर भारत में फुटबॉल की जड़ें बेहद कमजोर हैं. ऐसे में, यदि नई लीग भी उन्हीं क्षेत्रों में केंद्रित हो गई, जिनमें वह पहले से ही मज़बूत है, तो आई–लीग और नई लीग में कोई ज़्यादा फ़र्क़ नहीं रह जाएगा और भारतीय फुटबॉल का बेंड इट लाइक आईपीएल का सपना चकनाचूर हो जाएगा. नई लीग की राह में अभी बहुत से रोड़े हैं, उनसे पार पाकर आईपीएल की तर्ज पर एक नई लीग की शुरुआत करना फिलहाल दूर की कौड़ी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया टिकी है. इसलिए हम मानकर चलते हैं कि कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है. ■

अंडर–17 फुटबॉल विश्वकप

मेजबानी के लिए भारत सरकार की हरी झंडी

भारत को फीफा अंडर–17 फुटबॉल विश्वकप की मेजबानी मिल सकती है. इसके लिए भारत सरकार ने हरी झंडी भी दिखा दी है. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) ने देश में 2017 में अंडर–17 विश्वकप के आयोजन की दावेदारी पेश करने के लिए भारत सरकार से गारंटी की मांग की थी. कैबिनेट ने एआईएफएफ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा को टैक्स में छूट, सुरक्षा, खिलाड़ियों की यात्रा, रहने और फॉरेन एक्सचेंज की गारंटी चाहिए थी. मेजबानी के लिए भारत का दावा पहले से ही मजबूत है, क्योंकि उसे फीफा के महासचिव जेरोम वाल्के का समर्थन हासिल है. भारत की पहली बिड जनवरी में खारिज कर दी गई थी, क्योंकि भारत सरकार ने ज़रूरी आश्वासन नहीं दिए थे, लेकिन अब भारत की मेजबानी की राह आसान हो गई है. एआईएफएफ का कहना है कि अगर भारत को विश्वकप की मेजबानी का मौक़ा मिलता है, तो यह भारतीय फुटबॉल के लिए ख़ुशनसीबी होगी. हालांकि क्रिकेट के मुक़ाबले देश में फुटबॉल प्रशंसक कम हैं, लेकिन यदि अंडर–17 विश्वकप की मेजबानी भारत को मिल जाती है, तो इससे देश की जनता में फुटबॉल के प्रति प्रेम और बढ़ेगा. ■

क्या है आईएमजी-रिलायंस

आईएमजी - रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और आईएमजी (विश्व की प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मार्केटिंग एवं मैनेजमेंट कंपनी) का एक साझा उपक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत में खेल एवं मनोरंजन के साधनों का विकास, मार्केटिंग एवं प्रबंधन है. यह उपक्रम देश में विश्वस्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे कि देश की खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने आ सकें. ■

क्रिकेट : एक नज़र

जयवर्धने 11 हज़ारी बने

श्रीलंका के कप्तान महेला जयवर्धने एक दिवसीय क्रिकेट में 11 हज़ार रन बनाने वाले खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो गए हैं. वह ऐसा करने वाले विश्व के आठवें और श्रीलंका के तीसरे खिलाड़ी हैं. उनसे पहले श्रीलंका के सनथ जयसूर्या एवं कुमार संगकारा यह कारनामा कर चुके हैं. जयवर्धने टेस्ट क्रिकेट में भी 10 हज़ार रन बनाने वाले खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हैं. जयवर्धने ने यह मुकाम चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अपने करियर का 394वां एक दिवसीय मैच खेलते हुए हासिल किया. उन्होंने इस मैच में 84 रनों की नाबाद पारी खेली और अपनी टीम को सेमी–फाइनल में पहुंचाया. ■

11 हज़ार रन बनाने वाले बल्लेबाज

खिलाड़ी	मैच	रन	औसत
सचिन तेंदुलकर	463	18426	44.83
रिकी पॉन्टिंग	347	13704	42.03
सनथ जयसूर्या	445	13430	32.36
इंजमाम–उल–हक़	378	11739	39.52
जैक कैलिस	321	11498	45.26
सौरभ गांगुली	311	11363	41.02
कुमार संगकारा	344	11248	39.05

महेला जयवर्धने
रन 11025
मैच: 395 औसत: 33.40

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बॉलीवुड में हेट स्टोरी मेरी पहली फिल्म थी, लेकिन मैं इस बात से काफी खुश हूं कि यहां मैं टाइप कास्ट नहीं हुई हूं.

एकतरफा प्यार संभालना मुश्किल है : रिचा

रिचा एक बिंदास खयालों वाली लड़की जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि वह शादी से पहले के रिलेशनशिप पर विश्वास करती हैं. शायद इसीलिए वह आज तक बॉयफ्रेंड नहीं बना पाईं. लेकिन रिश्ता निभाना वह जानती हैं. आखिर क्या है उनके जीवन की सच्चाई, बता रही हैं इस बातचीत में रिचा ...

प्रियंका तिवारी

feedback@chauthiduniya.com

अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर से पहले अभिनेत्री रिचा चड्ढा को कोई नहीं जानता था. लेकिन इस फिल्म ने उनकी दुनिया ही बदल कर रख दी. गैंग ऑफ वासेपुर और गैंग ऑफ वासेपुर-2 की अपार सफलता के बाद इस फिल्म के सारे कलाकार स्टार बन गए. उन सभी कलाकारों को एक के बाद एक फिल्में मिलने लगीं. फिल्म में मनोज बाजपेई की पत्नी का किरदार निभाया था रिचा ने. वह इन दिनों काफी उत्साहित हैं. इसकी वजह यह है कि इन दिनों लगभग एक दर्जन फिल्मों के ऑफर रिचा के पास हैं. पिछले दिनों उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला की शूटिंग में हिस्सा लिया. हाल ही में उनके रिलेशनशिप के बारे में पत्रकारों के पूछने पर उन्होंने बताया कि वह अभी सिंगल हैं, लेकिन जल्द ही वह किसी रिश्ते में जरूर बंधेंगी.

वह अपने फिल्मी करियर के बारे में कहती हैं, वैसे तो मैंने अनुराग की ओय लॅकी ओय में भी काम किया था, लेकिन फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर की बात ही अलग थी. इसके दोनों पार्ट्स में मैंने काम किया है. खास तौर पर इसके पहले भाग में नगमा खातून का मेरा किरदार बहुत दमदार रहा है. चूंकि इसमें मैंने 16 से 60 साल तक की महिला का रोल किया है, इसलिए भी यह रोल खूब नोटिस किया गया. इसके बाद से ही मुझे बराबर फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं. हालांकि अभी मैंने तय नहीं किया है कि इनमें से कौन सी फिल्म करूंगी. अभी तमंचे, रामलीला जैसी कुछेक फिल्में ही मैं कर रही हूं.

मेरे लिए संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला काफी महत्वपूर्ण है. उम्मीद है कि फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर की तरह यह फिल्म भी मेरे करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी. इसके अलावा, मैं मीरा नायर के साथ भी काम कर रही हूं. मैंने काफी देर तक इसकी स्क्रिप्ट सुनी और पसंद आने पर ही मैंने इस फिल्म की हामी भरी. मैं वही फिल्में करना चाहती हूं, जो एक अभिनेत्री के रूप में मुझे स्थापित करे. मैं इसी तरह से सारी फिल्मों के ऑफर कुबूल करना चाहती हूं. मैं ऐसी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती, जो पांच साल तक बुक रहे. मैं एक के बाद एक चुनींदा फिल्में करना चाहती हूं. मुझे पता है कि मैं एक न्यूकमर हूं, इसलिए एक-एक फिल्म करके ही मेरा आगे बढ़ना ठीक होगा.

वहीं रिलेशनशिप के बारे में चर्चा चलते ही रिचा कहती हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मैं अपने करियर को लेकर इतनी मशगूल रही कि कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं बना पाई, लेकिन अब मैं बॉयफ्रेंड तलाश कर रही हूं. अभी तक मेरा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ करियर की तरफ था, लेकिन अब वह पटरी पर आ चुका है. मुझे अब सिर्फ बेहतर काम करना है. इस पर ध्यान केंद्रित कर अब मैं दोस्तों के साथ एंज्वॉय कर सकती हूं. हां प्यार के बारे में बाते करें, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह शब्द आपके जीवन को बहुत खुशहाल बना देता है, लेकिन मैं इसे किसी पुरुष के प्यार में नहीं ढूंढती. मैं परिवार, दोस्तों और मनुष्य के प्रति अपने प्यार के बारे में कह रही हूं. मैं अपने हर प्यार को अच्छी तरह से संभाल करके रखने की कोशिश करती हूं. पर सच तो यह है कि जब प्यार एकतरफा हो जाता है, तो इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसे में बेहतर यही होता है कि आप बिना किसी तमाशेबाजी के इस रिश्ते को खत्म कर लें. हालांकि अभी तक इसका कोई अनुभव मुझे नहीं हुआ है. निजी तौर पर मैं अपने हर रिश्ते को संभालकर रखना चाहती हूं, बाकी ईश्वर की मर्जी.

गैंग ऑफ वासेपुर की तैयारी के बारे में रिचा कहती हैं कि शूटिंग से पहले एक दुर्घटना में मुझे घुटने में चोट लग गई थी, ऐसे में मैं जिम नहीं जा सकती थी, जबकि इस रोल के लिए मुझे वयस्क और मोटी नजर आना था. इसलिए जिम न जाकर मैंने काफी वर्क आउट किया. अपनी अगली फिल्म के बारे में वह कहती हैं कि इस फिल्म में मैं दिल्ली की लड़की के किरदार में हूं. यह एक ऐसी सख्त लड़की का किरदार है, जो अपराधी परिवार से ताल्लुक रखती है. यह रोल नगमा खातून से बहुत अलग है.

अपने बारे में वह कहती हैं कि असल जिंदगी में मैं सख्त दिमाग की हूं, लेकिन मैं बहुत हंसी-मजाक में जीने वाली लड़की हूं. मैं सभी को आसानी से दोस्त बना लेती हूं. सभी के साथ प्यार से जीना चाहती हूं. हिरोइनों में फिगर को लेकर जिस तरह से पागलपन है, उसके बारे में रिचा कहती हैं कि मैं इस तरह की किसी बात पर यकीन नहीं करती. मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को शेप में रखने के लिए वर्कआउट करती हूं. ■

गैंग ऑफ वासेपुर की तैयारी के बारे में रिचा कहती हैं कि शूटिंग से पहले एक दुर्घटना में मुझे घुटने में चोट लग गई थी, ऐसे में मैं जिम नहीं जा सकती थी, जबकि इस रोल के लिए मुझे वयस्क और मोटी नजर आना था. इसलिए जिम न जाकर मैंने काफी वर्क आउट किया.

प्रेम में असफल सोनम

मैं अकेली हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान में प्रेम करने का गुण होता है. सोनम ने बताया कि मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में प्यार एक ही बार हो सकता है.

भले ही अभिनेत्री सोनम कपूर पर्दे पर रोमांस से भरपूर कई प्रेम कहानियों पर आधारित फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन वास्तविक जिंदगी की बात आने पर वह कहती हैं कि प्रेम संबंधों में वह बहुत ज्यादा भाग्यशाली नहीं रही हैं. ऐसा माना जा रहा था कि वह फिल्म आई हेट लव स्टोरीज के निर्देशक पुनीत मल्होत्रा के साथ डेट कर रही हैं. हालांकि वहीं दूसरी ओर उनका नाम अभिनेता शाहिद कपूर के साथ भी लिया जा रहा था.

गौरतलब है कि शाहिद और सोनम ने फिल्म मौसम में साथ काम किया था. हालांकि सोनम इस बारे में स्वाकार करती हैं, मेरी प्रेम कहानियां असफल रहीं. मैं अकेली हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान में प्रेम करने का गुण होता है. सोनम ने बताया कि मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में प्यार एक ही बार हो सकता है. दरअसल, उनका मानना है कि आप बार-बार प्यार में पड़ सकते हैं. ऐसा करने के लिए हमारे पास प्यार भरा दिल होना चाहिए. वास्तविक जिंदगी में भले ही वह प्रेम में असफल रही हों, लेकिन पर्दे पर उन्होंने कितनी ही प्रेम कहानियों को जीवंत किया है.

उनकी पहली फिल्म सांवरिया और आई हेट लव स्टोरीज, आयशा और मौसम भी ऐसी ही फिल्मों में से हैं. सोनम की आने वाली फिल्म रांझणा भी एक प्रेम कहानी है. फिल्म में सोनम दक्षिण के सुपर स्टार धनुष के साथ दिखाई देंगी. रांझणा में धनुष के साथ ताल-मेल के बारे में वह बताती हैं कि फिल्म में ताल-मेल दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो किरदारों के बीच होता है. ताल-मेल फिल्म में बनाया जाता है. उन्होंने कहा कि फिल्म में अभिनय और दृश्यों के माध्यम से निर्देशक दो किरदारों के बीच ताल-मेल बनाता है. रांझना की अधिकांश शूटिंग वाराणसी में हुई है. हिंदी का अभ्यास न होने के कारण धनुष को संवाद बोलने में परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन सोनम कहती हैं कि जब भावनाओं की बात आती है, तो भाषा रुकावट नहीं होती, क्योंकि आप एक्सप्रेशन से भावनाएं व्यक्त कर सकती हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

दुश्मनी दोस्ती में बदल गई

अभिषेक बच्चन और अभिनेत्री करीना कपूर काफ़ी समय बाद एक बार फिर साथ साथ दिखाई देंगे. कहते हैं, अब उनकी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है. दरअसल, दस साल बाद अब इन दोनों की न केवल सोच बदल गई है, बल्कि उन्हें इस बात का एहसास भी हो गया कि दोस्ती में ही बरकत है, दुश्मनी में नहीं. और इसी का फायदा फिल्मकार उमेश शुक्ला ने उठाया.

उन्होंने अभिषेक बच्चन को लेकर मेरे अपने नाम से एक फिल्म बनाने की बात तुरंत सोची. इस फिल्म की हिरोइन की तलाश काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन अब लगता है कि उमेश की तलाश पूरी हो गई है, क्योंकि उन्हें यह लगा कि अब वह करीना को कैश कर सकते हैं. उमेश ने इस फिल्म के लिए करीना कपूर से बात भी की. कहते हैं कि करीना मेरे अपने में काम करने के लिए तैयार भी हो गई हैं, यानी अभिषेक के साथ वह 10 वर्ष बाद किसी फिल्म में फिर दिखेंगी. गौरतलब है कि वर्ष 2000 में प्रदर्शित फिल्म रिफ्यूजी से अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने बॉलीवुड में एंट्री की थी.

इसके बाद दोनों की जोड़ी वर्ष 2003 में सूरज बड़जात्या की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं में एक साथ नज़र आई थी. इसके बाद अभिषेक और करीना ने एक साथ काम नहीं किया. रिश्तों को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव हो गया. मेरे अपने का निर्माण टी-सीरीज के बैनर तले किया जा रहा है. उमेश शुक्ला निर्देशित इस फिल्म में ऋषि कपूर, अभिषेक के पिता की भूमिका में हैं. फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और लंदन में किए करने की चर्चा है. ■

अच्छा किया, अच्छा फल मिला: पाउली

बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री पाउली डाम एक बार फिर बॉलीवुड में दिख रही हैं. वह फिल्म अंकुर अरोड़ा मर्डर केस में एक वकील की भूमिका में हैं. पाउली खुश हैं कि बॉलीवुड में उन्हें टाइपकास्ट नहीं किया गया है. गौरलतब है कि वर्ष 2012 में प्रदर्शित फिल्म हेट स्टोरी से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली थी. फिल्म में उनका किरदार कॉरपोरेट वर्ल्ड से जूझते एक खोजी पत्रकार का था और उनका किरदार काफी बोल्ड था. फिल्म को कुछ खास सफलता तो नहीं मिली, लेकिन पाउली के काम की काफी सराहना जरूर हुई.

पाउली कहती हैं कि बॉलीवुड में हेट स्टोरी मेरी पहली फिल्म थी, लेकिन मैं इस बात से काफी खुश हूं कि यहां मैं टाइप कास्ट नहीं हुई हूं, बल्कि मुझे यहां फिल्मों में अलग-अलग किरदार निभाने का मौका मिल रहा है. साथ ही वह कहती हैं कि आउटसाइडर को बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. इस इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, बावजूद इसके मैंने अपनी जगह बनाई है, यही मेरे लिए गर्व की बात है. अच्छा किया, इसलिए अच्छा फल मिला. ■

बेस्ट पापा हैं शाहरुख खान

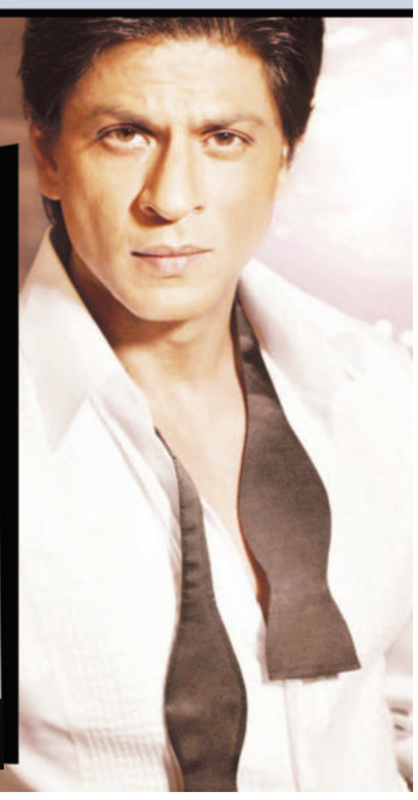

क़यामत से क़यामत तक का वह गीत पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा, आज भी लोग नहीं भूले हैं. इंडस्ट्री में पापा और बेटों की एक लंबी कतार है. पृथ्वीराज कपूर से शुरू हुई यह कतार आज भी बदस्तूर जारी है. कभी अमिताभ बच्चन ने अभिषेक के लिए कहा था कि वह बॉलीवुड के नंबर वन पापा हैं, लेकिन इन दिनों वह कहते हैं कि उनकी जगह शाहरुख खान ने ले ली है. दरअसल, इंडस्ट्री के कुछ स्टार्स रियल लाइफ में भी अच्छे पापा साबित हुए हैं. जैसे जावेद अख्तर, जीतेंद्र और सलीम, यानी सलमान खान के पिता, लेकिन इन दिनों बेस्ट पापा बनने के मामले में शाहरुख ने अमिताभ को भी पीछे छोड़ दिया है. अब आप यह पूछेंगे कि यह कैसे संभव हुआ? दरअसल, हुआ यह कि फादर्स डे के मौके पर एक वेबसाइट ने बॉलीवुड के पापाओं पर एक सर्वे करवाया.

सर्वे में इंडस्ट्री के लोगों से यह पूछा गया कि इन दिनों बॉलीवुड के बेस्ट पापा कौन हैं. सर्वे में एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि शाहरुख खान इन दिनों बेस्ट पापा हैं. गौरतलब है कि उन्हें और उनके बेटे आर्यन को इस सर्वे में बेस्ट पापा और बेटे का खिताब मिला है. ■

चौथी दुनिया
बिहार झारखंड

01 जुलाई-07 जुलाई 2013
www.chauthiduniya.com

सीतामढ़ी

विवाद के दलदल में फंसा नगर परिषद

क्या पार्षद समस्याओं का निदान कर पाएंगे

वाल्मीकि कुमार
feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी नगर परिषद पिछले एक दशक से गुटबाज़ी का केंद्र बन कर रह गया है. दरअसल, नगर परिषद के पास जनता की समस्याओं के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल समय नहीं है और इसी वजह से इस क्षेत्र का विकास लगातार प्रभावित हो रहा है. आखिर क्यों और कैसे? पढ़ें यह रिपोर्ट...

पिछले महीने नगर परिषद कार्यालय में संपन्न बैठक के दौरान जिस प्रकार कुछ वार्ड पार्षदों ने आक्रामक तेवर के साथ अपनी बातें रखीं, निश्चित तौर पर वह परिषद के लिए काफी शर्मनाक रही. शायद यह पहला मौका था, जब कार्यपालक पदाधिकारी एवं अध्यक्ष की मौजूदगी में महिला पार्षद भी अपनी उग्रता पर संयम रखने में विफल रही.

सीतामढ़ी के सौंदर्यीकरण और विकास का दंभ भरने वाला नगर परिषद कार्यालय तक़रीबन एक दशक से विवाद के दल-दल में फंसा है. दरअसल, जात-पात, पार्टी, अर्थतंत्र एवं बाहुबल से चलने वाला परिषद कार्यालय पिछले एक दशक में कोई ऐसा कार्य नहीं कर सका है, जिस पर गर्व किया जा सके, लेकिन गुटबाजी में नगर परिषद का एक मिसाल जरूर दिया जा सकता है. लंबे अर्से बाद नगर परिषद का चुनाव संपन्न हुआ. चुनाव में जीत शकुंतला शर्मा की हुई और उन्हें नगर परिषद अध्यक्ष का कमान सौंपा गया. तब विकास का खाका खींचने की नींव भी डाली गई, लेकिन कुछ माह बाद ही परिषद कार्यालय में राजनीति जोर पकड़ने लगी और ऐसे में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर उठा-पटक शुरू हो गई. बावजूद इसके, सच तो यह है कि श्रीमती शर्मा ने येन-केन प्रकारेण अपना कार्यकाल पूरा कर ही लिया.

अगले चुनाव में जयमुनि देवी की जीत हुई. बतौर अध्यक्ष उन्होंने भी नगर परिषद के बोर्ड की बैठक कर शहर के विकास की कवायद शुरू कर दी. भारी खींचतान के बीच नगर परिषद कार्यालय का चक्का चलता रहा. बाद में अल्पसंख्यक समुदाय से मो. जलालुद्दीन खां ने नगर परिषद अध्यक्ष की कमान संभाली. उन्होंने भी शहर के विकास को लेकर लोगों को तरह-तरह के सपने दिखाए, लेकिन क्षेत्र के समुचित विकास में उन्हें भी पूरी सफलता अंतत: नहीं मिली. इसकी वजह यह है कि परिषद में गहरी पैठ बना चुकी प्रतिशोध की राजनीति ने उन्हें भी जिले से लेकर पटना उच्च न्यायालय तक का सफर करा डाला.

पिछले चुनाव में नगर परिषद के कुल 28 वार्डों में भारी प्रशासनिक सख्ती के बीच चुनाव कराया गया. चुनाव के दौरान कुछ वार्डों में न केवल बवाल मचा, बल्कि पथराव भी हुए. पुलिस को लाठी भी चटकानी पड़ी. जाति व पार्टी की गुटबाजी ने इस बार भी ऐसा जोर पकड़ा कि जनहित का सपना चुनाव के बाद धराशाई होता नजर आने लगा. भारी विरोध के बावजूद नगर परिषद सभापति की कुर्सी पर सुवंश राय को बैठने का मौका मिला, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष पद के दावेदार रहे युगल किशोर प्रसाद को बैठाया गया. उत्साह और विश्वास के माहौल में नवगठित बोर्ड की बैठक हुई और पुन: विकास योजनाओं का पासा फेंका गया. इस बार भी खेमेबाजी की शिकार नगर परिषद का चक्का योजनाओं के कार्यान्वयन से पूर्व ही सशक्त विरोधी गुट के अड़ंगे में फंस गया. नतीजतन, करीब एक साल पूर्व बोर्ड की बैठक में पारित विकास योजनाओं का कार्यान्वयन अब तक अधर में ही लटका हुआ है. ऐसे में अब सभापति राय का विरोधी खेमा विकास को ढाल बना कर अध्यक्ष को सबक सिखाने की तैयारी में लग गया है. पिछले महीने नगर परिषद कार्यालय में संपन्न बैठक के दौरान जिस प्रकार कुछ वार्ड पार्षदों ने आक्रामक तेवर के साथ अपनी बातें रखीं, निश्चित तौर पर वह परिषद के लिए काफी शर्मनाक रही. शायद यह पहला मौका था, जब कार्यपालक पदाधिकारी एवं अध्यक्ष की मौजूदगी में महिला पार्षद भी अपनी उग्रता पर संयम रखने में विफल रही. अध्यक्ष के चुनाव के दौर में प्रबल दावेदार रहे डॉ. अमरनाथ गुप्ता, युगल किशोर प्रसाद व वार्ड पार्षद धनंजय कुमार ने चुनाव बाद भी अपने मिशन को धीमा नहीं पड़ने दिया.

धन-बल व बाहूबल के बूते अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने वाले अध्यक्ष के हर चाल पर दोनों पार्षद पैनी नजर रखते थे. उनकी मानें, तो बोर्ड की बैठक में एक साल पूर्व पारित योजनाओं को अब तक अमलीजामा नहीं पहनाया गया है. शहर के प्रत्येक वार्ड में चलाये जाने वाले चापाकल योजना और सोलर लाईट की आपूर्ति महज कुछ ही वार्डों में उपलब्ध है. नगर परिषद की जमीन पर प्रस्तावित मार्केट कॉम्प्लेक्स व परिषद कार्यालय का प्रशासनिक भवन का निर्माण भी अब तक अधर में लटका हुआ है. चर्चा है कि अध्यक्ष राय का रिमोट शहर के किसी दबंग भाई साहब के हाथ में है. इसी वजह से अध्यक्ष का हर कदम वार्ड पार्षदों की बजाय उनके इशारे पर ही उठता है. चर्चा यह भी है कि विकास का दंभ भरने वाले अध्यक्ष की नजर शहर में नगर परिषद के करोड़ों की जमीन पर टिकी है, जिस पर वे अपने चहेतों का व्यवसायिक झंडा लहराने का सपना देख रहे हैं, लेकिन विरोधी गुट भी इस मामले में हर कदम पर अपनी चाल दिखाने में आगे है.

नगर परिषद की राजनीति पर पैनी नजर रखने वालों की मानें, तो नगर परिषद को नचाने में मदारी की भूमिका निभाने में शहर के ओहदेदार जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं. शहर में साफ-सफाई, रोशनी, पेयजल, जल निकासी समेत अन्य कार्यों के कार्यान्वयन को लेकर जहां एक ओर आम लोग टकटकी लगाए बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर निर्वाचित प्रतिनिधियों को आंतरिक गुटबाजी से ही वक्त नहीं मिल रहा है. ऐसे में शहर के सर्वांगीण विकास व सौंदर्यीकरण का सपना महज सपना बन कर ही रह गया है. फिलहाल, एक ओर अध्यक्ष अपनी बात मनवाने को लेकर संकल्पित हैं, तो वहीं दूसरी ओर विरोधी खेमे का अड़ंगा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. और वैसे भी अब नगर परिषद ने करीब एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है. अगले चार साल का समय शहर के विकास में गुजरता है या गुटबाजी के भंवर जाल में उलझ कर रह जाएगा, फिलहाल यह कहना मुश्किल है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि शहर के आम-अवाम का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है. सड़क पर कचरे का अंबार, वार्ड के गलियों में बह रहे नालों का प्रदूषित पानी और जल जमाव की गंभीर समस्या का निदान नगर परिषद के आंतरिक गुटबाजी के कारण अधर में लटक गया है. हालांकि नगर परिषद की ओर से नाले की सफाई व कचरा हटाने की कवायद भी लगातार जारी है. अब देखना यह है कि अध्यक्ष के विरोध में विकास के सवाल पर गुटबाजी करने वाले गुट के पार्षद लोगों की समस्याओं का निदान कर पाते हैं या नहीं. और अगर कर पाते हैं, तो कितना कर पाते हैं.■

हज़ारों क्विंटल धान घोटालों का सच!

धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास जिले में हजारों क्विंटल धान खुले में इन दिनों सड़ रहा है, लेकिन न तो प्रशासन को इसकी कोई फिक्र है और न ही राज्य खाद्य निगम को. धान की खरीदारी के दौरान हुए करोड़ों रुपये के घपले और मिल मालिकों पर बकाया की बात भी सामने आई है. क्या है घोटालों का सच?

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

रोहतास जिले को धान का कटोरा कहा जाता है. इस जिले में दो लाख हेक्टेयर जमीन पर लगाई गई खरीफ की फसल ने वर्ष 2012-13 में कई रिकॉर्ड बनाए हैं. ये रिकॉर्ड सिर्फ उत्पादन से ही जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि इनमें कुछ घोटालों के पहलू भी छुपे हुए हैं. हैरानी की बात तो यह है कि 2011-12 वित्तीय वर्ष में धान की खरीदारी के दौरान हुए करोड़ों रुपये के घपले को लेकर कराई गई जांच की भी ऐसी-तैसी हो गई. कई मिल मालिकों पर बकाया वसूली के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देते हुए राज्य खाद्य निगम ने अपने कर्तव्य से इतिश्री भी कर ली. दरअसल, इसे देखकर इस वित्तीय वर्ष में मिल मालिकों के हौसले और भी बुलंद हो गए. नये-नये मिल लगाए गए और पुराने मिलों को समाप्त कर दिया गया. हर मिल पर हजारों मिट्रीक टन धान का आवंटन मीलिंग के लिए कराया गया. यही नहीं, खरीदारी में सफेदपोश दबंगों की इतनी चली कि धान गिराए बिना ही कागज पर खानापूर्ति कर लाखों रुपये इधर से उधर कर दिए गए.

जब इन गड़बड़ियों पर पर्दा डालने की बात आई, तो इंतजार शुरू हुई बारिश की. सच तो यह है कि ऐसा नहीं होने पर समय रहते अगर धान का उठाव हो जाता, तो हजारों क्विंटल अनाज तथा करोड़ों रुपये के गबन से जुड़े मामले सामने आ जाते. दरअसल, वर्षा ही एक ऐसा साधन है, जो खुले में रखे गए धान के रखवालों और खरीदारों पर लटक रही कार्रवाई की तलवार को रोक सकती है. बानगी के तौर पर हम रोहतास जिले के करगहर प्रखंड मुख्यालय स्थित धान खरीद केंद्र का उदाहरण पेश कर रहे हैं, जहां इस वर्ष डेढ़ लाख क्विंटल से ज्यादा की धान की खरीदारी हुई. 22 हजार क्विंटल से ज्यादा धान सीधे किसानों से लिए गए. शेष धान पैक्सों ने दिया.

गौरतलब है कि अब तक लगभग 75 हजार क्विंटल धान मिल मालिकों को चावल बनाने के लिए दे दिए गए हैं. शेष 80 हजार क्विंटल धान आज भी खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है. कहा जाता है कि कई राजनीतिक दबंगों ने मानक से काफी घटिया धान सरकारी पहुंच की बदौलत वहां जमा करा दिया था. आश्चर्य की बात तो यह है कि उन लोगों ने बिना धान गिराए ही पैसे का भुगतान करा लिया. हालांकि अभी इस मामले में जांच होनी बाकी है. शायद इसी को देखते हुए करगहर के धान खरीद केंद्र प्रभारी ने वर्षा के कुछ बूंदों के गिरने के साथ ही सात हजार क्विंटल धान बर्बाद हो जाने की घोषणा कर दी. हम यहां यह बताते चलें कि यह घोषणा जून के पहले सप्ताह में की गई थी. तब तक मात्र एक ही दिन हलकी बौछार धान के बोरों पर पड़ी थी. आनन-फानन में धान के दर्जनों बोरों को बगल में बह रहे नालों में गिरा दिया गया. इस मामले की जांच रोहतास प्रशासन भले ही न कराए, लेकिन अभी भी करगहर सहित कई खरीद केंद्रों पर हजारों क्विंटल धान इसी तरह से खुले आसमान के नीचे पड़े पड़े सड़ रहा है, लेकिन सरकार को बिल्कुल फिक्र नहीं. क्यों? ■

मंत्री ने जब गया नगर निगम के सभी विभागों की समीक्षा शुरू की थी, तो भ्रष्टाचार, लापरवाही तथा अनियमितताओं को देख वे भौंचक रह गए थे.

» एक नज़र «

शायरी का सरताज बना युवा शायर

महज बारह साल की उम्र से ही अगर किसी का लगाव साहित्य से हो जाए, तो उम्र के साथ उसकी पहचान बनने में देर नहीं लगती. सीतामढ़ी शहर के मेहसौल चौक निवासी सैयद अलताउद्दीन इसका बेहतर उदाहरण हैं. वर्ष 1996 से ही अपनी आवाज से मंच की तबीयत खुश कर देने वाले युवा शायर के शायरी का कोई जवाब नहीं है. दर्जनों पत्र-पत्रिकाओं में स्थान पाने वाले इस युवक के शायरी का प्रसारण समय-समय पर दरभंगा आकाशवाणी से होता रहता है, जबकि 12 जनवरी, 2013 को इनकी गजलों का प्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केन्द्र से किया जा चुका है. अलताउद्दीन जिले में साहित्य का विकास करना चाहते हैं. साहित्य साधना ही युवा शायर की पहली पसंद है. *– ब्रजेश कुमार*

सड़क का उद्घाटन

सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड के बेलाही मध्य विद्यालय से परतापुर मध्य विद्यालय तक जाने वाली सड़क का उद्घाटन जदयू विधायक गुड्डी देवी ने किया. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 86 लाख 17 हजार रुपये की लागत से सड़क का निर्माण किया गया. सड़क के उद्घाटन के मौके पर विधायक ने राज्य सरकार की सफलता की खूब प्रशंसा की. श्रम श्रेष्ठ साह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जदयू नेता राजेश चौधरी, दशरथ सहनी, सूरत साह, उदय कुमार, राजू वर्मा, संजय सिंह, विपिन सिंह, मुंशी मंडल, चुलहाई महतो व उदल महतो समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे. *– विभा सिन्हा*

जमींदोज हो रहा कोला पुल

शिवहर जिले के हरपुर हरकरवा गांव में स्थित कोला पुल लगभग जमींदोज होकर रह गया है. बागमती नदी के समीप से गुजरने वाली बालसुंद नदी पर निर्मित पुल बाढ़ के दिनों में आवागमन करने वालों के लिए कारगर रहा है, लेकिन सरकारी उदासीनता व प्रशासनिक लापरवाही के कारण अब न तो बालसुंद नदी का अस्तित्व बचा है और न ही पुल आवागमन के लायक रह गया है, जबकि वर्ष 2000 एवं 2008 में नदी को बेहतर बनाने में सरकारी खजाना से लाखों रुपये खर्च किए गए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया जा सका है. पिछले कई सालों से पुल के समीप से गुजरने वाली डायवर्जन लोगों के लिए आवागमन का साधन बना है. *–हेमंत कुमार*

विधायक मद में लूट

चतरा विधानसभा के विधायक जनार्दन पासवान द्वारा कार्यकर्ताओं को दिए गए फंड में भारी लूट का मामला सामने आया है. इटखोरी प्रखंड के नावाडीह पसरी पंचायत के सैधपुर गांव में गोसाल आहर को मरम्मत के नाम पर लगभग तीन लाख रुपये दिए गए हैं. इसी प्रकार गोसाईडीह में विधायक मद से चहारदीवारी के निर्माण में लूट की बात सामने आई है. आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि विधायक मद से काम हुआ है, लेकिन काम कहीं दिखता ही नहीं है. नाम नहीं छापने की शर्त पर राजद के ही कार्यकर्ता बता रहे हैं कि विधायक मद में भारी लूट है. इसकी जांच होनी चाहिए.

मतदाता सूची की समीक्षा

चतरा उपायुक्त इसराज सिंह जिले के सभी प्रखंडों में मतदाता सूची का निरीक्षण सख्ती से कर रहे हैं. जिस प्रखंड में सूची देखी जा रही है, वहां के अधिकारियों को काफी कुछ सुनना भी पड़ रहा है. उपायुक्त इसराज सिंह की सक्रियता से जिले में चल रही सारी योजनाओं में चुस्ती देखने को मिल रही है. मनरेगा में सुस्ती बरतने वाले अधिकारियों को भी खरी-खोटी सुननी पड़ रही है. दूसरी ओर शिक्षा एवं बंद पड़े आंगनबाड़ी केन्द्रों को लेकर भी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है. नये उपायुक्त के कड़े तेवर से चतरा जिले के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है. *– अमरेंद्र प्रताप*

किसानों को मिला अनुदान

किसान भी श्रीविधि के माध्यम से खेती कर उन्नत पैदावार कर सकते हैं. ये बातें सदर प्रखंड में आयोजित उपदान मेला में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने कही. वहीं, कृषि वाटिका के सुरेश सिंह कुशवाहा ने किसानों को जानकारी देते हुए कहा कि श्रीविधि के माध्यम से कम लागत में अधिक धान का पैदावार किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इसके लिए किसानों को निर्धारित समय पर फसल की देखभाल एवं पटवन करने की जरूरत है. ■ *– चौथी दुनिया ब्यूरो*

बच्चों को धूप से बचाएं

ariskon Pharma Pvt.Ltd. डॉ. मनोज

गर्मी के मौसम में बच्चों का बीमार पड़ना आम बात है। खासकर डायरिया से ग्रसित बच्चों की संख्या इन दिनों काफी बढ़ जाती है। सीतामढ़ी के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ मनोज बताते हैं कि जरा सी सावधानी बरत कर बच्चों को डायरिया से बचाया जा सकता है। उनकी राय है कि इस मौसम में बच्चे को मच्छर से बचाना चाहिए और इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों को सीधे धूप नहीं लगे। डॉ मनोज कहते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना चाहिए। वह कहते हैं कि अगर बच्चे को डायरिया हो ही जाए तो उसे तुरंत ओआरएस का घोल देना शुरू कर देना चाहिए। अगर बच्चा ओआरएस घोल पीने में असमर्थ हो तो उसकी मां को अपना दूध उसे पिलाना चाहिए। इस दौरान साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अगर इसके बाद भी नियंत्रण न हो तो तुरंत शिशु रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। मनोज कहते हैं कि इस मौसम में हाई फीवर की शिकायत बच्चों को होती है। ऐसे हालात में तुरंत बुखार को नियंत्रित करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ■ शिवानी

AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
MENSOSET
Her. Tonic with Ashoka 1800 mg
MUSTAL
Levocetirizine Hydrochloride Montelukast Sodium Tab.
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

ज़हरीला पानी पी रहे हैं लोग

पश्चिमी चंपारण के भिखनाठोरी में पीने का शुद्ध पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है. कुछ क्षेत्रों में पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा इतनी अधिक है कि अगर वह पानी गर्भवती महिलाएं पी लें, तो गर्भपात तक हो सकता है. अफसोस!लोग पेयजल के लिए नेपाल जाते हैं या फिर उन्हें पानी खरीदना पड़ता है. क्यों?

अवधेश कुमार शर्मा feedback@chauthiduniya.com

पानी है, लेकिन पी नहीं सकते और कपड़े धो नहीं सकते. यह हाल है पश्चिम चंपारण के विभिन्न इलाकों का. यहां के पानी में आर्सेनिक, क्लोराइड, अमोनिया जैसे खतरनाक तत्व पाए जाते हैं. पानी में लौह तत्व पाया जाता है, जिसे पीने वाले लोग अनेक तरह की बीमारियों से जूझते रहते हैं. हालांकि पानी का स्तर काफी करीब होने से पानी सहज ही उपलब्ध हो जाता है. जिले के अमोलवा रेलवे स्टेशन के निकट स्थित नंदकेश्वर सिंह उच्च विद्यालय के प्रांगण में पतालतोड़ कुंआ है, जहां पूरा साल पानी निकलता रहता है. जानकारी के अनुसार, यहां जो चापाकल लगाए गए हैं, उनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा चापाकल ऐसे हैं, जिनकी गहराई 26 फीट है. दरअसल, यही कारण है कि यहां से पानी पीने योग्य नहीं निकलता, जबकि शुद्ध पानी के लिए 180 फीट से ज्यादा गहराई होना जरूरी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, पानी में आर्सेनिक की मात्रा .01 मिली ग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, लेकिन यहां इसकी मात्रा 5 से 10 मिली ग्राम प्रति लीटर है.

गौरतलब है कि आर्सेनिक मिला पानी पीने के कारण 80 प्रतिशत महिलाओं में गर्भपात की संभावना रहती है. आजादी के पूर्व और आजादी के पश्चात भी भारत के भिखनाठोरी निवासी पेयजल के लिए नेपाल के पानी पर निर्भर रहे हैं. कुछ महीनों से पीएचईडी द्वारा टैंकर भेजकर पेयजल उपलब्ध कराया जाता रहा, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था. भिखनाठोरी के डॉ. आलम, शेषनाथ यादव, दयानंद गुप्ता, मोती पासवान, धनु उरांव और रामानंद सिंह कहते हैं कि सरकार द्वारा पानी मुहैया कराए जाने की घोषणा के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी है. मजे की बात तो यह है कि बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री चंद्रमोहन राय भी यहीं के हैं और उन्होंने भी भतुजला में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की घोषणा की थी, लेकिन यह घोषणा भी हवा-हवाई ही साबित हुई. बहुसंख्यक थारूओं के विकास के लिए थरूहट विकास अभिकरण की स्थापना की गई है. आश्चर्य की बात तो यह है कि थरूहट का भतुजला गांव के लोग पेयजल के लिए नेपाल जाते थे और करीब 85 घर वाले लोग गांव में पीने का पानी उधार लेते थे. पीएचईडी मंत्री ने लाखों रुपये खर्च कर सोलर से चलने वाले वाटर पंप की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ दिन बाद वह भी खराब हो गया. आज भी थारू पहाड़ी नदी के पानी पर आश्रित हैं. दोन क्षेत्र की स्थिति तो और भी विकराल है, जहां पीने का शुद्ध पेयजल भी नसीब नहीं होता! मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थरूहट में जाते जरूर रहते हैं, लेकिन थारूओं के हालात पर ध्यान नहीं देते. थरूहट को पेयजल मुहैया कराने के लिए सरकार को पड़ोसी मुल्क नेपाल से सबक लेनी चाहिए, जिसने दुर्गम स्थानों पर भी लोगों के लिए पाइप लाइन बिछा दिया है. प्रबुद्ध थारू सत्यनारायण दिसवा का कहना है कि सरकार व सरकारी तंत्र वास्तव में थरूहट के विकास के लिए काम करें, तो वह दिन दूर नहीं, जब सारे समाज के लोगों को शुद्ध पेयजल मिलने लगेगा. जगदीश चौधरी बताते हैं कि जो पानी वह पीते हैं, अगर उसे बाल्टी में रख दें, तो वह रातभर में लाल-पीला चिन्ह बना देता है. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सरकारी योजनाओं को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा.■

आर्सेनिक मिला पानी पीने के कारण 80 प्रतिशत महिलाओं में गर्भपात की संभावना रहती है. आजादी के पूर्व और आजादी के पश्चात भी भारत के भिखनाठोरी निवासी पेयजल के लिए नेपाल के पानी पर निर्भर रहे हैं. कुछ महीनों से पीएचईडी द्वारा टैंकर भेजकर पेयजल उपलब्ध कराया जाता रहा, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था.

खाद-बीज की दुकान को तीन जून को 4 करोड़ 29 लाख का भुगतान दिखाया गया है, छोटे-छोटे बैग व पॉलीथिन में रखी गई नकदी पर कई लोगों के नाम लिखे गए हैं.

नई राजनीतिक विकल्प तलाश रही है माकपा

कुमार मनीष feedback@chauthiduniya.com

माकपा ने आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को देखते हुए केन्द्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है. दूसरी तरफ वह खेतिहर मजदूरों और किसानों को एकजुट कर भूमि मुक्ति आंदोलन के लिए निर्णायक संघर्ष की तैयारी में भी जुट गई है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि नई राजनीतिक विकल्प क्यों तलाश रही है माकपा?

बेगूसराय में आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को देखते हुए माकपा किसान आंदोलन के माध्यम से एक नई राजनीतिक विकल्प तलाशने में की कोशिश कर रही है. दरअसल, केंद्र एवं राज्य सरकार की कृषि विरोधी नीति और मनरेगा समेत अन्य योजनाओं में मची लूट जैसे कई मामलों को मुद्दा बना कर वह अपने वोटों को समेटना चाहती है. साथ ही वह खेतिहर मजदूरों और किसानों को एकजुट कर भूमि मुक्ति आंदोलन के लिए निर्णायक संघर्ष की तैयारी भी कर रही है. बताते चलें कि बेगूसराय के सातों विधानसभा सीटों पर वामपंथियों का पिछले दिनों क़ब्ज़ा था. रिफाइनरी, खाद कारखाने और थर्मल में ट्रेड यूनियन की तूती बोलती थी, लेकिन अब बछवाड़ा विधानसभा सीट से भाकपा के अवधेश राय ने अपना गढ़ बनाने में सफलता हासिल कर ली है. कैडर आधारित कार्यकताओं के लिए जानी जाने वाली भाकपा और माकपा समेत अन्य वामपंथी दलों को भी एक सशक्त संगठनात्मक ढाचे व मजबूत आंदोलन की जरूरत है, ताकि एक बार फिर आगामी चुनाव में लाल परचम लहराया जा सके.

बेगूसराय से संपन्न हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की किसान इकाई बिहार राज्य किसान सभा के मौके पर सूबे के विभिन्न जिलों से पहुंचे. 450 किसान प्रतिनिधियों में से 34 किसानों ने संबंधित क्षेत्र में कृषि की स्थिति व संगठन की रिपोर्ट प्रस्तुत की. वहीं प्रतिनिधियों ने दल के अग्रिम पंक्ति के नेताओं द्वारा लाए गए प्रस्तावों के समर्थन में केंद्र व राज्य सरकार को पूंजीवाद का पोषक बताते हुए संघर्ष का ऐलान किया. सम्मेलन के माध्यम से प्रतिनिधियों के विचारार्थ भूमि सुधार, जलप्रबंधन, महिला उत्पीड़न, गन्ना किसानों की समस्याओं एवं बेगूसराय के बंद पड़े खाद कारखाना को खोलने के संबंध में प्रस्ताव लायाङ्ग गया. सम्मेलन के पहले दिन माकपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश करात, अखिल भारतीय किसान महासभा के संयुक्त महामंत्री सह राज्य सम्मेलन के पर्यवेक्षक नंद किशोर शुक्ला, राज्य महामंत्री अवधेश कुमार, उपाध्यक्ष विजय कांत ठाकुर समेत अन्य वक्ताओं ने एनडीए और यूपीए को किसान विरोधी व पूंजीवाद का पोषक दल बताते हुए कहा कि किसान सभा और वामपंथी आंदोलन की मजबूती से ही किसान विरोधी नीति को बदला जा सकता है. करात ने खाद, बीज, बिजली व बढ़ती महंगाई के लिए सरकार की गलत नीति को जिम्मेदार बताया और किसान मजदूरों की एकता की जोरदार वकालत की.

सम्मेलन के पर्यवेक्षक अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त मंत्री नंदकिशोर शुक्ला ने कहा कि सम्मेलन में यह फैसला लिया गया है कि खेती की जमीन से सामंती वर्चस्व मिटाने, किसान और कृषि विरोधी नीति, महिलाओं पर अत्याचार, गरीबों को जमीन से बेदखली के खिलाफ वामदल एक सशक्त लड़ाई के लिए संकल्पित है. इसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी देंगे. आंदोलन के प्रथम चरण में किसान सभा राज्य के भूमिहीनों का सर्वे करेगी और सरकार से भूमिहीनों को जमीन देने की मांग भी करेगी, वहीं दूसरे चरण में सामंतों की सिलिंग से फाजिल जमीन गैर मजरुआ और भू-दान आंदोलन की जमीन की पहचान कर घर विहीनों के बीच वितरित करेगी.■

राष्ट्रीय चेतना कार्यक्रम

बापू के संदेशों को प्रचारित करेंगे

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेशों सत्य, अहिंसा व भाईचारा को जब तक देश की जनता तक नहीं पहुंचाया जाएगा, देश में भ्रष्टाचार का खात्मा व शांति संभव ही नहीं है. राष्ट्रीय चेतना कार्यक्रम के अंतर्गत यह यात्रा बापू की कर्मभूमि चंपारण के घोडासहन प्रखंड के भेलवा कोठी से पोरबंदर होते हुए वरिष्ठ गांधीवादी चिंतक अन्ना हजारे के आदर्श गांव रालेगन सिद्धी पहुंची. इस संदेश यात्रा का उद्देश्य केवल गांधी के संदेशों को प्रचारित करना है, ताकि जनता के बीच फैली बुराइयां समाप्त हो सकें. यात्रा में तीस युवा गांधीवादियों का दल पूरे देश में गया. इस दल ने 2017 में होनेवाली चंपारण सत्याग्रह स्मृति दिवस समारोह की सौवीं वर्षगांठ पर गांधी का चंपारण विषयक परिचर्चा में लोगों को चंपारण में आने के लिए आमंत्रित किया. गांधी के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए यह जत्था युवा गांधीवादी विचारक रामपुकार सिन्हा के नेतृत्व में महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पहुंचा और पुष्प भी अर्पित की. सिन्हा ने अफसोस जताया कि आज का युवा वर्ग उपभोक्तावादी संस्कृति की गिरफ्त में फंसता जा रहा है. और इसीलिए देश और समाज से उसे कोई मतलब ही नहीं है. ऐसे में जरूरत है बापू के विचारों से ओत-प्रोत कर नया विचार पैदा करने की.

राष्ट्रीय चेतना कार्यक्रम के संयोजक धर्मेंद्र विद्रोही ने इस अवसर पर बताया कि सशस्त्र सीमा बल के आरक्षी उपमहानिदेशक प्रदीप कुमार गुप्ता ने इस यात्रा के नेतृत्वकर्ता रामपुकार सिन्हा को तिरंगा थमा कर चंपारण से विदा किया. श्री विद्राही ने बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत-नेपाल सीमा को सुरक्षित करना, युवा पीढ़ी को लक्ष्यवान बनाना, नारी सुरक्षा व सशक्तिकरण, किसानों व नौजवानों की समस्याओं का समाधान एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सत्य एवं अहिंसा की प्रतिमूर्ति बापू के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाना है. 5वीं राष्ट्रीय चेतना कार्यक्रम के अंतर्गत गांधी संदेश यात्रा 07 जून, 2013 से 26 जून, 2013 तक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम प्रभारी रामपुकार सिन्हा और संयोजक धर्मेंद्र विद्रोही के अलावा, तारकेश्वर प्रसाद, प्रो. अला-उद्दीन खिलजी, मो. अनवर अली, श्याम किशोर, सुनील जायसवाल, अवनीश कुमार, रंजीत केशरी, चंदन कुमार, गौरी शंकर ठाकुर, ध्रुव नारायण, प्रसून प्रवीण, अजय कुमार, नूरे जनत, रिंकी कुमारी, एकता कुमारी, जीनत कौशर, रितुराज, नेहा कुमारी, पूजा कुमारी, सुनीता कुमारी, रेखा कुमारी, नीलू कुमारी, सोनी कुमारी, सुनीता कुमारी, निक्की कुमारी, सुलेखा कुमारी, कलावती देवी मौजूद थे. ■

गया नगर निगम

निगम भ्रष्ट विधायक पस्त जनता त्रस्त

53 वार्डों वाले गया नगर निगम का हर पार्षद इन दिनों गुटबाजी में व्यस्त है. तत्कालीन नगर विकास मंत्री ने खस्ताहाल निगम की कमान खुद ही संभाल ली थी, लेकिन न तो अब वह मंत्री हैं और न ही उनसे किसी कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है. क्या है पर्दे के पीछे की सच्चाई?

सुनील सौरभ feedback@chauthiduniya.com

गया नगर निगम हमेशा से ही अनियमितता, घोटालों और पार्षदों के आपसी झगड़े के लिए सुर्खियों में रहा है. अब शहर की सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है, इसलिए लोग परेशान हैं. मेयर और डिप्टी मेयर के बीच झगड़े तथा स्वार्थ में लिप्त पार्षदों के कार्य भी शहर के विकास को बाधित कर रहा है. 53 वार्डों वाले गया नगर निगम का हर पार्षद अपने-अपने लाभ के हिसाब से गुटबाजी करने में व्यस्त है. सूबे के तत्कालीन नगर विकास मंत्री और गया के विधायक डॉ. प्रेम कुमार भी गया नगर निगम के कार्यों से असंतुष्ट थे. हद तो तब हो गई, जब गया नगर निगम के अधिकारियों ने उस समय के नगर विकास मंत्री के निर्देशों की अवहेलना शुरू कर दी थी. गया नगर निगम की मेयर विभा देवी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हो चुका है. शहर की बिगड़ती हालत को देखते हुए नगर विकास मंत्री गया नगर निगम की कमान खुद ही संभाल ली थी.

मंत्री ने जब गया नगर निगम के सभी विभागों की समीक्षा शुरू की थी, तो भ्रष्टाचार, लापरवाही तथा अनियमितताओं को देख वे भौंचक रह गए थे. आखिरकार विकास मंत्री को भी यह कहना पड़ा था कि गया नगर निगम के सभी विभागों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है. उन्होंने कहा कि निगम में दुकानों के आवंटन से संबंधित दस्तावेज गायब होने के साथ-साथ अनेक ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनसे निगम की राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है. मंत्री ने स्वीकार किया था कि निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण गया शहर की स्थिति बहुत खराब है. 1 जून, 2013 को मंत्री जी ने गया नगर निगम की समीक्षा बैठक बुलाई थी. मंत्री ने निगम की मार्केट शाखा से दुकानों के आवंटन संबंधी दस्तावेज गायब पाए थे. इस मामले में उन्होंने 48 घंटे के अंदर संबंधित कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन कई सप्ताह बीत जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकी. मंत्री ने इस संबंध में कहा कि उनके निर्देश का पालन नहीं किए जाने के मामले में पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गया नगर निगम की खराब आंतरिक व्यवस्था से बौखलाये नगर विकास मंत्री ने खुलकर कहा था कि निगम के नाक के नीचे गलत कार्य हो रहा है और अधिकारी कुछ नहीं करते. इससे साफ पता चलता है कि अधिकारियों का इसमें निजी स्वार्थ है.

केदारनाथ मार्केट के एक क्षेत्र विशेष का ही टेंडर होता है, लेकिन अवैध रूप से मार्केट के बाहर भी दुकानें लगाई जाती हैं. कभी विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मशहूर जवाहर टाउन हॉल आज अतिक्रमण का शिकार हो गया है. टाउन हॉल के दोनों ओर सब्जी और दुकानों का कचरा जमा रहता है और अवैध दुकानें भी लगी रहती हैं. निगम कार्यालय के सामने ही कचरे का अंबार भी लगा रहता है. हैरानी की बात तो यह है कि निगम के अधिकारियों की लापरवाही से माड़नपुर और करसिल्ली में करोड़ो रुपयों की योजना की शुरुआत नहीं हो पाई है. नगर विकास मंत्री ने अपने ही क्षेत्र के नगर निगम की खराब स्थिति और गया के लोगों को नागरिक सुविधाएं नहीं मिल पाने के कारण सख्त रुख अख्तियार कर लिया था. आश्चर्य की बात तो यह है कि गया नगर निगम के उन पदाधिकारियों पर मंत्री के कड़े रुख का भी कोई खास असर नहीं पड़ा था. मंत्री ने गया नगर निगम के नगर आयुक्त को शहर के तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने तथा अतिक्रमण करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश पहले ही दे दिया था. बड़ा सवाल यह है कि पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने जब सख्त आदेश दिया था, तो उस समय भी अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंगी थी. अब तो वह मंत्री भी नहीं रहे, तो जरा सोचिए कि नगर निगम का क्या हाल होगा. सवाल यह भी उठता है कि जब अधिकारी काम ही नहीं करना चाहेगा, तो कोई भी मंत्री आए, क्या फर्क पड़ता है.■

डॉ. प्रेम कुमार

भ्रष्टाचार का अड्डा बना जिला कृषि विभाग

मोतिहारी जिला कृषि विभाग इन दिनों भ्रष्टाचार का मुख्य केन्द्र बना हुआ है. विभाग के अधिकारी व कर्मचारी खुलेआम सरकार के नियमों व विभागीय आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और किसानों का जमकर आर्थिक दोहन कर रहे हैं.

इंतेजारूल हक feedback@chauthiduniya.com

जिला कृषि विभाग खाद व बीज की तस्करी रोकने तथा डीजल अनुदान की राशि का लाभ किसानों तक पहुंचाने में नाकाम है. लोगों का कहना है कि जिला कृषि विभाग इन दिनों भ्रष्टाचार का मुख्य केन्द्र बना हुआ है. यहां अधिकारी व कर्मचारी खुलेआम सरकार के नियमों व विभागीय आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और किसानों का जमकर आर्थिक दोहन कर रहे हैं. डीजल अनुदान की राशि के वितरण का मामला हो, या फिर सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही अन्य योजनाओं का, सभी जगह स्थिति एक जैसी ही है. योजनाओं पर माफियाओं व दलालों का दबदबा है. हाल ही में पटना की आर्थिक अपराध टीम द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी धर्मवीर पांडेय के कार्यालय व उनके आवास पर छापेमारी की गई, जहां से चेक बुक के साथ-साथ कमिशन के रुपये व अन्य कागजात बरामद हुए.

खाद-बीज की दुकान को तीन जून को 4 करोड़ 29 लाख का भुगतान दिखाया गया है, छोटे-छोटे बैग व पॉलीथिन में रखी गई नकदी पर कई लोगों के नाम लिखे गए हैं. 24 मई को जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के नाम से 10 करोड़ से ज्यादा 17 चेकों पर हस्ताक्षर किया गया है. 3 जून को मोतिहारी स्टेशन रोड स्थित तरुण खाद एवं बीज भंडार को 4 करोड़ 29 लाख रुपये का 17 चेकों से भुगतान किया गया है व कार्यालय के नाजिर अगनु चौधरी के घर से बरामद नगद राशि तथा उस राशि पर लिखे गए एक प्रतिशत व दो प्रतिशत आदि भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए काफी हैं.

जांच टीम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि तरुण खाद एवं बीज भंडार पर विभागीय अधिकारी काफी मेहरबान हैं और उसे लाभ पहुंचाने के लिए सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं. एक ही दिन इतनी बड़ी राशि 17 चेकों के माध्यम से भुगतान करने की मंशा से यह भी साफ हो जाता है कि यहां भ्रष्टाचार का खेल काफी पुराना है. हैरानी की बात मो यह है कि यहां के अधिकारियों व कर्मचारियों को न तो निगरानी का डर है और न ही सुशासन की खौफ! इसके अलावा, किसानों के लिए आवंटित डीजल अनुदान की राशि में घपले भी अधिकारियों की काली करतूत को उजागर करती है. जानकारी के अनुसार, खरीफ 2012 में डीजल अनुदान के मद में जिले को 1000 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, जिनमें मात्र 38695 रुपये किसानों के बीच बांटे गए और 613 लाख रुपया लौटाया गया, जबकि एक लाख 48 हजार 2 सौ 48 किसानों ने आवेदन दिए थे. अनुदान की राशि के लिए किसान भटकते रहे, लेकिन अनुदान की राशि उन्हें अंतत: नहीं मिली. जानकार बताते हैं कि विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों का हाल यह है कि बगैर कमिशन के कोई काम करना ही नहीं चाहता. यही स्थिति खाद की है. भारत-नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण खाद की कालाबाजारी व तस्करी की शिकायतें हमेशा अधिकारियों के पास पहुंचती हैं, लेकिन जांच के नाम पर इस मामले को उलझा दिया जाता है. खाद व बीज के लिए किसान प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्र में सड़क भी जाम करते हैं, फिर भी ठोस कार्रवाई नही होती. जानकार बताते हैं कि भारत-नेपाल सीमा से सटे छौड़ादानव, रक्सौल, घोड़ासहन, आदापुर, बनकटवा आदि प्रखंडों में सबसे अधिक खाद की दुकानें स्थापित की गई हैं. यहां से कालाबाजारी व तस्करी में काफी सहूलियत होती है. एक आकड़े के मुताबिक, 90 प्रतिशत किसानों को महंगे दामों पर खाद खरीदनी पड़ती है. खाद के लिए हंगामा व प्रदर्शन भी होता है, लेकिन कालाबाजारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती. कुल मिलाकर जिला कृषि विभाग भ्रष्टाचार का मुख्य अड्डा बना हुआ है. राजद जिलाध्यक्ष बच्चा प्रसाद यादव, राजद के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पु दुबे, महिला सेल की जिलाध्यक्ष नसीमा खातुन, नरकटिया विद्यानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी डा. शमीम अहमद, मुन्नी लाल यादव, मुख्तार आलम युवा जिलाध्यक्ष एहतेशाम हुसैन सरकार पर किसानों को ठगने का आरोप लगाते हैं. वे कहते हैं कि सरकार की दोहरी नीति के कारण चंपारण के किसान हाशिये पर हैं. इस बीच जिला कृषि पदाधिकारी धर्मवीर पाडेय से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका. ■

संक्षिप्त ख़बरें

फुड पार्क का निर्माण शुरू

जिले के मानसी प्रखंड अंतर्गत खुटिया पंचायत में प्रिस्टाइन कंपनी के द्वारा मेगा फुड पार्क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है. दूसरी ओर, दर्जनों किसान निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने से पीछे ही नहीं हट रहे हैं. मानसी विकास समिति के अध्यक्ष निर्मल शर्मा ने कहा कि फुड पार्क निर्माण से स्थानीय लोग एवं व्यवसायी खुश हैं, क्योंकि इससे हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा.

डोम समुदाय का उग्र प्रदर्शन

बहिष्कृत हितकारी संगठन के द्वारा मानसी प्रखंड कार्यालय के समक्ष डोम समुदाय के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष पप्पु डोम ने की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महादलित वर्ग के विकास के प्रति सरकार लापरवाह है, जिसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार एवं अफसरशाही है. सरकार उन लोगों के लिए तरह-तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन योजनाओं का लाभ महादलित वर्ग को नहीं मिल रहा है. उन्होंने चार सूत्री मांग की एक कॉपी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपी. *– कुमार धनंजय निराला*

समस्तीपुर बंद सफल

एनडीए गठबंधन टूटने के बाद जदयू के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर घंटों जाम किया. शहर से गांव तक बंद का असर देखने को मिला. भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाजार को भी बंद करा दिया और नरेन्द्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए. भाजपा नेता मनोज गुप्ता, रामसुमरन सिंह, शशिकांत आनंद, जिला अध्यक्ष सुशील कुमार चौधरी, चन्द्रकांत चौधरी, प्रो. मिनी पांडेय, विनोद कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बंद को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार में थोड़ी भी नैतिकता नहीं बची है. उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में जनता नीतीश की गद्दारी एवं धोखाधड़ी का हिसाब जरूर लेगी. बंद का असर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर सहित अन्य जिलों में भी देखा गया. *– प्रमोद प्रभाकर*

विचार गोष्ठी का आयोजन

सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था क्रिएशंस के तत्वावधान में आधुनिक बिहार के निर्माता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा की स्मृति में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया. सेमिनार का आयोजन बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने किया था. समारोह की अध्यक्षता श्रीमती नीलिमा श्रीवास्तव ने की. इस अवसर पर पूर्व विधायक ललन पासवान ने कहा कि जब तक बिहार का अस्तित्व रहेगा, सिन्हा साहब प्रासंगिक रहेंगे. इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, सिन्हा लाईब्रेरी के पूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ. राम शोभित प्रसाद सिंह, बिहार राज्य गीत के रचयिता कवि सत्यनारायण, बिहार राज्य प्रार्थना के रचयिता एन.आर.चिश्ती, टी.वी. पत्रकार कुमार अभिरंजन सहित अक्षत, अर्पित अदविक राज, अनामिका श्रीवास्तव, एकाग्र, लक्ष्य, मोहनीश मोहन, मोहित मोहन एवं मालविका शशि उपस्थित थे. ■ *– शिवानी*

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

» एक नज़र «

आंगनबाड़ी में शीघ्र बहाली

खगड़िया जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों के रिक्त पड़े सभी सीटों पर जल्द ही बहाली की जाएगी. पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी सैयद परवेज आलम ने यह बात कही. डीएम ने आईसीडीएस के बारे मेंबताया कि 1407 आंगनबाड़ी केन्द्र जिले में संचालित हैं, जबकि 1481 केन्द्रों की स्वीकृति है. उन्होंने बताया कि 39 उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटा गया है और बिजली चोरी के मामले में 42 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें से 5 लाख 45 हजार रुपये की वसूली की गई है.

मासिक परीक्षा आयोजित

मासिक परीक्षा प्रणाली से सभी वर्गों के बच्चों के रैंक में सुधार हो रहा है. ये बातें सीताराम मेमोरियल उच्च विद्यालय, सन्हौली, खगड़िया के प्रधानाध्यापिका सुकांति कुमारी ने बताई. श्री कुमारी ने बताया कि प्रति माह आयोजित मासिक परीक्षा से बच्चों की योग्यता का पता चलता है और बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति भी होती है. उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रणाली बच्चों के भविष्य की सफलता की कुंजी है. ऐसी परीक्षा प्रणाली छात्रों को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाती है.

आभा ने मारी बाजी

कहते हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है आभा कुमारी ने. आभा दीप नारायण राम कृष्ण उच्च विद्यालय, बसुआ-कोयला, खगड़िया की छात्रा है. अभावों में पढ़ी इस मेहनती छात्रा ने मैट्रिक की परीक्षा में 407 अंक ले आई. अपने माता-पिता के साथ-साथ उसने जिले का नाम भी रोशन किया. आभा कुमारी ने बताया कि उसके माता गायत्री एवं पिता अर्जुन शर्मा ने लकड़ी का एक छोटा कारोबार करके उसे पढ़ाया है. आभा ने अपनी इस सफलता का श्रेय विद्यालय के शिक्षक को दिया. आभा का सपना आईएएस बनकर समाज के निचले स्तर के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का है. *– नन्दकिशोर शर्मा*

गिरफ्तारी के विरोध में उग्र प्रदर्शन

सामाजिक कार्यकर्ता बाबूलाल शौर्य के समर्थकों ने गिरफ्तारी के विरोध में खगड़िया समाहरणालय के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया. लगभग चार-पांच घंटे सड़क जाम के बाद एसपी शिव कुमार झा ने यह आश्वासन दिया कि अगर जांच में डीएम सैयद परवेज आलम का बॉडीगार्ड दोषी पाया गया, तो उसे निलंबित कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि बाबूलाल शौर्य परबत्ता प्रखंड के लोगों की जमीन संबंधी समस्या को लेकर जिला पदाधिकारी को आवेदन देने गए थे. उसी दौरान बाबूलाल शौर्य एवं डीएम के अंगरक्षक के बीच विवाद हो गया. इस विवाद में बाबूलाल को अंगरक्षक ने थप्पर मार दिया. इसलिए विवाद और बढ़ गया. इसके बाद बाबूलाल को बिना शर्त रिहा करने के लिए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया.

भाजपा का मशाल जुलूस

भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों एवं जिला मुख्यालय में जदयू द्वारा किए गए विश्वासघात के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया. यह जुलूस जिलाध्यक्ष रामानुज चौधरी की अध्यक्षता में निकाला गया. श्री चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा बिहार की साढ़े दस करोड़ जनता का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि जदयू ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए जनता के अपमान का बदला लेने के लिए सड़क से संसद तक लगातार विरोध करेगी भाजपा. नीतीश सरकार में अफसरशाही एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला है. दूसरी तरफ, राज्यव्यापी बिहार बंद को लेकर मुख्यालय के दुकानों को बंद कराने के साथ-साथ विद्यालय एवं सड़क यातायात को भी बाधित किया गया. इस अवसर पर विधान पार्षद रजनीश कुमार, पूर्व विधायक चन्द्रमुखी देवी, भाजपा प्रदेश मंत्री नीलम साहनी, पूर्व जिलाध्यक्ष कंचन पटेल, शशिभूषण प्रसाद, राजकुमार विद्यार्थी, जिलामहामंत्री शत्रुधन भगत, रविश चन्द्र, करुणेश मिश्र, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुमिता देवी राय, अश्विनी कुमार सिंह, कुंवर सिंह, खगड़िया प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार चौधरी, नगर अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार, जिला प्रवक्ता राजेश सिंह, विष्णु बजाज, रामाकांत रजक, नवीन सिह, आनंदी सिंह, अर्जुन शर्मा, सुमन सिंह, रोशन भारती, रविराज, दुर्गेश चौधरी, मधुकर सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे.■ *– नन्दकिशोर शर्मा*

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

बालमुकुन्द
डायमंड टी.एम.टी.
IS:1786
इसमें है दम
यही है नंबर 1
भारत में पहली बार Q & Q कर रहे बंडल के साथ
Website: www.balmukundtmt.com
Email: bconcast@yahoo.com

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE
1 YEAR GUARANTY
WINNER OF NATIONAL AWARD
Contact : 9386595926, 9334115955

मुहल्ले के विकास से उत्साहित स्थानीय लोगों ने विश्वनाथ नगर विकास कार्यान्वयन समिति नाम से एक संस्था गठित कर मुहल्ले के विकास की मॉनिटरिंग का जिम्मा लिया था.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बेगूसराय ▸▸ 25 वर्ष बाद भी शिलान्यास नहीं हो पाया

वादे हैं वादों का क्या

बेगूसराय के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा करने वाली नगर निगम यहां दिनेश्वरी बाल उद्यान का उद्घाटन आज तक नहीं करा पाई. क्यों?

कुमार मनीष
feedback@chauthiduniya.com

बेगूसराय शहर की सूरत बदलने के लिए नगर निगम ने करोड़ों रुपये ख़र्च करने की घोषणा की है. कार्य होते हुए भी दिख रहा है, लेकिन शिलान्यास के ढाई दशक बाद भी विश्वनाथ नगर के दिनेश्वरी बाल उद्यान का आज भी उद्घाटन नहीं हो पाया है. इसे ज़िला प्रशासन और नगर निगम की संवादहीनता कहें या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता! दरअसल, दशकों से इस बाल उद्यान को विकसित करने या इसके सौंदर्यीकरण की सुध किसी ने नहीं ली. बीते 25 वर्षों में यहां काफ़ी कुछ बदल गया है, लेकिन दिनेश्वरी बाल उद्यान की तस्वीर आज भी नहीं बदली.

हरख कोठी के स्व. विश्वनाथ सिंह शर्मा की पत्नी स्व. दिनेश्वरी शर्मा ने 80 के दशक में हुए शहरीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के दौरान ही अपनी ज़मीन को व्यवस्थित रूप देकर एक स्तरीय मुहल्ला बसाने का सपना देखा था. मुहल्ले में पार्क और स्कूल की ज़मीन देकर लोगों को यहां बसने के लिए आकर्षित भी किया गया. अधिकांश नौकरीपेशा लोग धीरे-धीरे यहां बसने लगे. वर्तमान में विश्वनाथ नगर शहर का सर्वाधिक पॉश एरिया माना जाता है. दिवंगत श्रीमती शर्मा के प्रयास से 20 मार्च, 1988 को तत्कालीन डीएम एसएम शहाबुद्दीन के करकमलों से दिनेश्वरी बाल उद्यान का शिलान्यास कार्यक्रम एवं मुहल्ले का नामकरण समारोह आयोजित किया गया. तत्कालीन विधायक भोला सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुए शिलान्यास समारोह में अतिथियों एवं वक्ताओं ने पार्क की ज़रूरत और इसकी उपयोगिता की पुरजोर वकालत करते हुए, इसके निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के समर्थन में न केवल कशीदे पढ़े थे, बल्कि हरसंभव सहयोग व प्रयास का आश्वासन भी मुहल्लेवासियों को दिया था. मुहल्ले के विकास से उत्साहित स्थानीय लोगों ने विश्वनाथ नगर विकास कार्यान्वयन समिति नाम से एक संस्था गठित कर मुहल्ले के विकास की मॉनिटरिंग का जिम्मा लिया था. समिति द्वारा मुहल्ले में सुरक्षा गार्ड की तैनाती, स्ट्रीट लाइट, नव वर्ष मिलन समारोह एवं दीवाली के मौक़े पर सामूहिक आतिशबाज़ी जैसे सामाजिक आयोजन यहां किया जाता रहा है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तत्कालीन विधायक भोला सिंह बाल उद्यान के शिलान्यास समय पर करने की बजाए लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में पटना व दिल्ली के सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं. पार्क की चारों तरफ सड़क निर्माण को छोड़ दें, तो इस बाल उद्यान के लिए उनका कोई प्रयास मुहल्लेवासियों को नहीं दिखता.

यहां के स्थानीय निवासी अपने पते में इस पार्क का जिक्र तो करते हैं, लेकिन हक़ीक़त में पार्क के नाम पर चौतरफा सड़क से घिरे मैदान के सिवा कुछ भी नहीं है. यह मैदान भी गंदगी और जंगलों से पटा है. स्थानीय लोग इस मैदान का उपयोग वैवाहिक आयोजनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों, गिट्टी-बालू रखने और कूड़ा फेकने के लिए करते हैं. मुहल्ले में नाले की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण नाले का पानी भी पार्क में खुलेआम बहाया जा रहा है. समय-समय पर स्व. दिनेश्वरी शर्मा परिवार इस पार्क की ज़मीन पर अपना मालिकाना हक़ बता कर मुहल्लेवासियों के माथे पर शिकन पैदा करते रहते हैं. इन 25 वर्षों में हरख कोठी परिवार से जुड़े लोग स्थानीय वार्ड पार्षद व नगर परिषद के मुख्य पार्षद की कुर्सी को भी शोभायमान करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी पार्क के विकास के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई.

विश्वनाथ नगर विकास क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष डॉ. सुरेश चंद्र शर्मा बताते हैं कि शिलान्यास समारोह के मौक़े पर ही 40 फीट गहरे पार्क की ज़मीन में मिट्टी भराई की घोषणा की गई. 1 लाख, 65 हज़ार की लागत से नगर परिषद के कचरे से इस गड्ढे की भराई का कार्य किया गया. 1990 के आसपास ज़िला योजना से पार्क के चारों ओर ईंट-खरंजा की सड़क का निर्माण और बाद में इसे पक्कीकरण किया गया. 90 के दशक में ही ज़िला प्रशासन ने नवोदय विद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 80 हज़ार का चेक निर्गत किया था, जिसका कोई अता-पता मुहल्लेवासियों को नहीं है. समिति के ही गणेश सिंह और जनार्दन सिंह कहते हैं कि बाल उद्यान के निर्माण के लिए स्थानीय सहयोग के तहत कुछ राशि भी इकट्ठी की गई थी, लेकिन निर्माण या सौंदर्यीकरण सपना ही रह गया है. समिति के कोषाध्यक्ष रमाकांत सिंह कहते हैं कि समिति में सक्रिय सभी लोग अब उम्र के अंतिम पड़ाव के क़रीब पहुंच चुके हैं और स्थानीय युवाओं की शिथिलता के कारण समिति की गतिविधि भी अब शिथिल हो गई है. अन्यथा पार्क के निर्माण के लिए करोड़ों की नहीं, बल्कि कुछ लाख रुपये और इच्छाशक्ति की जरूरत है. वर्तमान समय में मुहल्लेवासी दिनेश्वरी बाल उद्यान के सौंदर्यीकरण के लिए ज़िला प्रशासन एवं निगम की तरफ टकटकी लगाए एक ऐसी विकास योजना का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे कि मुहल्ले के छोटे बच्चों को खेलने, मनोरंजन का एक बेहतर स्थान और सही माहौल मिल सके.■

बिहार राज्य में पहली बार B.Sc. नर्सिंग का एकमात्र संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION AND RESEARCH
I.D.H. Colony East of Nalanda Medical College, Gulzarbagh, Patna - 7
Ph :0612-2638057,9006181691, 9234713028, Fax : 0612-2638057, Email: kalyansevasansthan@gmail.com
SWAMI VIVEKANAND PARA MEDICAL COLLEGE
Madhav villa, Simultalla, Jamui (Bihar) Ph 06349-256201,
Both Institution are Recognised by Govt. of Bihar, I.N.C., NIOS (MHRD) Govt. of India
Aryabhatta Knowledge University, Patna Magadh University Bodh Gaya (Pharmacy Council of India)
An ISO 9001 : 2000 certified Institute, Website : www.kalyansevasansthan.org
ADMISSION IS GOING ON SESSION- 2013-14
DIPLOMA COURSES :
Physiotherapy
Medical Lab. Technician
Occupational Therapy
X-Ray Technician
O.T. Assistant
E.C.G. Technician
Sanitary Inspector
Ophthalmic Assist.
Orthotic & Prosthetic
Pharmacy (D.Pharm)
DEGREE COURSES :
Physiotherapy
Medical Lab. Technician
Occupational Therapy
X-Ray & Immaging Technician
Abridge Course Also Available
NURSING COURSES :
B.Sc. (Nursing)
A.N.M. (Nursing)
G.N.M. (Nursing)
पूरे देश एवं विदेश में सरकारी नौकरी हेतु मान्य
CERTIFICATE COURSES
Medical Dresser
Community Health
Limited Seats
Dr. U.P. Gupta
Director - in Chief , NIHER, Patna
HOSTEL FACILITIES ALSO AVAILABLE

इतिहास के जिज्ञासु, विद्यार्थी एवं शोधार्थी के लिए
परम आवश्यक पुस्तक : भारतीय इतिहास का सच
गौरवशाली भारत प्रकाशन - पाटलिपुत्र की प्रस्तुति
भारतीय इतिहास का सच - ऋतेश कुमार गुप्त
पृष्ठ - 312 (रंगीन) मूल्य रू. 300/-
Website : www.gloriousindiapublication.com, Author's Contact No. : 8051565675
Join Author on & : kumargupt123@gmail.com
Author's Blog : gloriousindia123.blogspot.com, Facebook page of the book : Bhartiya itihas ka Sach

लक्ष्य + परिश्रम + मार्गदर्शन = सफलता
लक्ष्य
साईंस एण्ड कॉमर्स कोचिंग
For : XI, XII (B.S.E.B & C.B.S.E), Engg. & Med.
हमारे गौरव
पढ़ाई की बदौलत
75 % से अधिक अंक
प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रायें

कॉलेज में नामांकन की सुविधा
स्थानः- पटेल मैदान से पश्चिम, निकट गर्ल्स हाई स्कूल, काशीपुर, समस्तीपुर
06274-225029
visit us - www.lakshyacoaching.in